

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023-24 के दौरान लंबे भू-राजनीतिक तनावों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए समुत्थानशीलता प्रदर्शित की है। टिकाऊ मुद्रास्फीति-रोधी मौद्रिक नीति रुख और सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों के संयोजन के परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति काफी हद तक सहन सीमा के भीतर बनी रही। मौद्रिक और ऋण स्थितियां मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित हुईं। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रतिबद्धता के भीतर पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया। वर्ष के दौरान बाह्य क्षेत्र की धारणीयता संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ जिससे वैश्विक समष्टि वित्तीय आघातों के प्रतिकूल प्रभाव- विस्तार से अर्थव्यवस्था का बचाव हुआ।

II.1.1 प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख, भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियों के जटिल रहने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में समुत्थानशील रही। यूएस और प्रमुख उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडी) में उछाल के प्रभाव से वैश्विक जीडीपी वर्ष 2023 में 3.2 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 3.5 प्रतिशत¹) बढ़ी। मौद्रिक सख्ती और आपूर्ति शृंखलाओं की बहाली के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 में घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 8.7 प्रतिशत थी। राजकोषीय नीति में महामारी के कारण लाई गई नरमी, धीमी संवृद्धि और उच्च ब्याज दर के माहौल में वैश्विक लोक ऋण-जीडीपी अनुपात पर बढ़ने का दबाव पड़ा। वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा, जिसका 2022 में 3.0 प्रतिशत विस्तार हुआ था, 2023 में 1.2 प्रतिशत तक संकुचित हुई², ऐसा बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों और वस्तुओं की मांग की बजाय सेवाओं की ओर परिवर्तित होने के कारण था। केंद्रीय बैंकों द्वारा व्यक्त किए गए दीर्घावधि उच्च रुख के बावजूद बाजार सहभागियों के बीच मौद्रिक नीति की भावी दिशा संबंधी अनिश्चित धारणाओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों ने अस्थिरता को दर्शाया। सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में 2023-24 की

पहली छमाही में वृद्धि हुई और दूसरी छमाही में उसमें बड़े दो-तरफा परिवर्तन हुए। यूएस डॉलर वर्ष के दौरान दृढ़ रहा जिससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमडी) मुद्राओं पर मूल्यहास होने का दबाव पड़ा।

II.1.2 वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 के दौरान समुत्थानशीलता प्रदर्शित की। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि³, जो 2022-23 में 7.0 प्रतिशत थी, बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई, जिसे मजबूत निश्चित निवेश का समर्थन मिला। आपूर्ति पक्ष की बात करें तो आर्थिक गतिविधियों को विनिर्माण क्षेत्र में हुए लाभप्रदता सुधार से सहायता मिली जिसे निविष्टि लागत में कमी आने और सेवा गतिविधि में निरंतरता बने रहने से लाभ हुआ, और परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में आई मंदी की भरपाई हुई।

II.1.3 मुद्रास्फीतिरोधी मौद्रिक नीति, सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और वैश्विक पण्य कीमतों में सुधार के कारण 2023-24 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होकर सहन सीमा के भीतर आ गई। मूल मुद्रास्फीति व्यापक आधार पर अवस्फीति स्थिति में थी और दिसंबर 2023 से 4 प्रतिशत से कम हो गई।

¹ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2024), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

² वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी, विश्व व्यापार संगठन (अप्रैल 2024)।

³ इस रिपोर्ट के अध्याय I के फुटनोट 4 का संदर्भ लें।

II.1.4 पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान दिए जाने, संवृद्धि-अनुकूल उपायों की दिशा में सार्वजनिक व्यय किए जाने तथा राजकोषीय सुदृढीकरण के प्रति बेहतर प्रतिबद्धता होने के परिणामस्वरूप सामान्य सरकारी वित्त संबंधी प्रमुख घाटे और ऋण संकेतकों में सुधार हुआ। समुत्थानशील आर्थिक गतिविधि और अनुपालन में सुधार के परिणामस्वरूप कर राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई।

II.1.5 वर्ष के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों में स्थिति के अनुरूप परिवर्तन हुए। चलनिधि अधिशेष घटने के कारण मुद्रा बाजार की दरें बढ़ गईं, जिसमें सरकारी नकदी शेष में वृद्धि होना भी आंशिक कारण रहा। ऋण मांग निरंतर बने रहने के बीच जमा प्रमाण पत्र (सीडी) निर्गम में वृद्धि हुई। घरेलू मुद्रास्फीति के कम होने, प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित भारत सरकार (जीओआई) के अपेक्षित से कम बाजार उधार कार्यक्रम के कारण सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में, जो 2023-24 की पहली छमाही के दौरान सीमा के भीतर था, कमी आई। आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के प्रदर्शन से शेयर बाजारों में मजबूत लाभ दर्ज हुआ। मजबूत घरेलू संभावनाओं और भारत की बाह्य स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये (आईएनआर) ने स्थिरता प्रदर्शित की। भारी पूंजी अंतर्वाहों और चालू खाता घाटे (सीएडी) में आई कमी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।

II.1.6 इस पृष्ठभूमि के साथ शेष अध्याय छह खंडों में संरचित है। वास्तविक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण खंड 2 में किया गया है। खंड 3 में मुद्रास्फीति और उसके चालकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कुल मौद्रिक राशियों और वित्तीय बाजारों में हुए विकास का उल्लेख क्रमशः खंड 4 और 5 में किया गया है। सरकारी वित्त (केंद्र और राज्यों) में हुए परिवर्तनों की चर्चा खंड 6 में की गई है, और बाह्य क्षेत्र में हुए उतार-चढ़ाव खंड 7 में शामिल हैं।

II.2 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 के दौरान कमजोर बाहरी मांग, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनावों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों में लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आघात - सहनीयता को प्रदर्शित किया। 2023-24 में लगातार तीसरे वर्ष वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 7 प्रतिशत और उससे अधिक बनी रही, जो पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने के कारण स्थिर निवेश में मजबूत वृद्धि द्वारा अनुसमर्थित थी। भले ही कृषि क्षेत्र की गतिविधि में मंदी देखी गई लेकिन आपूर्ति पक्ष पर, इनपुट कीमतों में सुधार और सेवा गतिविधि में निरंतर गति से विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता को बढ़ावा मिलने से आर्थिक गतिविधि में सुधार देखने को मिला।

II.2.2 इस खंड में, समग्र मांग का घटक-वार विश्लेषण उप-खंड 2 में दिया गया है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में समग्र आपूर्ति स्थितियों में हुई प्रगति के आकलन की चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। रोजगार और श्रम बाजार में हुए बदलावों के बारे में उप खंड 5 में निष्कर्षात्मक टिप्पणियों सहित उपखंड 4 में चर्चा की गई है।

2. समग्र मांग

II.2.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार वास्तविक जीडीपी ने 2022-23 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की [सारणी II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 1]। इस तेजी को निवेश मांग में ठोस विस्तार से बल मिला, जो निजी उपभोग मांग में मंदी और बाहरी मांग के दबाव की भरपाई से कहीं अधिक है (परिशिष्ट सारणी 2)। 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत पर बने रहकर मजबूत थी। ति 2 में हासिल हुई तेजी बरकरार रहते हुए ति3:2023-24 में और गति पकड़ ली। (चार्ट II.2.1)।

उपभोग

11.2.4 निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) - घरेलू कुल मांग का मुख्य आधार - 2023-24 में कमजोर पड़ गया। अपर्याप्त और असमान दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण खरीफ और रबी दोनों ही फसलों का उत्पादन कम हो गया दोपहिया वाहनों की बिक्री, जोकि ग्रामीण मांग का एक संकेतक है, 2023-24 की दूसरी छमाही में बढ़ी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग भी दूसरी छमाही में कम हुई, जिससे ग्रामीण मांग में कुछ सुधार का संकेत मिलता है। श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार, उच्च प्रयोज्य आय, खुदरा मुद्रास्फीति में कमी और खुदरा ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि से शहरी मांग को समर्थन मिला। घरेलू हवाई यात्री यातायात, रेलवे यात्री यातायात और यात्री वाहन बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और ई-वे बिल जारी करने दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में 2023-24 में मामूली बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि सरकार अपने राजकोषीय सुदृढीकरण लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रही। (चार्ट 11.2.2)

सारणी 11.2.1. वास्तविक जीडीपी वृद्धि

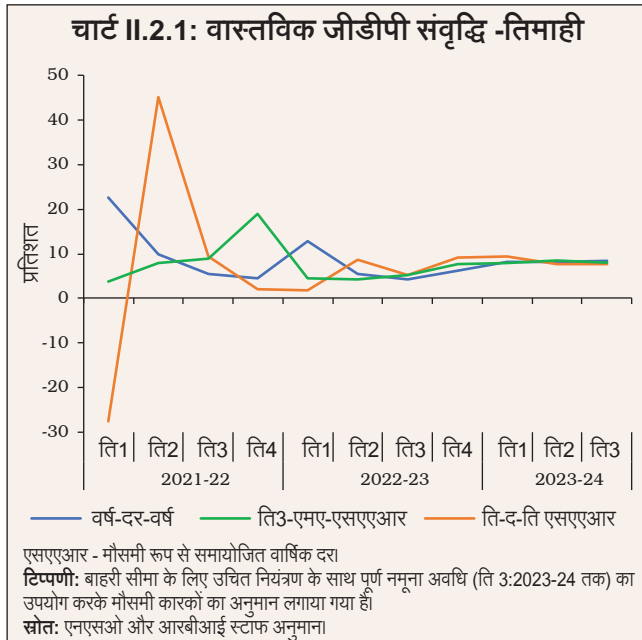
घटक	वृद्धि (प्रतिशत में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
I. कुल उपभोग व्यय	5.0	-4.6	9.8	7.1	3.0
निजी	5.2	-5.3	11.7	6.8	3.0
सरकार	3.9	-0.8	0.0	9.0	3.0
II. सकल पूंजी निर्माण	-6.0	-10.6	25.4	2.0	10.2
सकल स्थिर पूंजी निर्माण शैयरो में बदलाव	1.1	-7.1	17.5	6.6	10.2
मूल्यवान स्टॉक	-58.7	-76.4	525.4	14.5	5.0
III. निवल निर्यात	-3.4	-7.0	29.6	13.4	1.5
निर्यात	-3.4	-7.0	29.6	13.4	1.5
आयात	-0.8	-12.6	22.1	10.6	10.9
IV. जीडीपी	3.9	-5.8	9.7	7.0	7.6

स्रोत: एनएसओ।

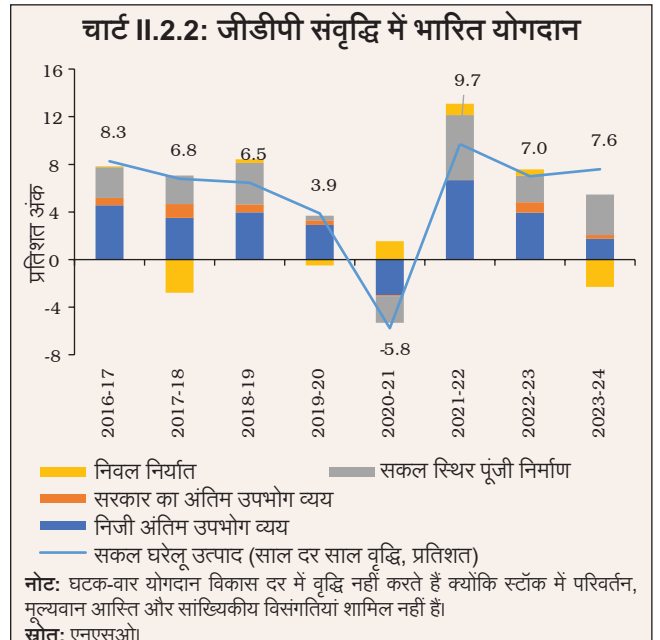
निवेश और बचत

11.2.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, मौजूदा कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से मापी जाती है, जो पिछले वर्ष के

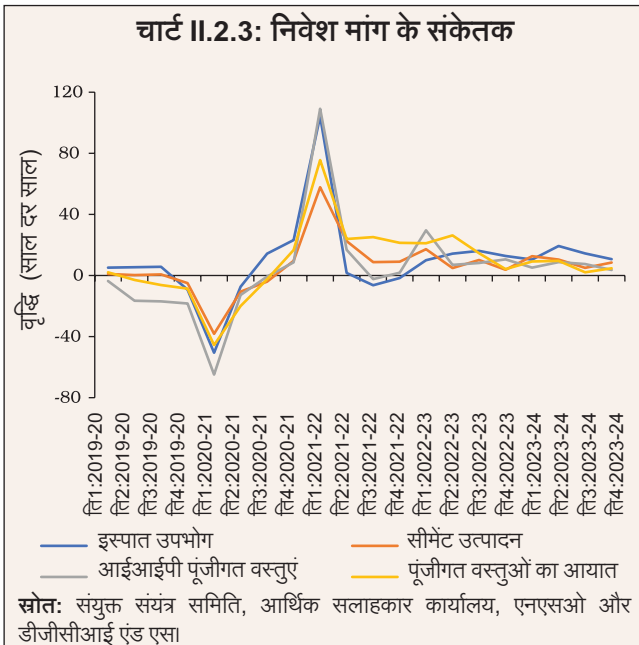
चार्ट 11.2.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि -तिमाही



चार्ट 11.2.2: जीडीपी संवृद्धि में भारत योगदान



चार्ट II.2.3: निवेश मांग के संकेतक



32.4 प्रतिशत से मामूली रूप से कम होकर 2022-23 में 32.2 प्रतिशत हो गई। 2023-24 के लिए जीसीएफ के घटकों के लिए उपलब्ध जानकारी आवास क्षेत्र में तेजी के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर सरकार के निरंतर जोर के कारण निवेश में बढ़ोतरी का संकेत देती है। जीडीपी के मुकाबले वास्तविक सकल स्थिर पूंजी

निर्माण (जीएफसीएफ) का अनुपात पिछले वर्ष के 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 34.1 प्रतिशत हो गया। जीएफसीएफ के घटकों में, निर्माण क्षेत्र ने गति पकड़ी है, जो इसके निकटतम संयोग संकेतकों - इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन में मजबूत वृद्धि से स्पष्ट है (चार्ट II.2.3)। विनिर्माण क्षेत्र का क्षमता उपयोग (सीयू) अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बना हुआ है। यह पिछली तिमाही⁴ के 74.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 की तीसरी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित सीयू 74.6 प्रतिशत था।

II.2.6 सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत 2022-23 में घटकर 29.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 30.8 प्रतिशत थी। ऐसा परिवार वित्तीय बचत (निवल) में पिछले वर्ष के 7.2 प्रतिशत (सारणी II.2.2 और परिशिष्ट सारणी 3) की तुलना में 2022-23 में जीएनडीआई के 5.2 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुआ क्योंकि इसने घरेलू स्तर पर उपभोग और निवेश को निधि देने के लिए महामारी के दौरान संचित हुई अतिरिक्त बचत को कम कर

सारणी II.2.2 : परिवार क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए. सकल वित्तीय बचत	10.4	9.9	10.7	10.4	11.9	11.8	11.4	15.2	10.9	10.9
जिसमें:										
1. मुद्रा	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9	1.1	0.9
2. जमाएं	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.3	6.2	3.5	4.0
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.8
4. सरकार पर दावे	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	0.9
5. बीमा निधि	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.7	2.8	2.0	2.0
6. भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.3	2.3
बी. वित्तीय देयताएं	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	5.7
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	7.2	6.9	7.9	7.3	7.5	7.8	7.6	11.6	7.2	5.2

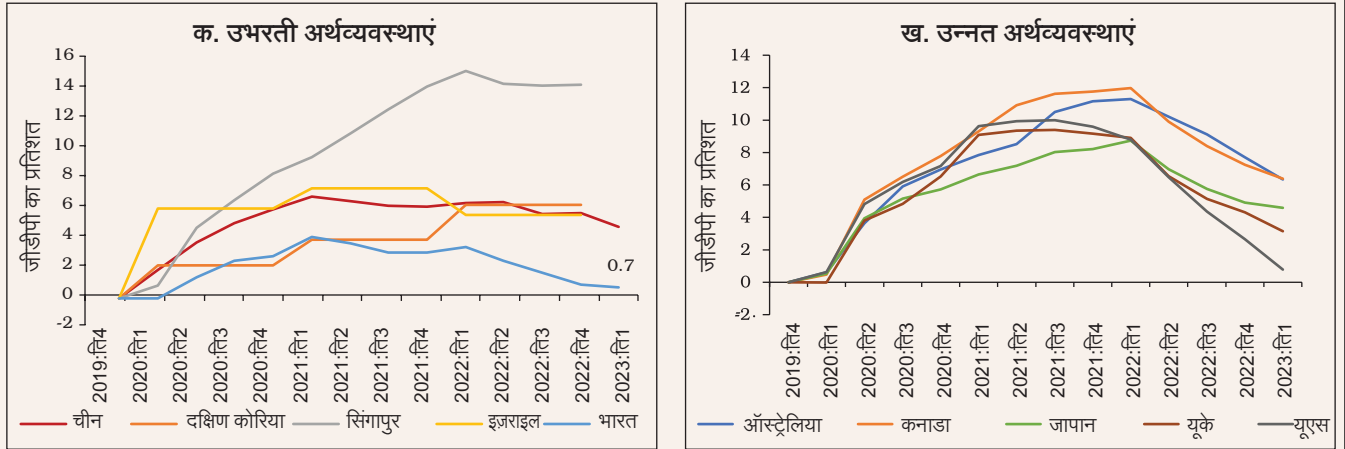
जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय निपटान आय।

टिप्पणी: पूर्णांकन (राउंडिंग ऑफ के कारण) आंकड़े कुल देय की जोड़ के बराबर नहीं भी हो सकते हैं।

स्रोत: एनएसओ।

⁴ रिजर्व बैंक की ऑर्डर बही, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) पर आधारित।

चार्ट II.2.4 : अतिरिक्त परिवार बचत की मात्रा

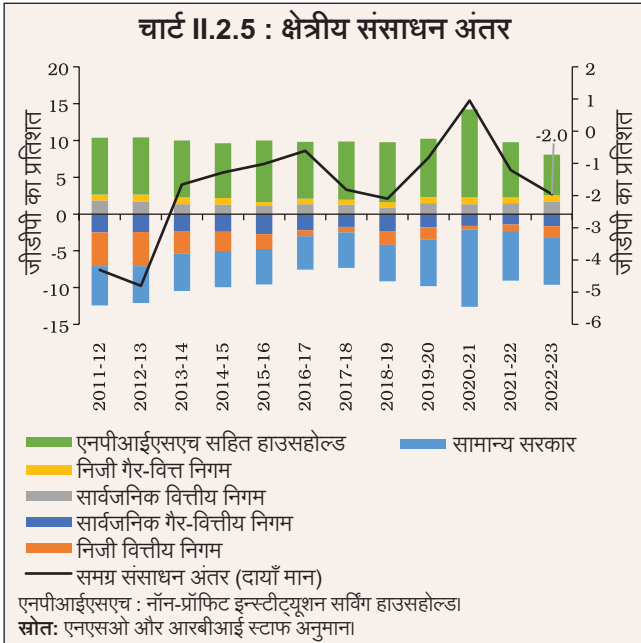


टिप्पणी: भारत संबंधी डेटा में अतिरिक्त पारिवारिक वित्तीय बचत की मात्रा शामिल है।
 स्रोत: सोपर्स ईटी. एएल.,(2023)⁵ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

दिया। वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, भारत ने 2020-21 के दौरान घरेलू वित्तीय बचत (निवल) में जीएनडीआई के 11.6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज किया था, क्योंकि गतिशीलता पर महामारी से उपजे प्रतिबंध और संपर्क-गहन सेवाओं पर खर्च में कटौती

हुई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2021 के अंत तक महामारी के कम होने और दबी हुई मांग के बने रहने के कारण अतिरिक्त वित्तीय बचत⁶ की संचित मात्रा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत हो गया; अतिरिक्त वित्तीय बचत का स्टॉक मार्च 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत तक कम हो गया (चार्ट II.2.4)।

चार्ट II.2.5 : क्षेत्रीय संसाधन अंतर



II.2.7 गैर-वित्तीय निगमों के प्रभाव के कारण, 2022-23 के दौरान बचत-निवेश अंतर बढ़ गया, जो बचत दर में कमी के साथ-साथ निवेश मांग में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट II.2.5)। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिव्यय उच्च स्तर से कम हो गया।

3. समग्र आपूर्ति

II.2.8 एनएसओ के एसईई के अनुसार, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से हासिल गति के चलते मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापी जाने वाली समग्र आपूर्ति, 2022-23 में

⁵ डी सोयर्स, फ्रेंकोइस, डायलन मूर, और जूलियो एल. ऑर्टिज (2023), 'महामारी के दौरान संचित बचत: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ अंतरराष्ट्रीय तुलना', एफईडीएस नोट्स, वाशिंगटन डीसी।

⁶ अतिरिक्त बचत के प्रवाह (बचत दर में बचत दर रुझान को घटाते हुए) की गणना हैमिल्टन रुझान का उपयोग करके अनुमानित बचत दर से विचलन के रूप में की जाती है। स्टॉक 0 से t=-1 पर संचित होना शुरू होता है, जहां t=0 COVID-19 के कारण कम वृद्धि की पहली अवधि है।

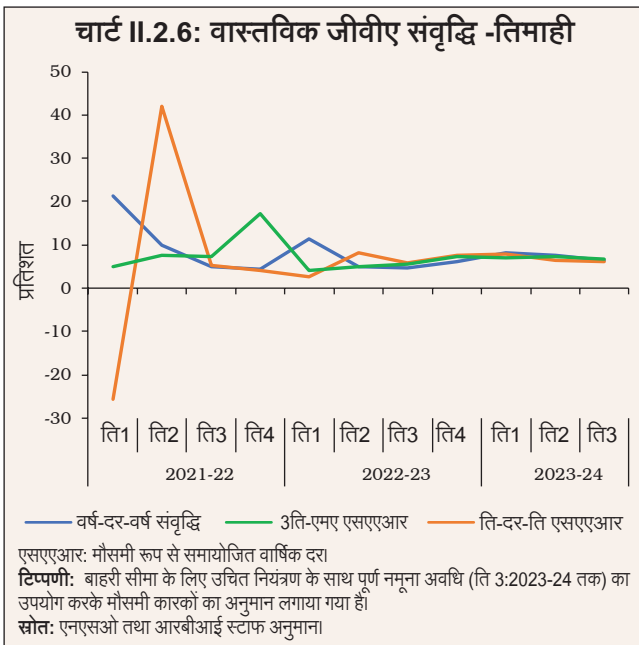
सारणी II.2.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	6.2	4.0	4.6	4.7	0.7
II. उद्योग	-2.5	1.1	9.6	-0.6	8.3
II.1 खनन और उत्खनन	-3.0	-8.2	6.3	1.9	8.1
II.2 विनिर्माण	-3.0	3.1	10.0	-2.2	8.5
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.3	-4.2	10.3	9.4	7.5
III. सेवाएँ	5.8	-7.9	10.6	9.9	7.9
III.1 निर्माण	1.6	-4.6	19.9	9.4	10.7
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	6.0	-19.9	15.2	12.0	6.5
III.3 वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	6.8	1.9	5.7	9.1	8.2
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	6.6	-7.6	7.5	8.9	7.7
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	3.9	-4.1	9.4	6.7	6.9

स्रोत: एनएसओ।

6.7 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 6.9 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि कृषि क्षेत्र 2023-24 में गति कम की गई (सारणी II.2.3)। 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में गति में तेजी देखी गई (चार्ट II.2.6)।



कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ

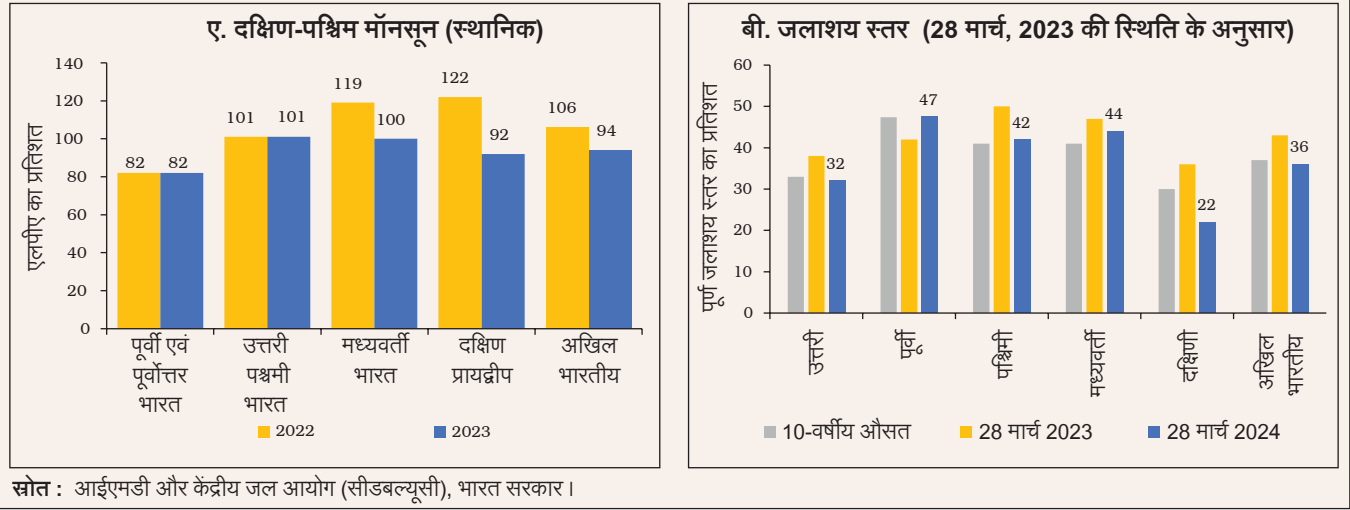
II.2.9 कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र को अल नीनो⁷ की मजबूत स्थिति के साथ-साथ असमान और दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) से होने वाले कम वर्षा से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 2023 (जून-सितंबर) में समग्र एसडब्ल्यूएम वर्षा अखिल भारतीय स्तर पर दीर्घावधि औसत (एलपीए)⁸ से 6 प्रतिशत कम थी (चार्ट II.2.7 ए)। एसडब्ल्यूएम की देर से शुरुआत के साथ-साथ अस्थायी और स्थानिक असमान वर्षा के कारण, खरीफ की बुआई शुरू होने में देरी हुई और समग्र खरीफ बुआई में कमी आई। उत्तर-पूर्वी मानसून (एनईएम) [अक्टूबर-दिसंबर] भी कम वर्षा (9 प्रतिशत) के साथ समाप्त हुआ। सामान्य से कम एसडब्ल्यूएम और एनईएम वर्षा ने जलाशयों के भंडारण स्तर को कम कर दिया (चार्ट II.2.7बी)।

II.2.10 एसई के अनुसार, 2023-24 में खरीफ और रबी खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष के अंतिम अनुमान से 1.3 प्रतिशत कम था (सारणी II.2.4)। उत्पादकता लाभ से बाजरा

⁷ ऐतिहासिक रूप से, 23 अल नीनो वर्षों में से 14 वर्षों में एसडब्ल्यूएम मानसून वर्षा कम रही है। 1997 आखिरी अल नीनो वर्ष था जिसके दौरान एसडब्ल्यूएम सीजन में सामान्य वर्षा हुई थी।

⁸ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सामान्य वर्षा सीमा दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 96-104 प्रतिशत है।

चार्ट II.2.7: वर्षा एवं जलाशय स्तर



के उत्पादन को लाभ होने की संभावना है (बॉक्स II.2.1)। पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार, 2023-24 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 2022-23 के अंतिम अनुमान से 0.1 प्रतिशत कम था, जिसका मुख्य कारण सब्जियों का कम उत्पादन था।

II.2.11 2023-24 में खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने सभी फसलों की उत्पादन⁹ लागत पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित किया। 31 मार्च 2024 को खाद्यान्न का कुल सार्वजनिक स्टॉक कुल त्रैमासिक बफर मानदंड का 2.9 गुना था (चार्ट II.2.8)।

सारणी II.2.4: कृषि उत्पादन 2023-24

(लाख टन)

फसल	2022-23 अंतिम अनुमान**	2023-24 द्वितीय एई (एसएई)	2023-24 2022-23 के अंतिम अनुमान के दौरान (एसएई) घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. खाद्यान्न	3,135.5	3,093.5	-1.3
चावल	1,255.2	1,238.2	-1.4
गेहूं	1,105.5	1,120.2	1.3
पोषक मोटा अनाज	535.0	500.7	-6.4
दालें	239.8	234.4	-2.2
तूर	33.1	33.4	0.8
चना	122.7	121.6	-0.9
उड़द	24.0	20.6	-14.4
मूँग	18.3	15.1	-17.6
2. तिलहन	403.0	366.0	-9.2
3. गन्ना	4,905.3	4,464.3	-9.0
4. कपास #	336.6	323.1	-4.0
5. जूट और मेस्ता ##	93.9	96.3	2.6

* खरीफ और रबी फसलें

** गर्मियों की फसलें छोड़कर

#: हरेक 170 किलोग्राम की लाख गाँठें

##: हरेक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

⁹ वास्तविक भुगतान लागत और परिवार श्रम का आरोपित मूल्य का जोड़ (ए2+एफएल)।

बॉक्स II.2.1

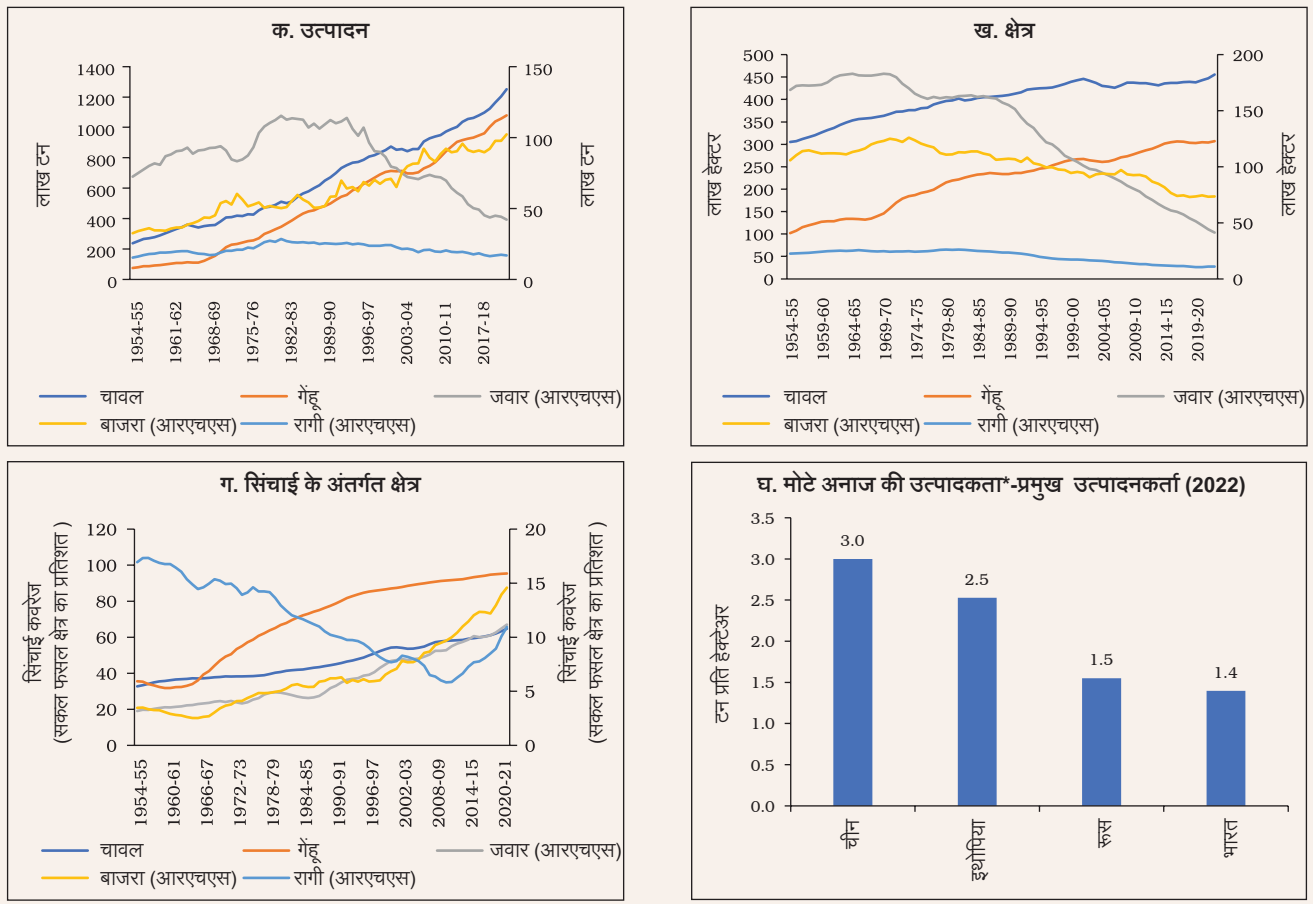
भारत में मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना: आपूर्ति पक्ष के संवाहकों की पहचान करना

एशिया के लगभग 80 प्रतिशत और वैश्विक मोटे अनाज उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग भारत द्वारा उत्पादित¹⁰ होता है। हालाँकि, बाजरा का रकबा और उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है (चार्ट 1ए और 1बी), जो आंशिक रूप से एमएसपी-समर्थित खरीद के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन और गुणवत्तापूर्ण अनाज के प्रति उपभोक्ता प्राथमिकताओं में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है (राव, 2021)। मोटे अनाज आम तौर पर बिना/न्यूनतम सिंचाई के वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है (चार्ट 1सी)। भारत में मोटे

अनाज की उत्पादकता दुनिया भर के प्रमुख उत्पादकों की तुलना में कम बनी हुई है (चार्ट 1डी)।

2021-22 के लिए प्लॉट स्तर की खेती की व्यापक लागत सर्वेक्षण (सीसीसीएस) डेटा सीमांत¹¹ किसानों से एक महत्वपूर्ण उपज अंतर को दर्शाता है, जिससे सुधार की काफी गुंजाइश बनती है। इस पृष्ठभूमि में, 2021-22 के लिए सीसीसीएस डेटासेट का उपयोग करते हुए एक सामान्यीकृत रैखिक मॉडल के परिणाम वर्षा की स्थिति पर बाजरा के लिए उपज अंतर¹² की एक महत्वपूर्ण निर्भरता दिखाते हैं (सारणी 1)।

चार्ट 1 : भारत में मोटे अनाज की तुलना में प्रमुख अनाजों का उत्पादन



*: जवार को छोड़कर।

नोट: डेटा 5 वर्ष के चल औसत पर आधारित है।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और एफएओएसटीएटी, यूएनओ।

(जारी)

¹⁰ "भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुंच गया", पीआईबी, 31 जनवरी 2023।

¹¹ अधिकतम प्राप्य (संभावित) उपज सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूखंडों की औसत उपज है। (प्रत्येक राज्य के लिए सर्वेक्षण किए गए नमूने का शीर्ष 10 प्रतिशत)। उपज अंतर को संभावित और वास्तविक उपज के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹² परिणाम चर (उपज अंतर) प्रतिशत के संदर्भ में है; इसलिए, मान शून्य (कोई उपज अंतर नहीं) से लेकर अधिकतम एक या 100 प्रतिशत तक होता है। परिणाम चर की इस प्रकृति के कारण, पैपके और वूल्ड्रिज (1996) के बाद विश्लेषण के लिए एक भिन्नात्मक लॉजिस्टिक प्रतिगमन मॉडल का चयन किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि अधिक इनपुट उपयोग निम्न स्तर के उपज अंतर से जुड़ा है।

सारणी 1 : मोटे अनाज उत्पादन में उपज अंतर के निर्धारक

आश्रित चर: उपज अंतर	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4
वर्षा				
वास्तविक वर्षा (मिलीमीटर)	-1.27*** (0.26)	-0.98*** (0.23)	-	-
एलपीए से विचलन (1 = सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा [@])	-	-	-0.04** (0.02)	-0.04** (0.02)
इनपुट चर				
श्रम (घंटे/हेक्टेयर)	-0.60* (0.33)	-0.84*** (0.27)	-0.88*** (0.29)	-0.85*** (0.28)
सिंचाई (घंटे/हेक्टेयर)	-0.01 (0.02)	0.01 (0.01)	0.02 (0.01)	-
सिंचाई का स्वामित्व (1=स्वामित्व)	-	-	-	-0.01* (0.01)
बीज (किलो/हेक्टेयर)	0.16 (0.15)	0.15 (0.10)	0.12 (0.11)	0.10 (0.11)
उर्वरक (किलो/हेक्टेयर)	-0.17*** (0.04)	-0.16*** (0.04)	-0.17*** (0.05)	-0.16*** (0.04)
प्रौद्योगिकी चर				
संकर बीजों का उपयोग (1=अपनाया गया)	-0.06** (0.03)	-0.05** (0.02)	-0.03 (0.02)	-0.04* (0.02)
मशीन (घंटे/हेक्टेयर)	-0.19** (0.09)	-0.11* (0.07)	-0.12** (0.06)	-0.13** (0.06)
मांग चर				
विलंबित कीमत [#] (₹/क्विंटल)	-1.73 (1.55)	-	-	-
अपेक्षित निवल प्रतिलाभ [#] (1= सकारात्मक प्रतिलाभ)	-	-0.14*** (0.02)	-0.15*** (0.02)	-0.14*** (0.02)
राज्य डमी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
पर्यवेक्षणों की संख्या	448	448	427	427
छद्मसंभावना लॉग	-288.67	-282.00	-272.17	-272.13

-: लागू नहीं

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।

@: एलपीए से +/-19 प्रतिशत का वर्षा विचलन जिला स्तर पर सामान्य माना जाता है।

#: पिछले वर्ष की कीमतों के आधार पर।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियाँ हैं (डेल्टा विधि का उपयोग करके गणना की जाती है और ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर की जाती है)।

2. जिला स्तर पर ली गई कीमतों और वर्षा को छोड़कर, सभी चर के डेटा का उपयोग प्लॉट स्तर पर किया गया है।

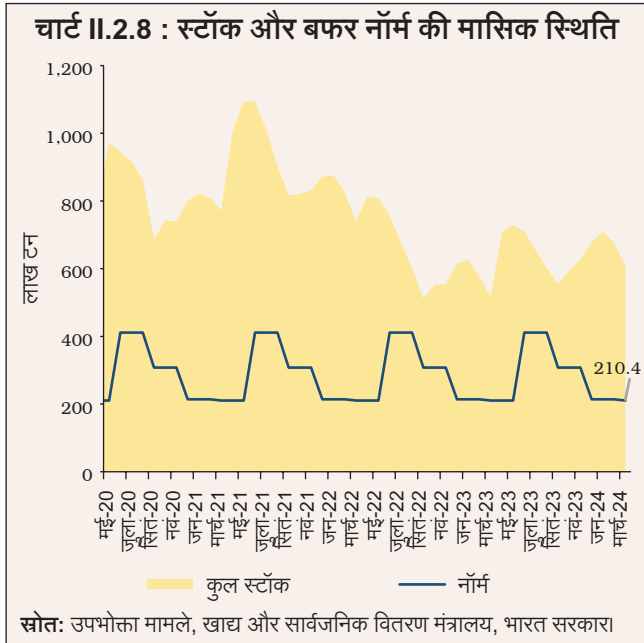
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हालाँकि मोटे अनाज को सूखा प्रतिरोधी फसल माना जाता है, लेकिन न्यूनतम किंतु सुनिश्चित¹³ सिंचाई उपज के अंतर को पाटने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्रम, उर्वरक और मशीन का उपयोग भी उपज अंतर से नकारात्मक किन्तु महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। संकर बीज अपनाने से पैदावार बेहतर होती है। उच्च अपेक्षित निवल प्रतिलाभ (पिछली कीमतों और प्रचलित लागत का उपयोग करके अनुमानित) भी किसानों को उच्च उपज वाले इनपुट में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार उपज अंतर को कम करेगा।

सन्दर्भ:

1. पपके, एल.ई., और वूल्ड्रिज, जे.एम. (1996), 'इक्नोमेट्रिक मेथड्स फॉर फ्रैक्शनल रिस्पॉन्स वेरिएबल्स विद एन एप्लीकेशन टू 401 (के) प्लान पार्टिसिपेशन रेट्स', *जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स*, 11(6), 619-632।
2. राव, बी.डी., भंडारी, आर. और टोनापी, वी.ए. के. (2021), 'बाजरा पर श्वेत पत्र - पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा को मुख्यधारा में लाने पर एक नीति नोट', आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद, भारत।

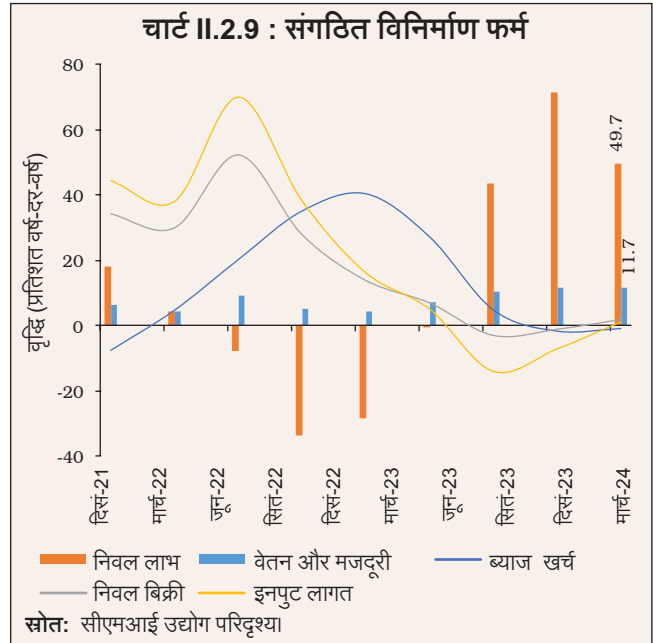
¹³ सारणी 1 में सिंचाई के स्वामित्व को डमी द्वारा समझाया गया।



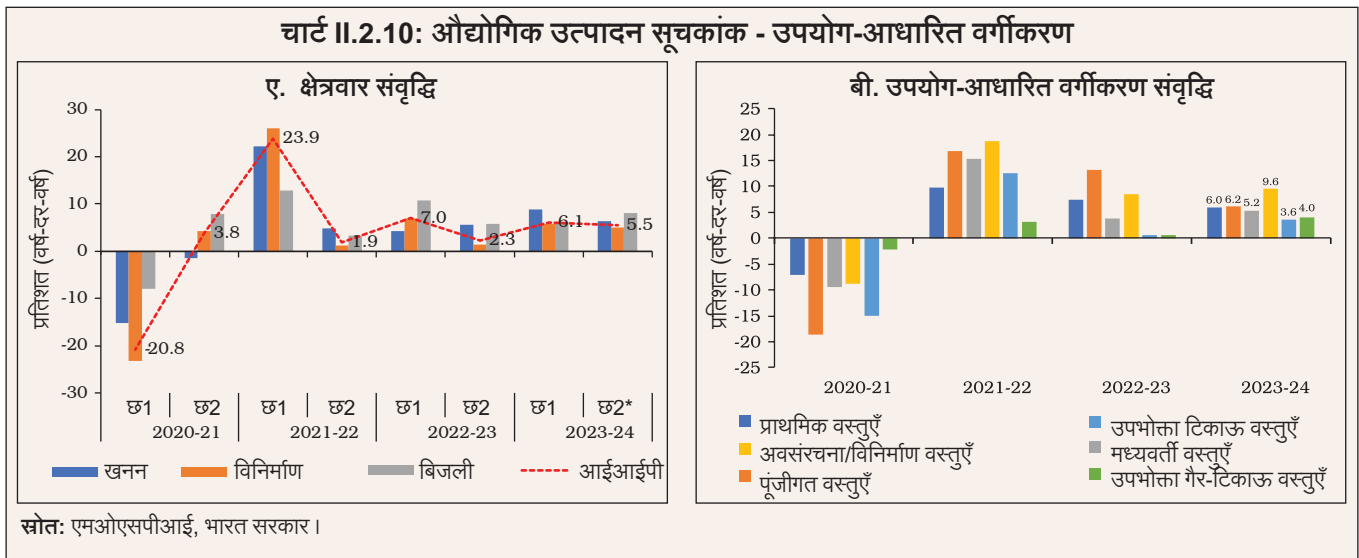
29 नवंबर 2023 को, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण को 1 जनवरी 2024 से पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

औद्योगिक क्षेत्र

II.2.12 भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें इनपुट लागत के दबाव में कमी और साथ ही बेहतर कॉरपोरेट मुनाफे से मदद मिली (चार्ट II.2.9)।



II.2.13 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में 2023-24 के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में यह 5.2 प्रतिशत थी (चार्ट II.2.10ए)। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 उद्योग समूहों में से 13 ने परिवहन उपकरण, मोटर वाहन और बुनियादी धातुओं के नेतृत्व में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज किया। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष विस्तार दर्ज किया गया (चार्ट II.2.10बी)। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज किया गया (चार्ट II.2.10बी)।



II.2.14 विनिर्माण क्षेत्र को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लाभ हुआ। दिसंबर 2023 तक ₹1.07 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.7 लाख करोड़ का उत्पादन/बिक्री हुई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 7.0 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ और निर्यात ₹3.4 लाख करोड़ से अधिक हो गया। योजना की शुरुआत से अब तक लगभग ₹4,415 करोड़ का प्रोत्साहन संवितरित किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पीएलआई योजना के प्रमुख लाभार्थी रहे हैं।

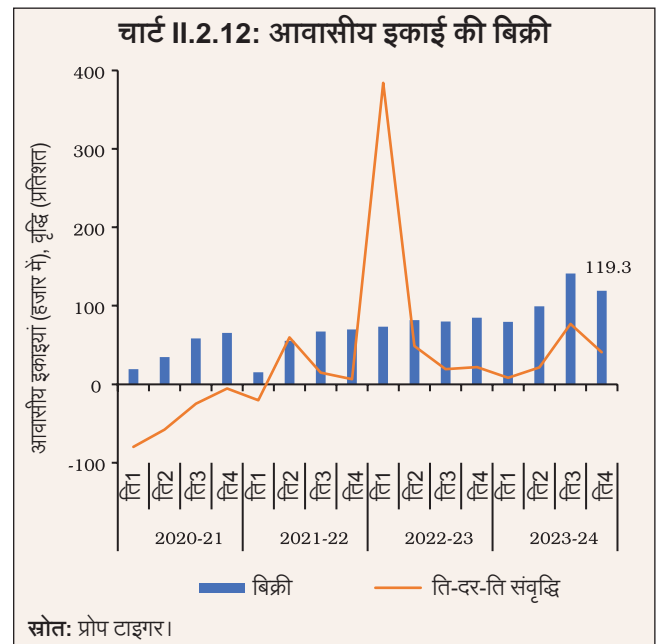
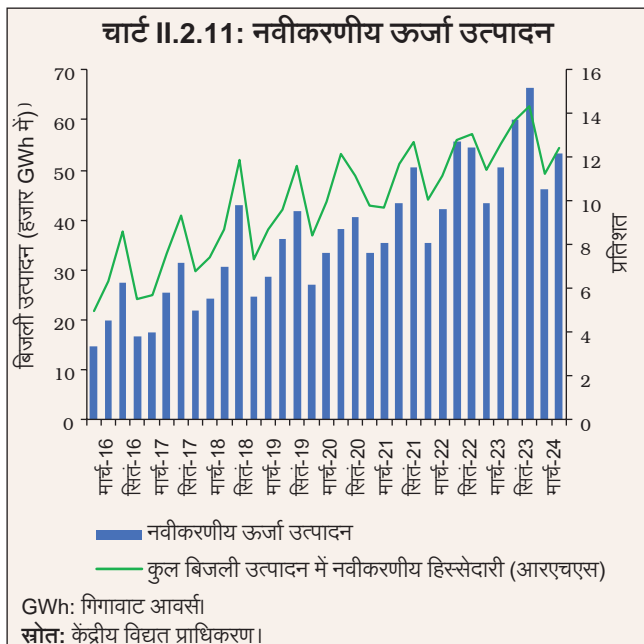
II.2.15 कोयला उत्पादन में वृद्धि के कारण खनन क्षेत्र सूचकांक में 2023-24 में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। नवीकरणीय ऊर्जा, जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत है, ने 2023-24 के दौरान बेहतर वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.2.1)। 31 मार्च, 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 190.6 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी।

सेवा क्षेत्र

II.2.16 2023-24 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि को निर्माण गतिविधि और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं द्वारा बढ़ावा

मिला। हवाई यातायात, रेलवे माल ढुलाई, ऑटोमोबाइल बिक्री, स्टील की खपत, जीएसटी ई-वे बिल और विदेशी पर्यटकों के आगमन जैसे सेवा क्षेत्र के अनुमानित संकेतकों में उछाल दर्ज किया गया (सारणी II.2.5)।

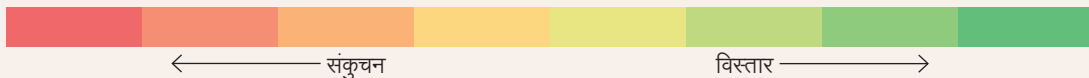
II.2.17 भारत का निर्माण क्षेत्र, जो वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि दर्ज की। 2023-24 में स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महामारी के बाद से घरेलू स्वामित्व के लिए संचित मांग और मजबूत उपभोक्ता परिदृश्य ने 2023-24 में गति बनाए रखी (चार्ट II.2.12)। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र 2023-24 में सुस्त रहा। निरंतर अवकाश और कॉरपोरेट यात्रा मांग के साथ, आतिथ्य क्षेत्र ने और अधिक लाभ कमाया। वित्तीय क्षेत्र में, कुल जमा और वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण में दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज हुई। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने निरंतर वृद्धि दर्ज की।



सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

संकेतक	2022-23				2023-24			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी मांग								
ऑटोमोबाइल बिक्री	51.8	16.9	10.0	8.7	12.2	0.9	20.6	21.7
यात्री वाहन बिक्री	33.9	34.4	21.4	10.7	9.5	5.7	8.7	10.8
कृषि / ग्रामीण मांग								
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	15.8	4.8	10.5	18.7	-1.9	-5.8	-4.9	-22.9
दुपहिया वाहनों की बिक्री	55.0	13.6	7.2	6.7	11.2	-1.6	22.6	24.9
तिपहिया वाहनों की बिक्री	211.3	71.2	68.2	84.4	89.6	62.2	35.2	7.3
यातायात								
कुल वाहन पंजीकरण	61.3	1.4	19.0	15.1	6.0	13.9	10.7	10.8
घरेलू हवाई यात्री यातायात	206.2	64.1	18.5	52.2	19.1	23.0	9.1	5.2
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	403.3	263.9	98.1	93.6	35.0	21.6	18.5	17.0
घरेलू हवाई कार्गो	32.1	10.0	-3	0.5	-1.0	-1.0	9.5	10.0
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	-1.7	-3.8	-11	-2.8	0.1	3.7	10.7	23.9
माल यातायात निवल टन किलोमीटर @	19.4	14.5	-66.7	4.7	-3.5	0.9	4.6	-
माल यातायात माल प्रारंभ स्थान*	11.8	8.4	3.2	-33.5	1.1	4.8	6.4	8.2
पोर्ट कार्गो	9.3	12.8	5.2	8.6	0.8	2.9	10.0	2.7
घरेलू व्यापार								
जीएसटी ई-वे बिल	45.6	20.1	17.2	18.1	15.8	15.0	17.1	16.3
जीएसटी ई-वे बिल इंटर-स्टेट	46.6	23.8	23.6	22.3	19.3	18.4	22.1	18.2
जीएसटी ई-वे बिल अंतर-राज्यीय	43.8	14.6	7.4	11.4	10.0	9.3	8.6	13.1
जीएसटी राजस्व	34.5	27.5	14.2	12.6	11.6	10.6	12.9	11.3
निर्माण								
स्टील की खपत	10.0	14.3	16.1	12.9	11.1	16.8	11.6	8.6
सीमेंट उत्पादन*	17.3	4.9	10.1	3.8	12.7	10.3	5.1	8.5
पर्यटन और आतिथ्य								
होटल अधिभोग दर	64.7	62.2	65.0	66.3	63.0	60.9	65.2	67.8
विदेशी पर्यटकों का आगमन*	895.4	521.5	218.2	121.0	38.2	17.5	14.0	13.1



* : @: ति3:2023-24 का डेटा अक्टूबर 2023 से संबंधित है। *: ति4:2023-24 का डेटा जनवरी-फरवरी 2024 के लिए है। -: उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम); ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; वाहन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; रेल मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बंदरगाह संघ; वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); संयुक्त संयंत्र समिति; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; एचवीएस एनारॉक, और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

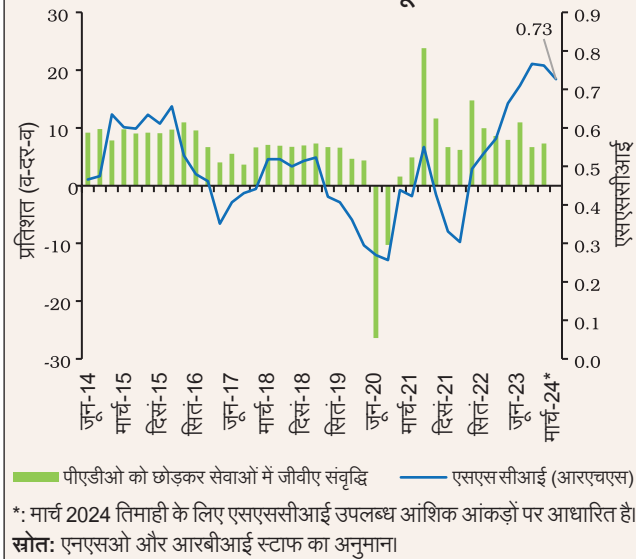
II.2.18 सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)¹⁴, जिसमें निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं से जड़ी गतिविधि आदि शामिल है और पीएडीओ को छोड़कर सेवा क्षेत्र में जीवीए वृद्धि का एक संयोग संकेतक है, 2023-24 में ऊंचे स्तर पर रहा (चार्ट II.2.13).

4. रोजगार

II.2.19 2022-23 और 2023-24 के दौरान श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ। वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि के साथ-साथ 2022-23 में बेरोजगारी

¹⁴ एसएससीआई का निर्माण उच्च आवृत्ति संकेतकों, अर्थात् स्टील की खपत, सीमेंट उत्पादन, प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री/उत्पादन, रेलवे माल यातायात, हवाई यात्री/माल यातायात, पर्यटक आगमन, गैर-तेल आयात, बैंक ऋण और जमा आदि से एकत्र की गई जानकारी को उपयुक्त रूप से संकलित और संयोजित करके किया गया है।

चार्ट II.2.13: सेवा क्षेत्र में संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक



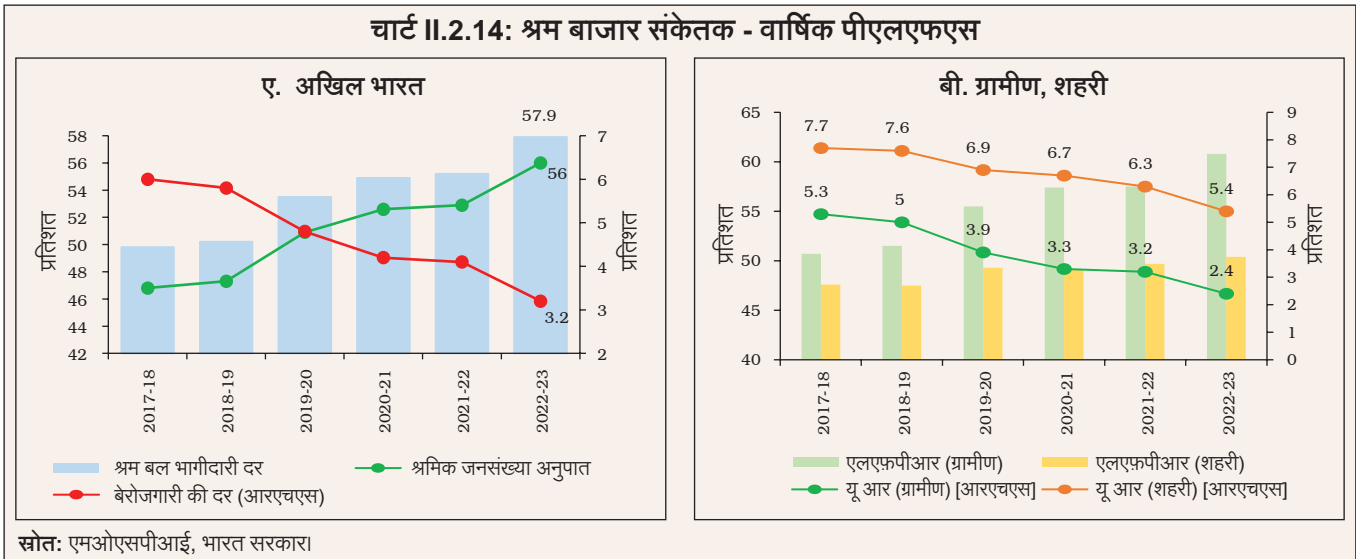
दर (यूआर) घटकर 3.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत से) हो गई। महामारी के बाद बेहतर सामान्यीकरण के साथ, 55.2 प्रतिशत¹⁵ से 57.9 प्रतिशत हो गया। 2022-23 के लिए एलएफपीआर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में पीएलएफएस शृंखला की शुरुआत के बाद से

सबसे अधिक थे (चार्ट II.2.14ए)। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ (चार्ट II.2.14बी)।

II.2.20 शहरी क्षेत्रों को कवर करने वाले त्रैमासिक पीएलएफएस, के अनुसार, एलएफपीआर के साथ-साथ ति4: 2023-24 के दौरान श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक था, जिसने बेरोजगारी दर को उसके न्यूनतम स्तर 6.7 प्रतिशत तक ले जाने में मदद की (चार्ट II.2.15)। पेट्रोल डेटा द्वारा मापे गए संगठित क्षेत्र के रोजगार में भी 2023-24 में वृद्धि का संकेत मिला (चार्ट II.2.16)।

II.2.21 उत्पादकता वृद्धि मध्यम अवधि की संवृद्धि का एक प्रमुख चालक है। 1990 के दशक से भारत में उत्पादकता वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में निम्न-उत्पादक से उच्च-उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों का पुनर्वितरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)¹⁶ का तीव्र विस्तार शामिल है [बॉक्स II.2.2]

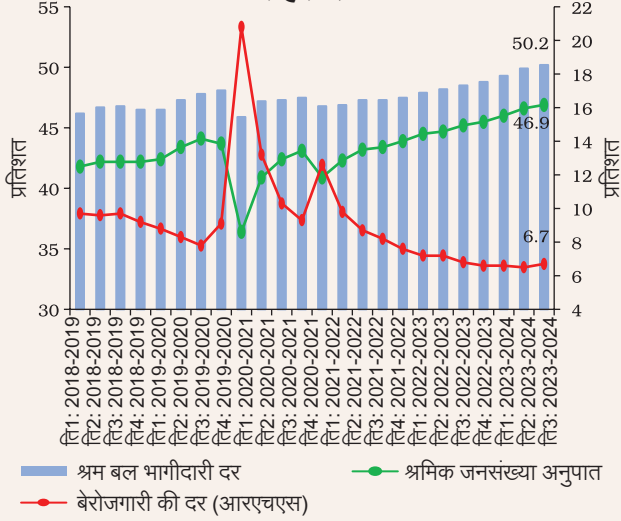
चार्ट II.2.14: श्रम बाजार संकेतक - वार्षिक पीएलएफएस



¹⁵ वार्षिक संकेतक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) पर आधारित होते हैं जबकि त्रैमासिक पीएलएफएस संकेतक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर आधारित होते हैं। सभी संकेतक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए हैं।

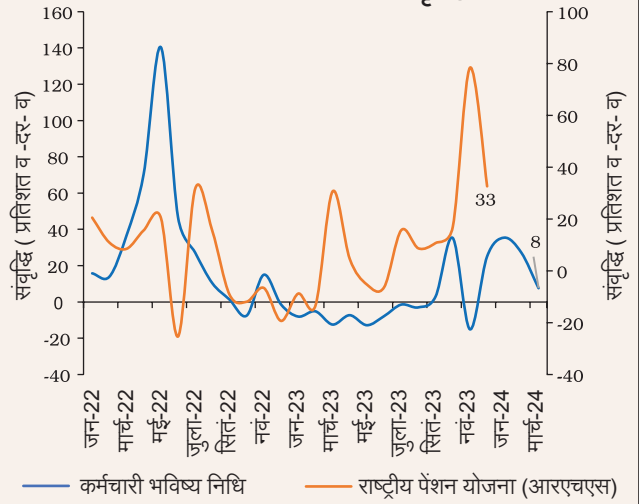
¹⁶ आईसीटी क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्योग शामिल हैं, जिनके उत्पाद ट्रांसमिशन और डिस्प्ले (ओईसीडी, 2020) सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्रसंस्करण और संचार के कार्य को पूरा करते हैं।

चार्ट II.2.15: त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक - शहरी क्षेत्र



स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

चार्ट II.2.16: कर्मचारी भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना - ग्राहक वृद्धि



स्रोत: एमओएसपीआई और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

बॉक्स II.2.2

भारत में उत्पादकता और डिजिटलीकरण

उत्पादकता पर डिजिटलीकरण¹⁷ के प्रभाव का आकलन दो अलग-अलग चैनलों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात्, अर्थव्यवस्था में आउटपुट और श्रम उत्पादकता वृद्धि में इनपुट के रूप में आईसीटी की भूमिका के माध्यम से; और आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों (दास और एरुबन, 2016) के बीच अंतर की जांच करके उत्पादकता संभावनाओं का अनुमान लगाना।

उत्पादन कार्य में इनपुट के रूप में आईसीटी की भूमिका

भारत के लिए, 1980 से 2020 तक 27 केएलईएमएस उद्योगों के लिए उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि का अनुमान इस प्रकार बनाया गया था:

$$\Delta \ln Y \equiv \bar{v}_{ictk} \Delta \ln ICTk + \bar{v}_{ictnonk} \Delta \ln ICTnonk + \bar{v}_L \Delta \ln L + \Delta TFP \quad \dots (1)^{18}$$

अगले चरण में, श्रम उत्पादकता वृद्धि का विघटन इस प्रकार प्राप्त होता है:

$$\Delta \ln Lp \equiv v_{ictk}^- \Delta \ln ICTk + v_{ictnonk}^- \Delta \ln ICTnonk + v_L^- \Delta \ln LQ + \Delta TFP \quad \dots (2)^{19}$$

विघटन परिणाम²⁰ दर्शाते हैं कि उत्पादन वृद्धि में आईसीटी पूंजी सेवाओं का योगदान 1981-90 के दौरान 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 1992-2023 के दौरान 13.2 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में श्रम उत्पादकता वृद्धि में आईसीटी पूंजी का योगदान 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गया।

टीएफपी वृद्धि पर आईसीटी क्षेत्रों का प्रभाव

निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करके आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों के बीच उत्पादकता अंतर की जांच करने के लिए 27 केएलईएमएस उद्योगों को आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

(जारी)

¹⁷ ओईसीडी (2020) के अनुसार, आर्थिक विकास में आईसीटी क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाकर डिजिटलीकरण की सीमा को मापा जा सकता है।

¹⁸ जहां कुल मूल्य वर्धित (Y) उद्योग मूल्य वर्धित वृद्धि के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। $\Delta \ln k$ और $\Delta \ln L$ कारक इनपुट - पूंजी और श्रम में वृद्धि को दर्शाते हैं। पूंजीगत इनपुट को आईसीटी पूंजी और गैर-आईसीटी पूंजी में विभाजित किया गया है। इन्हें क्रमशः ICTK और ICTnonK के रूप में दर्शाया गया है। \bar{v}_{ictk} और $\bar{v}_{ictnonk}$ कुल जोड़े गए मूल्य में आईसीटी और गैर-आईसीटी पूंजी के दो-अवधि के औसत मुआवजे के हिस्से को दर्शाते हैं। \bar{v}_L कुल जोड़े गए मूल्य में श्रम मुआवजे का दो-अवधि का औसत हिस्सा है। ΔTFP समग्र TFP वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

¹⁹ जहां $\Delta \ln Lp$ श्रम उत्पादकता वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, v_{ictk}^- और $v_{ictnonk}^-$ क्रमशः आईसीटी और गैर-आईसीटी उद्योगों में पूंजी गहनता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, और $\Delta \ln LQ$ श्रम गुणवत्ता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

²⁰ 1991 और 2020, क्रमशः बीओपी संकट और सीओवीआईडी वर्ष होने के कारण, नकारात्मक श्रम उत्पादकता वृद्धि के कारण विश्लेषण से हटा दिए गए हैं।

सारणी 1 : उत्पादकता और आईसीटी क्षेत्र

अवधि/चर	आश्रित चर (ΔP_i):				
	1980-2020	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020
1	2	3	4	5	6
आईसीटी क्षेत्र डमी	0.16*** (3.46)	0.31* (1.83)	0.52 (1.39)	0.68* (1.99)	-0.31 (-0.91)
गैर-आईसीटी क्षेत्र डमी	0.12' (2.69)	0.27 (1.56)	0.45 (1.24)	0.60* (1.82)	-0.33 (-0.99)
आईसीटी और गैर-आईसीटी के बीच अंतर	0.04*** (5.46)	0.04*** (9.15)	0.07' (2.69)	0.07'' (3.24)	0.01 (1.33)
पर्यवेक्षणों की संख्या	1053	243	243	243	243

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. मॉडल में श्रम गुणवत्ता, पूंजी स्टॉक, पूंजी संरचना, उद्योग और वर्ष-निर्धारित प्रभावों के नियंत्रण शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-सांख्यिकी हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

$$\Delta P_{it} = \alpha + \beta * ICT Dummy + \gamma X_{it} + \epsilon_{it} \quad \dots (3)^{21}$$

परिणाम बताते हैं कि, औसतन, आईसीटी क्षेत्र की उत्पादकता पूरे नमूना अवधि (1980-2020) और दशकीय उप-अवधि (सारणी 1) के लिए गैर-आईसीटी क्षेत्र की तुलना में बेहतर रही। आईसीटी का उत्पादकता प्रभाव 1980 से 2010 के दौरान बढ़ता रहा, जिसने भारत के लिए सोलो के उत्पादकता विरोधाभास²² की अवधारणा को खारिज कर दिया।

हालाँकि, हाल की अवधि (2010-2020) में भारत में विरोधाभास का उद्भव आम तौर पर दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते डिजिटलीकरण के बावजूद जीएफसी उत्पादकता मंदी के अनुरूप है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों या उनकी गुणवत्ता तक असमान पहुंच को दर्शाता है; और अग्रणी और पिछड़ी फर्मों के बीच प्रौद्योगिकी लाभों के धीमे प्रसार (डाइप्पे एट अल., 2020) को दर्शाता है।

सन्दर्भ:

1. डाइप्पे, ए., किलिक सेलिक, एस., और किंडबर्ग-हैनलॉन, जी (2020), 'ग्लोबल प्रोडक्टिविटी: ट्रेड्स, ड्राइवर्स, एंड पॉलिसीस', विश्व बैंक, वाशिंगटन
2. एरुंबन, ए.ए., और दास, डी.के. (2016), 'इन्फोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया', टेलीकम्यूनिकेशंस पॉलिसी 40(5), 412-431।
3. ओईसीडी (2020), 'ए रोडमैप टुवार्ड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर मीसरिंग द डिजिटल इकोनॉमी', रिपोर्ट फॉर द जी 20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स।
4. वैन आर्क, बी. (2016), 'द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स ऑफ द न्यू डिजिटल इकोनॉमी', इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी मॉनिटर, 31, 3-18।

5. निष्कर्ष

II.2.22 कमजोर बाहरी मांग के होते हुए भी मजबूत निवेश गतिविधि के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि को दर्शाया। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आपूर्ति पक्ष में प्रमुख वाहक थे जबकि असमान और न्यून मॉनसून वर्षा के कारण कृषि गतिविधि धीमी रही। राजकोषीय सुदृढीकरण को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर ध्यान को देखते

हुए, संवृद्धि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। मजबूत कॉरपोरेट तुलनपत्र, बढ़ती क्षमता उपयोग, दोहरे अंक की ऋण वृद्धि, स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र और जारी अवस्फीति आदि के विकास के अन्य कारक बनने की संभावना है। लंबे समय तक बने रहने वाले भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन और प्रतिकूल जलवायु संबंधी दबाव परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं।

²¹ जहां ΔP_{it} वार्षिक उत्पादकता वृद्धि दर है, i उद्योग है, और t वर्ष (1980-2020) है। आईसीटी उद्योग डमी है, जो मान 1 लेता है, यदि उद्योग आईसीटी क्षेत्र से संबंधित है और 0 अन्यथा। X_{it} यह श्रम गुणवत्ता, पूंजी गुणवत्ता, कुल पूंजी स्टॉक, उद्योग निश्चित प्रभाव और वर्ष निश्चित प्रभाव सहित नियंत्रण चर का एक वेक्टर है। X_{it} गैर-आईसीटी क्षेत्र से संबंधित उद्योग के लिए अनुमानित औसत उत्पादकता है, और $\alpha + \beta$ आईसीटी क्षेत्र से संबंधित उद्योग के लिए अनुमानित औसत उत्पादकता है। इसलिए, β आईसीटी और गैर-आईसीटी उद्योग की उत्पादकता वृद्धि दर में अंतर दिखाता है।

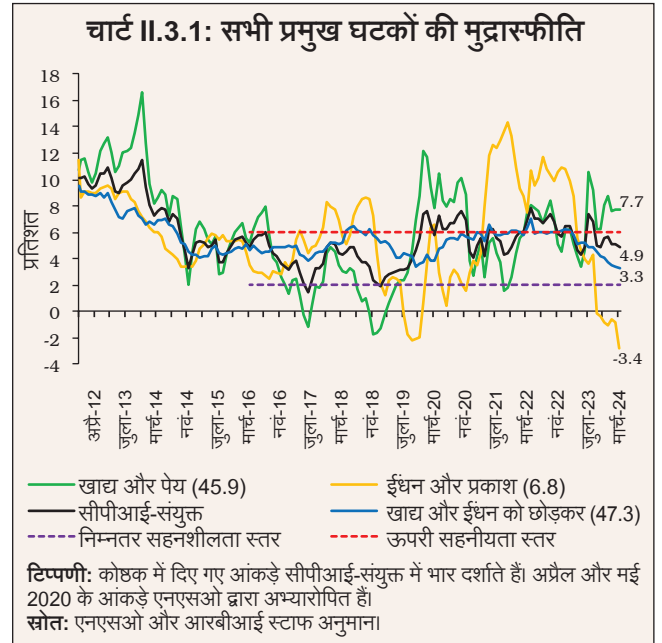
²² नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उद्भव कई अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकता में गिरावट के साथ हुआ है। जिसे अक्सर 'सोलो उत्पादकता विरोधाभास' (वैन आर्क 2016) के रूप में जाना जाता है।

II.3 कीमतों की स्थिति

II.3.1 भारत में, मौद्रिक नीति को सख्त करने, आपूर्ति प्रबंधन उपायों और इनपुट लागत दबावों को कम करने के फलस्वरूप, 2023-24 अवधि के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति²³ कम होकर सहन स्तर में आ गई (अध्याय III देखें)। लगातार आपूर्ति दबावों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर रही। दूसरी ओर, मुख्य मुद्रास्फीति निरंतर आधार पर कम हुई, जिससे मौजूदा सीपीआई शृंखला²⁴ में मार्च 2024 में सबसे कम प्रिंट दर्ज किया गया। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी के कारण ईंधन और बिजली समूह सितंबर 2023 से अपस्फीति में बना हुआ है (चार्ट II.3.1)।

II.3.2 हालांकि 2023-24 में औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति सीमित रही, लेकिन मानक विचलन द्वारा मापी गई अस्थिरता, चरम मौसमी घटनाओं के कारण रुक-रुक कर खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ गई (सारणी II.3.1)।

II.3.3 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में वैश्विक मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मूल्यांकन दिया गया है। उप-



खंड 3 भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उप-खण्ड 4 में इसके प्राथमिक घटकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। उप-खंड 5 में कीमतों और लागत के अन्य संकेतकों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

सारणी II.3.1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
माध्य	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5	6.7	5.4
मानक विचलन	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9	0.7	0.9
स्क्यूनेस	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1	-0.1	1.5
कर्टोसिस	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0	-0.6	1.6
माध्यिका	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6	6.7	5.1
अधिकतम	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0	7.8	7.4
न्यूनतम	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2	5.7	4.3

टिप्पणी: स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दरों का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना की गयी वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकती है।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

²³ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) [आधार वर्ष: 2012=100] में वर्ष-दर-वर्ष बदलाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है।

²⁴ मुद्रास्फीति आगे अप्रैल 2024 में अनुकूल रही।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति परिदृश्य

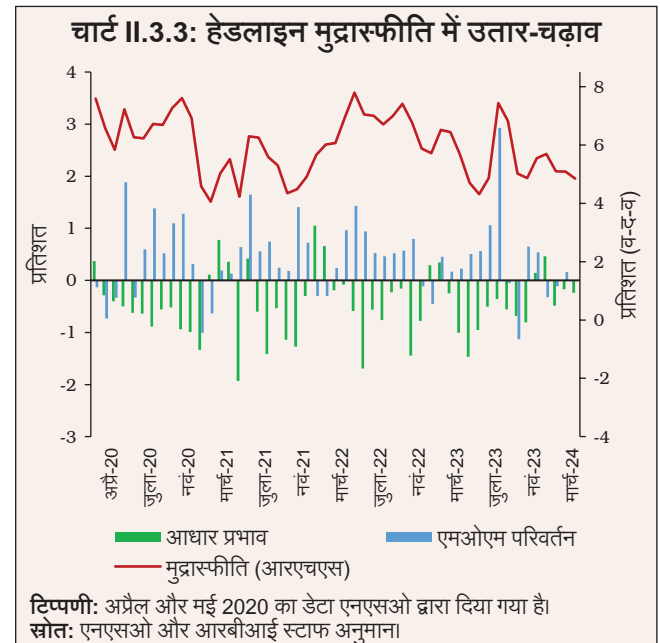
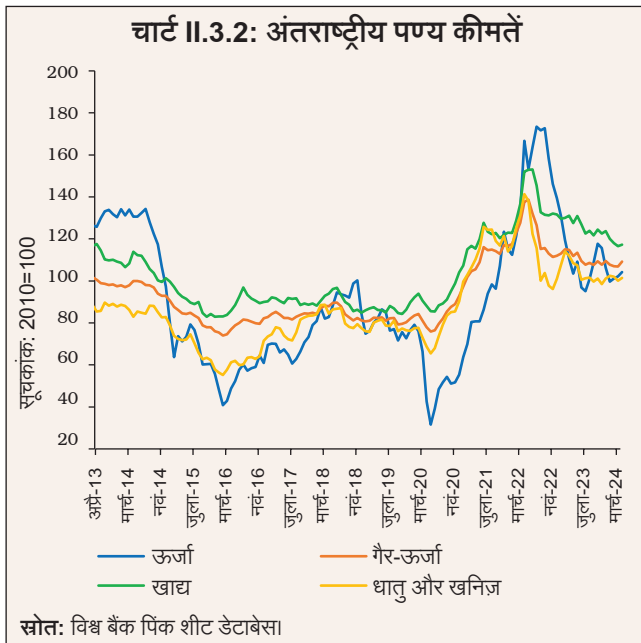
II.3.4 वैश्विक स्तर पर, मुद्रास्फीति 2022 में अपने बहु-दशक शिखर से 2023 में कम हो गई, लेकिन यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उनके लक्ष्य और पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर रही। मजबूत और समकालिक मौद्रिक नीति को सख्त बनाने, आपूर्ति शृंखलाओं को सामान्य बनाने और वैश्विक ऊर्जा और खाद्य कीमतों में नरमी ने मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण लाने में मदद की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 6.8 प्रतिशत हो गई, हालांकि यह 2010-19²⁵ के दौरान 3.5 प्रतिशत के औसत से ऊपर रही।

II.3.5 विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक (चार्ट II.3.2) के अनुसार, प्रमुख पण्य में, 2023-24 के दौरान ऊर्जा की कीमतों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी आई। जबकि ओपेक+ देशों द्वारा उत्पादन में कटौती जारी रखने से कच्चे तेल की कीमतों पर विपरीत दबाव पड़ा, लेकिन वैश्विक मांग में कमी और

गैर-ओपेक+ आपूर्ति में वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई। कमजोर चीनी और यूरोपीय मांग के कारण 2023-24 में धातु की कीमतों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई। अच्छी फसल से आपूर्ति में सुधार के कारण अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, आपूर्ति-मांग के अंतर के कारण चावल और चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती घटनाएं और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

3. भारत में मुद्रास्फीति

II.3.6 भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2023 में पूरे वर्ष के न्यूनतम 4.3 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2023 में 7.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। अक्टूबर में यह घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन दिसंबर और फिर 5.7 प्रतिशत तक बढ़ गई। मार्च 2024 में कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गया, जो खाद्य कीमतों में अस्थिरता को दर्शाता है (चार्ट II.3.3)। मुद्रास्फीति के प्रति



²⁵ विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024, आईएमएफ।

संवेदनशील कृषि वस्तुओं के संबंध में लक्षित हस्तक्षेप, स्टॉक सीमा और सक्रिय व्यापार नीति पहल सहित आपूर्ति पक्ष के उपायों ने मूल्य दबाव को कम करने में मदद की। मौद्रिक सख्ती, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार और इनपुट लागत दबाव में

सुधार से मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी आई। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) के बाद की अवधि में मुख्य मुद्रास्फीति पर आघात का प्रभाव काफी कम हो गया है, जो मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के अनुरूप स्थिरता का संकेत देता है (बॉक्स II.3.1)।

बॉक्स II.3.1

भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता

मौसमी रूप से समायोजित त्रैमासिक हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति प्रदर्शनों का अनुमान वृद्धि की अवधि में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिगमन-आधारित घटना अध्ययन ढांचे में विलंबित मुद्रास्फीति और विलंबित वृद्धि घटना डमी के एक प्रकार्य के रूप में किया जाता है (ब्लैको एट एल, 2022)। वृद्धि की घटनाओं को दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रसार के 90वें प्रतिशत तक की सीमा स्तर से ऊपर या वितरण के दाएं मान में मुद्रास्फीति में परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है (चार्ट 1)।

घटना की अवधि का चयन मुद्रास्फीति वृद्धि को उनके पूर्व-वृद्धि स्तर तक पहुंचने में लगने वाले औसत समय (तिमाहियों की संख्या) पर आधारित होता है। मुद्रास्फीति पथ की गतिशीलता का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:

$$y_{i,t} = \alpha_i + \sum_{j=0}^J \beta_j y_{i,t-1-j} + \sum_{k=-K_1}^{K_2} \gamma_k D_{i,t-k} + \varepsilon_{it} \quad \dots(1)$$

जहां $y_{i,t}$ वी अवधि में मौसमी रूप से समायोजित त्रैमासिक मुद्रास्फीति दर (हेडलाइन या मुख्य) है, $D_{i,t-k}$ डमी वैरिएबल है जो मुद्रास्फीति वृद्धि अंतर (t) की शुरुआत में मान 1 लेता है और 0 अन्यथा और,

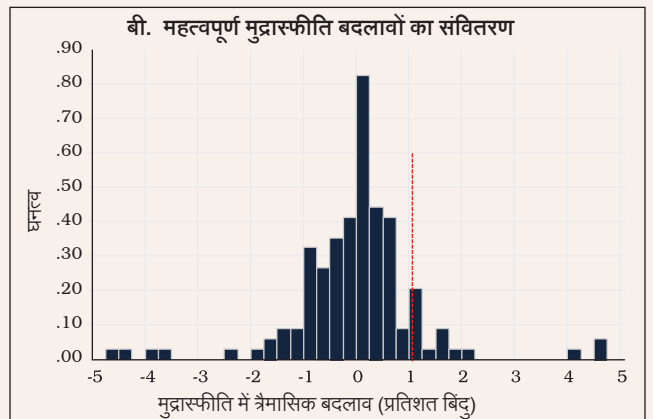
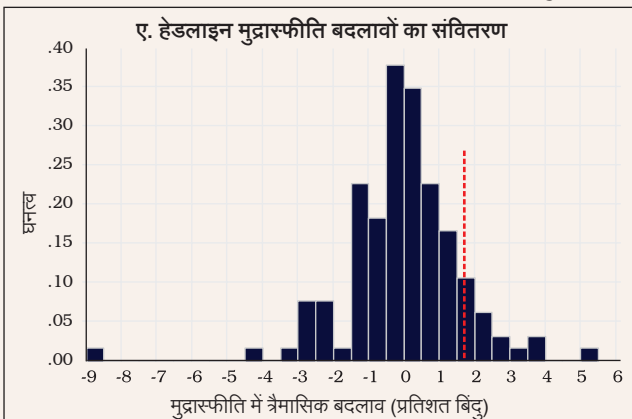
ε_{it} यादृच्छिक त्रुटि शब्द है। J और K क्रमशः मुद्रास्फीति अंतराल और घटना के अंतराल हैं। K_1 और K_2 घटना की अवधि की शुरुआत और अंत हैं।

अनुमानित गुणांक $\hat{\beta}_j$ and $\hat{\gamma}_k$ से क्रमशः विलंबित मुद्रास्फीति और विलंबित डमी से प्राप्त औसत मुद्रास्फीति पथ का अनुमान इस प्रकार है:

$$\hat{y}_t = \sum_{k=-K_1}^{\min(t-1, K_2)} \prod_{j=0}^{\min(t-2-k, J)} \hat{\beta}_j \hat{\gamma}_k, \text{ for } t \geq -K_1 + 1 \quad \dots(2)$$

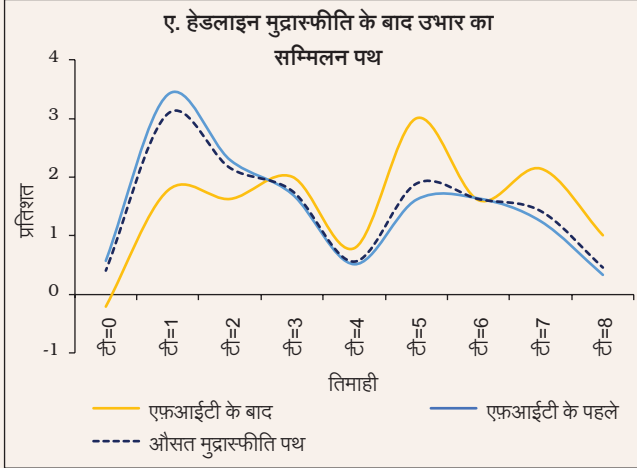
अंतर-देशीय साक्ष्य से पता चलता है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि लगातार बनी हुई है, लेकिन अवस्फीति की अवधि मुद्रास्फीति वृद्धि के चरण से अधिक है (ब्लैको एट एल 2022; एरी एट अल 2023)। भारत में, मुख्य मुद्रास्फीति को किसी भी अतिव्यापी आघात के अभाव में अपने पूर्व-उछाल स्तर पर लौटने में औसतन एक वर्ष लगता है; हालाँकि, खाद्य मुद्रास्फीति (चार्ट 2 ए और 2 बी) में अस्थिरता के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति का इसके पूर्व-आघात स्तर तक प्रसार बाधित है। पूर्व-एफआईटी (1995-2016) और एफआईटी के बाद (2017-2023) अवधियों का अलग-अलग विश्लेषण, विशेष रूप से मुख्य मुद्रास्फीति के

चार्ट 1 : मुद्रास्फीति संवितरण (1995 -2023)

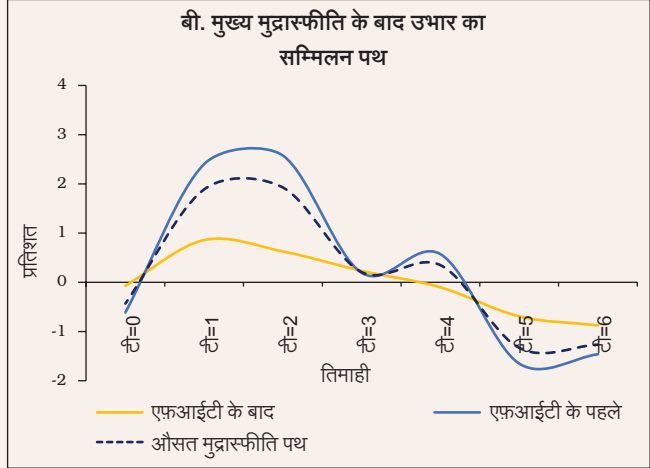


टिप्पणी: लाल रेखा मुद्रास्फीति में परिवर्तन के प्रसार का 90वां प्रतिशत दर्शाती है।
 स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)



स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



लिए, प्रसार के पैटर्न में बदलाव का संकेत देता है। जबकि संरचनात्मक कारकों और नीति प्रसार अंतराल के कारण संतुलन में वापस आने की समय-सीमा समान रहती है, मुख्य मुद्रास्फीति में उछाल पूर्व-एफआईटी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। यह स्थिर मुद्रास्फीति अनुमानों की ओर इशारा करता है। इस प्रकार, विश्वसनीय और समय पर कार्यान्वित की गई मौद्रिक नीति आकार और अवधि दोनों के संदर्भ में मुद्रास्फीति पर आघात के प्रभाव को नियंत्रित कर सकती है।

11.3.7 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्रमुख वाहक बनी रही, हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान एक साल पहले के 46 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान 60.3 प्रतिशत हो गया। वर्षा के असमान स्थानिक और अल्पकालिक वितरण और चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की क्षति हुई और प्रमुख कृषि पण्य के उत्पादन में

सन्दर्भ:

1. एरी ए., सी. एम-ग्रेनाडोस, वी मायलोनास, एल रत्नोवस्की, और डब्ल्यू झाओ (2023), 'वन हंड्रेड इन्फ्लेशन शॉक्स: सेवन स्टाइलिज्ड फैक्ट्स', आईएमएफ वर्किंग पेपर डबल्यूपी/23/190।
2. ब्लैंको ए., पी. ओटोनेलो और टी. रानोसोवा (2022), 'द डायनेमिक्स ऑफ लार्ज इन्फ्लेशन सर्जेज', एनबीईआर वर्किंग पेपर सीरीज, नं. 30555।

कमी आई। सब्जियों की कीमतों में बार-बार आघात, गेहूं के कम स्टॉक और दालों और मसालों के उत्पादन में गिरावट के कारण, खाद्य मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी रही। राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति पर आपूर्ति के दबाव का प्रभाव राज्य की सीमाओं के बाहर उनके प्रभाव विस्तार का आकलन प्रदान करता है (बॉक्स 11.3.2)।

बॉक्स 11.3.2

भारत की स्थानिक संयोजकता और उप-राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की गतिशीलता: घटनाओं का आकलन

राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मार्क-अप को कम करके परिवहन और व्यापार लागत को आसान बनाती है। आपूर्ति आघात के स्थानिक संचरण और सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव का विश्लेषण निम्नलिखित रूप के विषम स्थानिक ऑटो रिग्रेशन (एसएआर) मॉडल के माध्यम से किया जाता है:

$$\pi_{it} = \rho_i \sum_j w_{ij} \pi_{jt} + \theta_{1i} Shock_{it} + \epsilon_{it} \quad \dots(A)$$

जहां π_{it} यह वर्ष t में राज्य i के लिए मुद्रास्फीति है। आपूर्ति का आघात राज्य स्तर पर सामान्य²⁶ से पूर्ण वर्षा विचलन द्वारा अनुमानित है और w_{ij} राज्यों i और j ($w_{ii} = 0$)²⁷ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या द्वारा मापा गया पंक्ति-सामान्यीकृत स्थानिक लिंकेज है। मॉडल का अनुमान 2013-24 के दौरान 27 राज्यों में वार्षिक सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा का उपयोग करके विषम गुणांक (एक्वारो एट एला, 2021) के साथ समीकरणों की एक प्रणाली के रूप में लगाया गया है। यह देखा गया है कि

²⁶ पूर्ण वर्षा विचलन सामान्य वर्षा के सापेक्ष वर्षा की स्थिति को दर्शाता है। उच्च विचलन उच्च कमी या अधिक वर्षा का संकेत देते हैं, जो दोनों कृषि उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं।

²⁷ बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़े राज्य के लिए $i, w_{ij} > 0$ अधिकांश j के लिए जहां $j \neq i$.

सारणी 1 : मुद्रास्फीति²⁸ में स्थानिक भिन्नताओं पर आपूर्ति आघात का प्रभाव

मॉडल →	(1)	(2)	(3)	(4)
	पूर्ण अवधि सैंपल (2013-24)		कोविड के पूर्व (2013-19)	
1	2	3	4	5
स्थानिक स्वसंबंध	0.715*** (0.072)	0.725*** (0.077)	0.701*** (0.059)	0.710*** (0.059)
पूर्ण वर्षा विचलन	0.021*** (0.010)	0.020*** (0.010)	0.029*** (0.011)	0.029*** (0.011)

*** 1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाता है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक आधारित त्रुटियां हैं जिनका अनुमान एकवारो ईटी एल(2021) द्वारा सुझाए गए तटस्थ व्युत्पत्ति का उपयोग करके किया गया है। गुणांक औसत प्रभाव, राज्यों पर लिया गया औसत दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

राज्यों के बीच सकारात्मक और महत्वपूर्ण स्थानिक स्व-सहसंबंध है, जो परिवहन संबद्धता माध्यम से आपूर्ति दबावों के प्रसार का संकेत देता है। अधिक वर्षा विचलन से खाद्य मुद्रास्फीति पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाता है (सारणी 1)।

स्थानिक ढांचे का उपयोग करते हुए, वर्षा के दबावों के कुल प्रभाव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव (पेस और लेसेज, 2009) में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य-स्तरीय वर्षा विचलन के कारण मुद्रास्फीति पर राज्य-वार प्रभाव को दर्शाता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव परिवहन नेटवर्क के माध्यम से अन्य राज्यों में वर्षा के दबावों के प्रसार के कारण दूसरे दौर के प्रभाव को दर्शाता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्षा विचलन का प्रत्यक्ष प्रभाव औसतन खाद्य मुद्रास्फीति पर सकारात्मक

और महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष प्रभाव कुल प्रभाव का 75 प्रतिशत है जो राज्यों के बीच मजबूत परिवहन कनेक्टिविटी का संकेत देता है (सारणी 2)।

अप्रत्यक्ष योगदान में स्थानिक-अस्थायी भिन्नताओं को हीटमैप (चार्ट 1) में शामिल किया गया है। अधिकांश राज्यों में कुल खाद्य मुद्रास्फीति में अप्रत्यक्ष प्रभाव²⁹ का योगदान अधिक है, जो आपूर्ति प्रबंधन में सड़क बुनियादी ढांचे की भूमिका को रेखांकित करता है।

निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि आपूर्ति संबंधी आघात जोकि खाद्य मूल्य दबाव को उत्पन्न करते हैं, खराब कनेक्टिविटी वाले दूर-दराज के राज्यों में बढ़ सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्यों में व्यापार लागत का दबाव कम होता है।

सारणी 2: मुद्रास्फीति पर वर्षा के आघात का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव

मॉडल →	(1)	(2)	(3)	(4)
	पूर्ण अवधि सैंपल (2013-24)		कोविड के पूर्व (2013-19)	
1	2	3	4	5
प्रत्यक्ष प्रभाव	0.045*** (0.010)	0.047*** (0.010)	0.041*** (0.012)	0.044*** (0.012)
अप्रत्यक्ष प्रभाव	0.128*** (0.024)	0.131*** (0.025)	0.121*** (0.023)	0.122*** (0.023)
कुल प्रभाव में प्रत्यक्ष प्रभाव का हिस्सा (प्रतिशत)	27.01	27.50	25.31	26.51

*** 1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाता है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बूटस्ट्रैप का उपयोग करके अनुमानित मानक आधारित त्रुटियां हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)

²⁸ विशिष्टताएँ (2) और (4) राज्य-स्तरीय वर्षा में उच्च भिन्नता के कारण विंसोराइज्ड वर्षा विचलन मूल्यों का उपयोग करती हैं। विशिष्टताएँ (1) और (3) सटीक वर्षा विचलन का उपयोग करती हैं।

²⁹ योगदान को कुल प्रभाव में अप्रत्यक्ष प्रभाव के हिस्से के रूप में प्राप्त किया जाता है। कुछ वर्षों में कम अप्रत्यक्ष प्रभाव उन वर्षों में उच्च प्रत्यक्ष प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है।

चार्ट 1: राज्य और समय सीमा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव का योगदान

वर्ष	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल
2013-14	0.61	0.15	0.12	0.31	0.46	0.12	0.40	0.28	0.16	0.46	0.51	0.12	0.26	0.12	0.12	0.17	0.12	0.48	0.51	0.34	0.12	0.68	0.16	0.89	0.12	0.12
2014-15	0.30	0.89	0.90	0.77	0.65	0.55	0.12	0.63	0.47	0.20	0.62	0.47	0.81	0.12	0.12	0.23	0.12	0.73	0.12	0.89	0.53	0.84	0.21	0.34	0.48	0.78
2015-16	0.86	0.83	0.87	0.65	0.51	0.89	0.46	0.49	0.39	0.79	0.40	0.80	0.22	0.57	0.12	0.25	0.12	0.61	0.84	0.69	0.58	0.57	0.89	0.12	0.65	0.77
2016-17	0.62	0.12	0.83	0.72	0.79	0.22	0.87	0.90	0.86	0.71	0.12	0.43	0.51	0.15	0.17	0.84	0.49	0.86	0.15	0.87	0.90	0.64	0.88	0.14	0.50	0.87
2017-18	0.21	0.82	0.18	0.54	0.12	0.12	0.12	0.57	0.12	0.52	0.89	0.12	0.90	0.13	0.19	0.16	0.12	0.37	0.12	0.12	0.75	0.16	0.14	0.15	0.25	0.41
2018-19	0.53	0.52	0.12	0.59	0.85	0.59	0.17	0.78	0.29	0.86	0.13	0.90	0.90	0.24	0.19	0.25	0.16	0.39	0.59	0.14	0.25	0.38	0.54	0.67	0.90	0.89
2019-20	0.56	0.17	0.88	0.67	0.15	0.12	0.45	0.34	0.53	0.14	0.69	0.45	0.84	0.15	0.12	0.37	0.53	0.66	0.31	0.61	0.24	0.72	0.30	0.64	0.50	0.81
2020-21	0.12	0.81	0.28	0.89	0.90	0.12	0.74	0.38	0.12	0.33	0.24	0.24	0.12	0.12	0.44	0.32	0.18	0.90	0.61	0.41	0.12	0.36	0.26	0.55	0.12	0.12
2021-22	0.64	0.15	0.82	0.86	0.86	0.90	0.12	0.89	0.84	0.77	0.18	0.90	0.52	0.31	0.33	0.41	0.21	0.87	0.67	0.36	0.69	0.42	0.66	0.67	0.89	0.36
2022-23	0.62	0.67	0.21	0.12	0.46	0.40	0.85	0.81	0.89	0.90	0.68	0.75	0.19	0.47	0.51	0.46	0.25	0.86	0.42	0.74	0.15	0.88	0.90	0.58	0.87	0.34
2023-24	0.63	0.65	0.25	0.10	0.51	0.51	0.80	0.82	0.87	0.82	0.65	0.72	0.25	0.45	0.55	0.52	0.22	0.81	0.40	0.70	0.21	0.83	0.86	0.61	0.85	0.37

टिप्पणी: नीला अप्रत्यक्ष प्रभाव के उच्च योगदान को दर्शाता है, जबकि लाल कम योगदान को दर्शाता है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

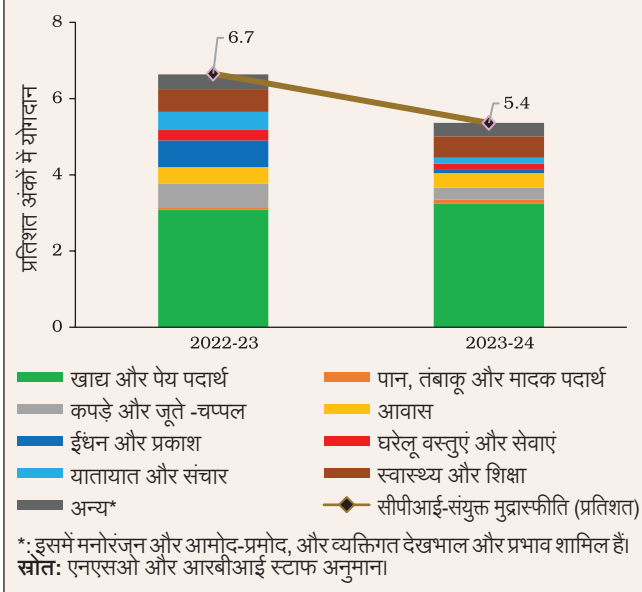
सन्दर्भ:

1. आर्मिगटन, पी. (1969), 'ए थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर डिमांड डिस्टिगुइश्ड बाय प्लेस ऑफ प्रोडक्शन', इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ पेपर्स, वाशिंगटन डीसी, 159-78।
2. डियरडॉर्फ, ए. (2004), लोकल कम्पेरिटिव एडवांटेज: ट्रेड कॉस्ट एंड द पैटर्न ऑफ द ट्रेड', मिशिगन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र चर्चा पत्र में अनुसंधान संगोष्ठी, मिशिगन विश्वविद्यालय, एन आर्बरा।
3. लेसेज, जे. और रॉबर्ट के.पी. (2009), इन्ट्रोडक्सन टू स्पेशियल इकनोमेट्रीस, सीआरसी प्रेस, न्यूयॉर्क, जनवरी।
4. एक्वारो, एम., नतालिया बी., और हाशेम पी.एम. (2021), एस्टिमेशन एंड इन्फेरेंस फॉर स्पेशियल मॉडल्स विद हीट्रोजीनस कोईफ़ीसीएंटस : एन अप्लीकेशन टू यूएस हाउस प्राइसेस, एप्लाइड इकनोमेट्रिक्स जर्नल, 36 (1), 18-44.

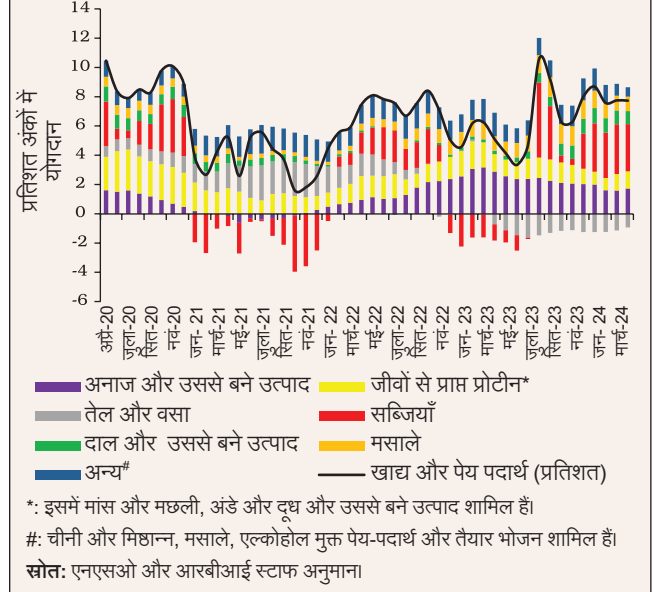
II.3.8 ईंधन और विद्युत समूह में मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान औसतन 1.2 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले के 10.3 प्रतिशत से काफी कम है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में सुधार के कारण तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन की कीमतों में कमी के बाद सितंबर 2023 से इस समूह में साल-दर-साल कीमतें अपस्फीति में चली गईं। हालाँकि, कई राज्यों में टैरिफ बढ़ोतरी के कारण बिजली की कीमत मुद्रास्फीति बढ़कर औसतन 9.7 प्रतिशत हो गई।

II.3.9 2023-24 के दौरान, मुख्य मुद्रास्फीति एक साल पहले के 6.1 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, क्योंकि सितंबर-मार्च के दौरान व्यापक आधार पर अवस्फीति ने गति पकड़ी। यह सहजता घरेलू सामान, कपड़े और जूते की कीमतों, और व्यक्तिगत देखभाल और वस्तुओं पर प्रभाव (सोने और चांदी को छोड़कर) और घर का किराया, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और सेवा पक्ष में परिवहन किराए की कीमतों से उत्पन्न थी। कुल मिलाकर, 2023-24 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति गिरकर 5.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल

चार्ट II.3.4: मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



चार्ट II.3.5: खाद्य मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



पहले की तुलना में 129 आधार अंक (बीपीएस) कम है (परिशिष्ट सारणी 4)।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

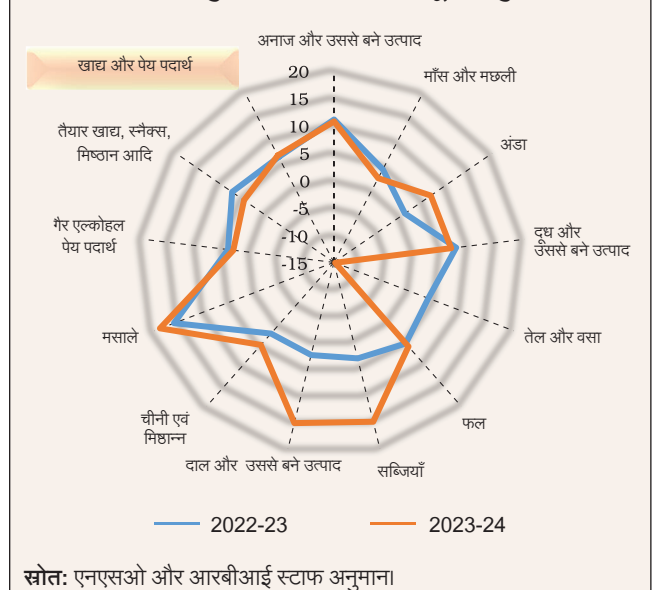
II.3.10 2023-24 के दौरान, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों से प्रभावित थी, इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, आवास तथा कपड़े और जूते -चप्पल आदि का स्थान था (चार्ट II.3.4)

खाद्य

II.3.11 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति (भारांक: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) 2023-24 में 3.3 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत की विस्तृत सीमा में रही। अनाज, मसालों, दालों और पशु प्रोटीन में लगातार मूल्य दबाव, सब्जियों, मुख्य रूप से टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जोकि खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख वाहक थे (चार्ट II.3.5)। हालाँकि, वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में नरमी के कारण तेल और वसा पूरे वर्ष अपस्फीति में रहे।

II.3.12 खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति 2023-24 में औसतन 7.0 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले के 6.7 प्रतिशत से अधिक है। खाद्य समूह के भीतर, छह उप-समूहों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि शेष छह उप-समूहों में यह कम हुई (चार्ट II.3.6)। दालों और मसालों (संयुक्त भार: सीपीआई-

चार्ट II.3.6: प्रमुख खाद्यान्न उप-समूह में मुद्रास्फीति

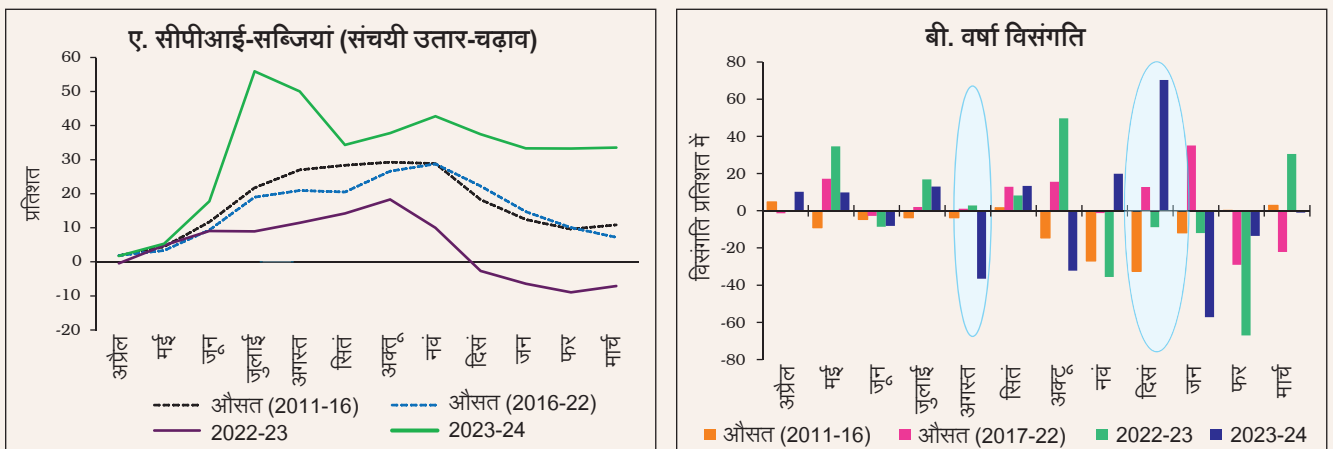


खाद्य और पेय पदार्थों में 10.6 प्रतिशत) में क्रमशः 15.2 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत की दोहरे अंक की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। जुलाई 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 10.6 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जनवरी 2020 के बाद सबसे अधिक है।

11.3.13 नवंबर 2022-जून 2023 के दौरान अपस्फीति में रहने के बाद, फसलों की क्षति और आपूर्ति में व्यवधान के कारण जुलाई 2023 में सब्जियों की कीमतें (खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 13.2 प्रतिशत का भार) 37.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गईं। देश के उत्तरी भागों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) के साथ-साथ गैर-टॉप सब्जियों (चार्ट 11.3.7ए और 11.3.7बी) की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। आपूर्ति की स्थिति के धीरे-धीरे सामान्य होने और ताजा फसल की आवक में बढ़ोतरी से सब्जियों की मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में 2.8 प्रतिशत तक कम हो गई। नवंबर 2023 में प्याज और टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ गैर-टॉप सब्जियों की कीमतों में और प्रतिकूल आधार पर वृद्धि हुई। प्रभावों के कारण मार्च 2024 में सब्जियों की मुद्रास्फीति 28.3 प्रतिशत तक फिर से बढ़ गई।

11.3.14 ताजा रबी फसल से बाजार में मजबूत आवक के कारण अप्रैल-मई 2023 के दौरान माह-दर-माह आधार पर प्याज की कीमतों में गिरावट आई। हालाँकि, प्याज की कीमतें जून 2023 में बढ़ीं और कम उत्पादन के कारण नवंबर तक दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई [2022-23 के अंतिम अनुमान (एफई) की तुलना में पहले अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, 2023-24 में 15.7 प्रतिशत की गिरावट]। प्याज की कीमतों में मौसमी उछाल अगस्त में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण बढ़ गया था, जिसके परिणामस्वरूप फसल खराब हो गई। रबी स्टॉक की कम उपलब्धता के बीच खरीफ प्याज की कटाई में देरी के कारण कीमतों पर दबाव बढ़ गया, जिससे नवंबर 2023 में साल-दर-साल मुद्रास्फीति 86.3 प्रतिशत हो गई। मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने बहु-आयामी उपायों का सहारा लिया: 2022-23 में प्याज के बफर स्टॉक में 2.5 एलएमटी से 2023-24 में 7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की वृद्धि; खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से स्टॉक का निपटान; विभिन्न चैनलों के माध्यम से सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री; 29 अक्टूबर, 2023 से 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम

चार्ट 11.3.7: सीपीआई-सब्जी कीमतों और वर्षा विसंगति में मौसमी प्रभाव



टिप्पणी: चार्ट बी के लिए, वर्षा विचलन को 50-वर्षीय औसत (1971 से 2020) से विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है; औसत वर्षा के आंकड़े कैलेंडर वर्ष पर आधारित होते हैं।
स्रोत: एनएसओ, एन्वीस्टेट्स इंडिया 2023, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू करना; और 8 दिसंबर 2023³⁰ से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध आदि इसमें शामिल हैं। इन उपायों और ताजा फसल की आवक के कारण, दिसंबर 2023-फरवरी 2024 के दौरान प्याज की कीमतों में संचयी रूप से लगभग 58 प्रतिशत की गिरावट आई।

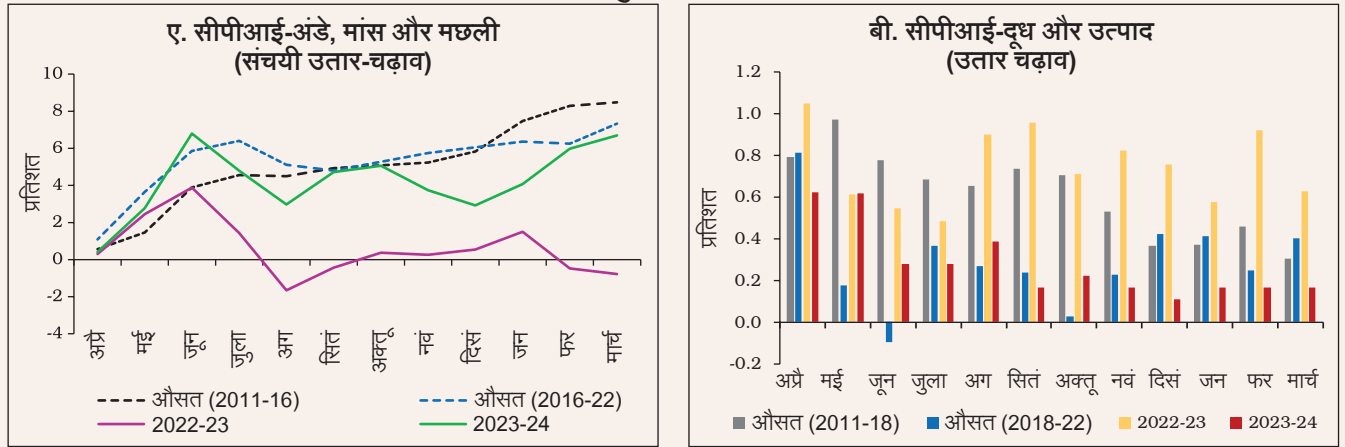
11.3.15 टमाटर की कीमतों में 2023-24 में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। विशेष रूप से उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण फसल क्षति और आपूर्ति में और कर्नाटक में कीटों के हमले के कारण जुलाई में इस श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़कर 202.1 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई शृंखला में सबसे अधिक है। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर के दौरान नई फसल की आवक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। प्रमुख उत्पादक राज्यों में अत्यधिक/बेमौसम वर्षा के कारण नवंबर 2023 में टमाटर की कीमतें फिर से बढ़ गईं। कुल मिलाकर, कम उत्पादन के कारण आपूर्ति में गिरावट [2022-23 में (-)1.3 प्रतिशत] ने मूल्य दबाव में योगदान दिया। टमाटर की कीमतों में अगस्त-अक्टूबर 2023 में और उसके बाद दिसंबर 2023-जनवरी 2024 में उच्च उत्पादन (2022-23 एफई की तुलना में 2023-24 प्रथम एई में 1.9 प्रतिशत) के कारण सुधार हुआ। दूसरी ओर, अधिक उत्पादन (2022-23 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि) के कारण फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक आलू की कीमतें अपस्फीति में रहीं। हालाँकि, फरवरी 2024 में आलू की मुद्रास्फीति सकारात्मक हो गई और 2023-24 में कम उत्पादन [2022-23 से अधिक (-) 1.9 प्रतिशत] और प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण मार्च 2024 में 41 प्रतिशत तक पहुंच गई। बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के कारण जुलाई में अदरक, लहसुन, फूलगोभी, पत्तागोभी, बैंगन और हरी मिर्च जैसी सब्जियों की कीमतों में भी

उच्च दबाव देखा गया। गैर-टीओपी सब्जियों में असामान्य रूप से उच्च संचयी मूल्य गति ने जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ताजा फसल की आवक के साथ, बाद के महीनों में इन सब्जियों की कीमतों में सुधार हुआ, हालांकि उच्च न्यून तापमान के कारण यह नवंबर-दिसंबर 2023 में सामान्य से कम रहा।

11.3.16 अनाज और उत्पादों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21 प्रतिशत का भार) अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान द्वि-अंकीय वृद्धि हुई, जो चावल और गेहूं की कीमतों से प्रेरित थी। फरवरी 2023 में अत्यधिक तापमान, मार्च 2023 में बेमौसम बारिश और कम स्टॉक स्तर की वजह से कम उत्पादन के कारण गेहूं की कीमतों में वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ की फसल के कम उत्पादन के साथ वर्ष 2023-24 में कम आवक के कारण अक्टूबर 2022 से चावल की कीमतों में द्वि-अंकीय मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। घरेलू आपूर्ति में सुधार और अनाज में मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में मुक्त-बाजार-बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत बिक्री के लिए 101.5 एलएमटी गेहूं और 25 एलएमटी चावल के आवंटन सहित विभिन्न उपाय किए जैसे कि भुजिया (उबला) चावल पर निर्यात शुल्क लगाना; गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध; गेहूं पर स्टॉक सीमा; सस्ती दरों पर बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए सब्सिडी वाले मूल्यों पर 'भारत' ब्रांड आटा और चावल की खुदरा बिक्री शुरू करना; इथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरियों को सब्सिडी वाले चावल के विपथन पर प्रतिबंध लगाना आदि। मार्च 2024 में अनाज की मुद्रास्फीति घटकर 8.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें गेहूं/आटा 4.7 प्रतिशत था। हालांकि चावल की मुद्रास्फीति 12.7 प्रतिशत के उच्च

³⁰ 4 मई, 2024 को, सरकार ने 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के एमईपी के अधीन प्याज की निर्यात नीति को 'प्रतिबंध' से 'मुक्त' कर दिया।

चार्ट II.3.8: सीपीआई – पशु प्रोटीन: कीमतों में मौसमी परिवर्तन

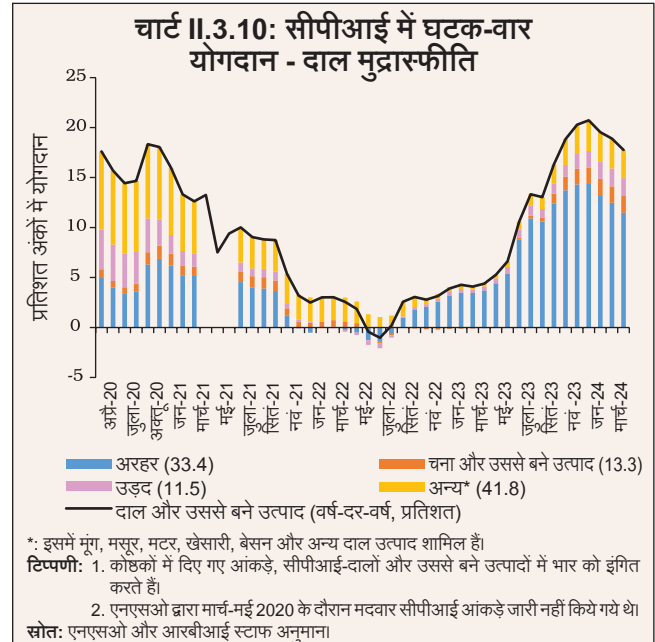
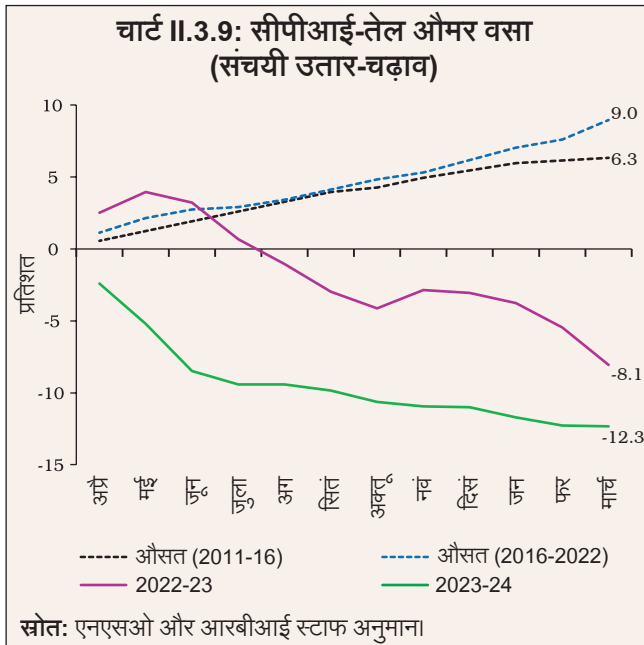


स्तर पर बनी हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) को जनवरी 2024 से पांच साल के लिये बढ़ा दिया है।

II.3.17 अंडे, मांस और मछली (जिनका सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत का भारांक है) जैसी पशु-प्रोटीन युक्त वस्तुओं की कीमतों में मई-जून 2023 के दौरान गर्मी की वजह से में वृद्धि देखी गई, जिससे दक्षिणी भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अंडे का उत्पादन और कुक्कुटपालन में उपज को प्रभावित किया (चार्ट II.3.8ए)। जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान श्रावण-मास के कारण मांग में गिरावट के कहलते बाद में मूल्य-दबाव कम हो गए। हालांकि, मूल्य-दबाव फिर से उभरे विशेष रूप से सितंबर 2023 से अंडे के मामले में, जो मौसमी मांग और उच्च निर्यात को दर्शाता है। अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 2023-24 के दौरान दूध और पण्यों की कीमतों में मुद्रास्फीति कम हो गई, प्रमुख दूध सहकारी समितियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि नहीं हुई, और 2023 (मार्च-मई) के शुरुआती भाग में बेमौसम बारिश के बाद गर्मियों की देरी से शुरुआत के कारण दूध और उत्पादों (जैसे आइस्क्रीम, दही और छाछ) की चरम मांग कम हो गई। इसके अलावा, वैश्विक

डेयरी कीमतों ने निर्यात को हतोत्साहित किया, जिससे मक्खन और घी जैसे दुग्ध-वसा की घरेलू आपूर्ति अधिक हो गई। बेहतर घरेलू उपलब्धता के कारण वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में पशु-खाद्य और चारे की लागत कम हो गई। इसके अलावा, जैसे-जैसे डेयरी क्षेत्र 2022 के गांठदार-त्वचा-रोग के प्रकोप से उबर गया और उत्पादन में सुधार हुआ, दूध की कीमत बढ़ने लगीं। (चार्ट II.3.8बी)।

II.3.18 तेल और वसा की कीमतें (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का योगदान) 2023-24 के दौरान दोहरे अंक की अपस्फीति में थीं, जो 2022-23 के दौरान तिलहन के अधिक घरेलू उत्पादन (8.9 प्रतिशत तक), अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और प्रमुख खाद्य तेलों पर कम आयात शुल्क (चार्ट II.3.9) के कारण औसतन (-) 14.8 प्रतिशत थी। 2023-24 में तिलहनों का कम खरीफ़ उत्पादन [(-) 2022-23 एफई की तुलना में 2023-24 द्वितीय एई के अनुसार 12.7 प्रतिशत] के कारण कुछ तिलहन (जैसे सरसों और मूंगफली तेल) में दबाव पड़ा। सरकार ने 15 जून 2023 को रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। कच्चे पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन पर कम आयात शुल्क संरचना मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई थी। घी और मक्खन की मुद्रास्फीति



कम हो गई जोकि दूध की कीमत में नरमी और अनुकूल आधार प्रभाव को दर्शाता है।

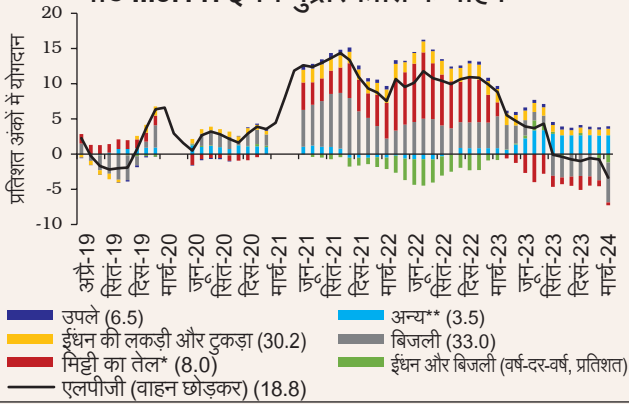
II.3.19 वर्ष के दौरान दालों की कीमतों में मुद्रास्फीति (जिनका सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का योगदान है) लगातार बढ़ी, जो वर्ष 2023-24 में औसतन 15.2 प्रतिशत थी (चार्ट II.3.10)। वर्ष 2022-23 के साथ ही खरीफ 2023-24 सीजन (अर्थात् उड़द और मूंग) में दालों के कम उत्पादन [2022-23 एफई की तुलना में 2023-24 द्वितीय अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार (-) 6.6 प्रतिशत] ने कीमतों पर दबाव डाला। घरेलू उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, जैसे कि 'मुक्त श्रेणी' के तहत तुअर और उड़द के आयात को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया; न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) प्रतिबंध के बिना, चने के निकटतम विकल्प, पीली मटर का मुक्त आयात अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया; 31 दिसंबर, 2023 तक तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगाई गई; अधिक बुआई रकबे को प्रोत्साहित करने के लिए 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर के लिए 40 प्रतिशत की खरीद सीमा

हटा दी गई; तुअर को राष्ट्रीय बफर से अंशांकित तरीके से जारी किया गया; और 'भारत दाल' ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री को प्राथमिकता प्रदान किया।

II.3.20 फलों की कीमतों में मुद्रास्फीति (जिनका सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भारांक है) अप्रैल-जून 2023 में भी कम रही, जिसे उच्च उत्पादन (2021-22 एफई की तुलना में 2022-23 बागवानी एफई के अनुसार 2.5 प्रतिशत) द्वारा समर्थन मिला। हालांकि, जुलाई 2023 से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ ने सेब के बागानों को नुकसान पहुंचाया और आपूर्ति में व्यवधान पैदा किया। मजबूत उत्पादन के कारण जून-सितंबर के दौरान केले में मुद्रास्फीति मध्यम रही, जो कि इसके बाद उत्पादक क्षेत्र में आपूर्ति बाधाओं के साथ-साथ उच्च त्योहारी मांग के कारण दिसंबर 2023 में 16.6 प्रतिशत तक सख्त हो गई। वर्ष 2023-24 में उच्च उत्पादन (2022-23 की तुलना में 1.7 प्रतिशत) के कारण जनवरी 2024 से फलों की मुद्रास्फीति कम हो गई।

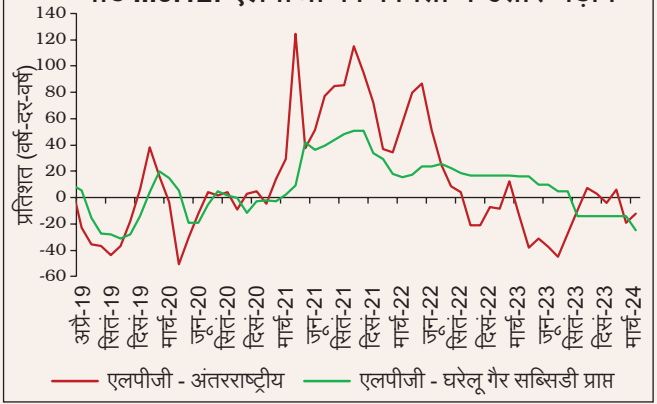
II.3.21 अन्य खाद्य वस्तुओं में, मसालों में द्वि-अंकीय मुद्रास्फीति बनी रही (2023-24 के दौरान औसतन 18.9

चार्ट II.3.11: ईंधन मुद्रास्फीति के वाहक



*: इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल और अन्य स्रोतों से प्राप्त मिट्टी का तेल शामिल है।
 **: इसमें डीजल, कोक, कोयला, काठकोयला और अन्य ईंधन शामिल हैं।
टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई-ईंधन और बिजली के भार को दर्शाते हैं।
 2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़े जारी नहीं किये गये थे।
 3. घरेलू गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतें चार मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई कोलकाता और चेन्नई) में कीमतों का औसत हैं।
स्रोत: एनएसओ, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.3.12: एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव



प्रतिशत), मुख्य रूप से जीरा (क्युमिन) द्वारा संचालित - जिसने प्रतिकूल मौसम की स्थिति और स्थिर उत्पादन के कारण जुलाई-दिसंबर 2023 के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की। सितंबर 2023 में जीरे की कीमतों में मासिक गति तेजी से गिर गई और दिसंबर 2023 से नकारात्मक हो गई, जो खेती के तहत उच्च रकबे को दर्शाती है और इसके परिणामस्वरूप 2023-24 में उच्च उत्पादन (2022-23 के दौरान 49 प्रतिशत) हुआ। वर्ष के दौरान सूखी मिर्च में मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में 27.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 3.7 प्रतिशत हो गई।

ईंधन

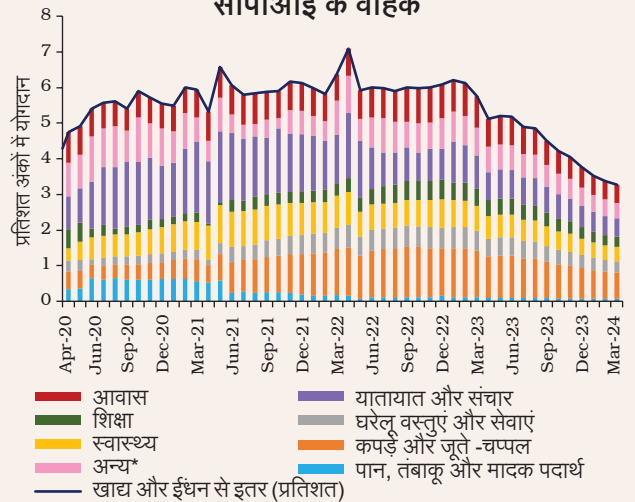
II.3.22 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत का भारांक) का योगदान 2023-24 में घटकर 1.6 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 10.5 प्रतिशत था। केरोसिन और एलपीजी मूल्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण ईंधन मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 10.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में (-) 3.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.3.11)। दिनांक 30 अगस्त, 2023 को एलपीजी की कीमतों में ₹200 प्रति घरेलू सिलेंडर की कटौती ने सितंबर 2023 से देखी गई अपस्फीति को कम किया (चार्ट II.3.12)। 8 मार्च, 2024 को एलपीजी की

कीमत में 100 रुपये प्रति घरेलू सिलेंडर की कटौती की घोषणा की गई।

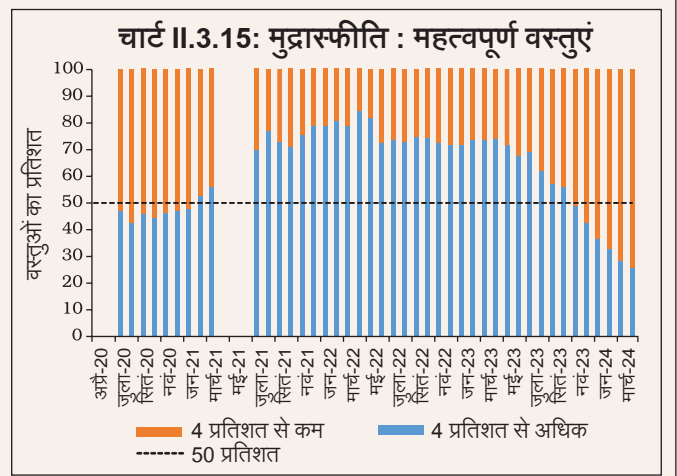
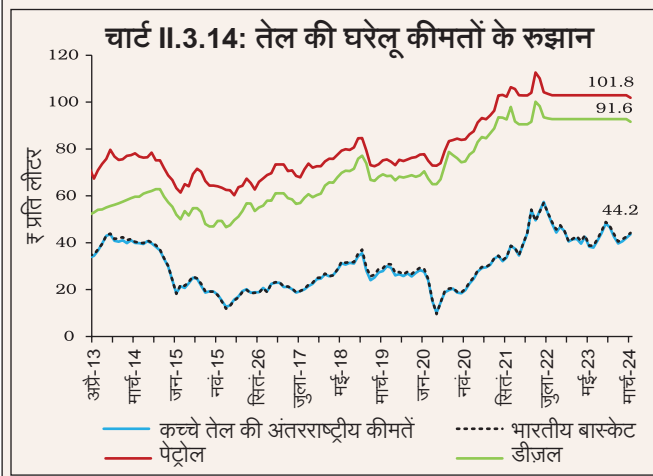
मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति)

II.3.23 अस्थिर खाद्य और ईंधन वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति, यानी, मुख्य मुद्रास्फीति, एक साल पहले के 6.1 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 4.3 प्रतिशत हो गई, जिसमें वस्तु और सेवा मुद्रास्फीति दोनों में नरमी शामिल है (चार्ट II.3.13)।

चार्ट II.3.13: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के वाहक



*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ द्वारा दिए गए हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



टिप्पणी: 1. कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।
2. मार्च-मई 2020 के दौरान एनएसओ द्वारा वस्तुगत सीपीआई डेटा जारी नहीं किया गया था।
स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.3.24 कोर सीपीआई के प्रमुख घटकों में से, कपड़े और जूते में मुद्रास्फीति कम हो गई, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में तेजी और कपड़ा और पहनने के परिधान के लिए कमजोर निर्यात मांग को दर्शाती है। मार्च 2024 में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होकर 2.7 प्रतिशत हो गई। अगस्त 2022 (चार्ट II.3.14) के बाद से बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों और परिवहन किराए में कमी को दर्शाते हुए, परिवहन और संचार कीमतों में मुद्रास्फीति 2023-24 में एक साल पहले की 5.9 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गई। दिसंबर 2022-अगस्त 2023 के दौरान 6 प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद, स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो गई क्योंकि महामारी से प्रेरित स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कम हो गई और चिकित्सा आपूर्ति सामान्य हो गई। मार्च 2024 में लगभग 75 प्रतिशत मुख्य सीपीआई वस्तुओं में 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जो व्यापक आधार पर नरमी का संकेत देती है (चार्ट II.3.15)।

II.3.25 आवास मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में 4.9 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2024 में 2.7 प्रतिशत हो गई। निवल आवास मुद्रास्फीति, भोजन और ईंधन को छोड़कर 2023-24 में औसतन 4.4 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले के 6.6 प्रतिशत से काफी कम रही।

II.3.26 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति 2023-24 में मामूली रूप से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 7.6 प्रतिशत थी, यह मुख्य रूप से युद्ध-प्रेरित सेफ-हेवेन मांग के कारण अंतरराष्ट्रीय मूल्य आंदोलनों के कारण सोने की ऊंची कीमतों से प्रेरित रही।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.3.27 क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान औसतन 5.3 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.1 प्रतिशत थी। कृषि मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान औसत से अधिक क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत पर रही, जो मुख्य रूप से बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित रही।

II.3.28 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अप्रैल-अक्टूबर 2023-24 के दौरान अपस्फीति में रहा और उसके बाद थोड़ा सकारात्मक हो गया, जिसका कारण नवंबर में सब्जियों, विशेष रूप से प्याज और टमाटर की कीमतों में तेज वृद्धि और दिसंबर में प्रतिकूल आधार प्रभाव रहा। वर्ष के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति के सामान्य होने और

वैश्विक मांग में मंदी के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में सुधार को प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से ऊर्जा, खाद्य और धातुओं में। कुल मिलाकर, 2023-24 के दौरान डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति औसत (-) 0.7 प्रतिशत रही (एक साल पहले 9.4 प्रतिशत की तुलना में), जो औसत सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत से काफी कम थी।

11.3.29 निम्न डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति सभी तीन प्रमुख समूहों द्वारा संचालित रही - प्राथमिक वस्तुएं (डबल्यूपीआई टोकरी में 22.6 प्रतिशत का भार); ईंधन और बिजली (13.2 प्रतिशत); और विनिर्मित उत्पाद (64.2 प्रतिशत)। प्राथमिक वस्तु डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से गैर-खाद्य वस्तुओं और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अपस्फीति को दर्शाती है, जो कि वैश्विक कीमतों में कमी के अनुरूप है, जबकि वर्ष के दौरान असमान और कम वर्षा के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव आया। इसके विपरीत, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में कमी के अनुरूप ईंधन और बिजली में 2023-24 के दौरान औसतन (-) 4.5 प्रतिशत (एक साल पहले 28.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मुकाबले) लगातार अपस्फीति दर्ज की गई। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी ने विनिर्मित उत्पादों की कीमतों को 2023-24 के दौरान औसतन (-) 1.7 प्रतिशत (एक साल पहले 5.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मुकाबले) अपस्फीति में रखा। यह मुख्यतः विनिर्मित खाद्य उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रसायनों और वस्त्रों की कीमतों के कारण था। डबल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति दोनों में नरमी को दर्शाते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डिफ्लेटर मुद्रास्फीति 2022-23 की इसी अवधि में 8.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में 1.1 प्रतिशत हो गई।

11.3.30 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीफ फसलों के लिए 5.3-10.4 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 2.0-7.1 प्रतिशत की सीमा में बढ़ाया गया। खरीफ फसलों में मूंग के एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि रबी फसलों में मसूर की दाल और गेहूँ के लिए सबसे अधिक वृद्धि हुई।

11.3.31 अप्रैल-फरवरी 2023-24 में सांकेतिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि औसतन 6.0 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह 5.4 प्रतिशत थी, जिसमें कृषि और गैर-कृषि मजदूरी वृद्धि दोनों 6 प्रतिशत के करीब रही। मुख्य रूप से कृषि मजदूरों की श्रेणी में जुताई, बागवानी और पैकेजिंग में तथा गैर-कृषि मजदूरों की श्रेणी में बीड़ी निर्माताओं और बांस/बेंत की टोकरी बुनकरों में मंदी होने कारण अक्टूबर से विकास की गति कम हुई है।

6. निष्कर्ष

11.3.32 संक्षेप में, खाद्य मूल्य के ओवरलैपिंग आघातों के बावजूद, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 में कम हुई। यह नरमी निरंतर मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति रुख, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सुधार का परिणाम रही। कोर मुद्रास्फीति ने जून 2023 से व्यापक आधार पर अवस्फीति प्रदर्शित की और 2023 के अंत तक 4 प्रतिशत से नीचे चली गई। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023-24 (जुलाई-अगस्त को छोड़कर) में सहनशीलता बैंड में रही, यह मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रहा। लंबे समय से चली आ रही भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक गतिविधियों के कारण नए सिरे से आपूर्ति शृंखला दबाव, निचले जलाशय स्तर और प्रमुख फसलों के उत्पादन में गिरावट से आगे चलकर मुख्य मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा हो गया है।

II.4 मुद्रा एवं ऋण

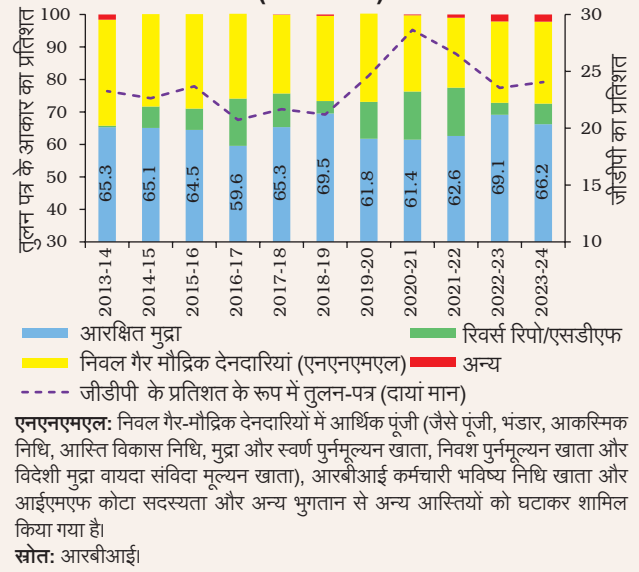
II.4.1 वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप मौद्रिक और ऋण स्थितियों की स्थितियाँ बनीं जिससे घरेलू आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिला। ₹2000 के बैंक-नोटों का आहरण (मई 2023), बैंक के साथ गैर-बैंक का विलय (जुलाई 2023) और वृद्धिशील नकद-आरक्षित-अनुपात (आई-सीआरआर)³¹ [अगस्त 2023] के अस्थायी अधिरोपण ने वर्ष 2023-24 के दौरान उपर्युक्त स्थितियों के विकास को प्रभावित किया। बैंकिंग प्रणाली में ₹2000 रुपये के बैंक-नोटों के एक प्रमुख हिस्से की जमाराशियों के रूप में वापसी से आरक्षित मुद्रा और संचलनगत-मुद्रा का प्रसार कम हो गया। इन बैंक नोटों की वापसी और सावधि जमा दरों में वृद्धि ने कुल जमा और व्यापक मुद्रा (एम₃) में तेजी लाने में योगदान दिया। बैंक ऋण ने वर्ष 2023-24 में द्वि-अंकीय संधारणीय वृद्धि प्रदर्शित की। बैंकों ने ऋण-जमा अंतर को पाटने के लिए जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाए।

II.4.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 आरक्षित धन की गतिशीलता और भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में बदलाव पर प्रकाश डालता है। इसके बाद, उप-खंड 3 और 4 में क्रमशः, निष्कर्षों टिप्पणियों के साथ, मुद्रा-आपूर्ति और बैंक-ऋण गतिविधियों की समीक्षा की गई है।

2. आरक्षित मुद्रा³²

II.4.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम) केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में मौद्रिक देयताओं की मात्रा को दर्शाती है (चार्ट II.4.1)। प्रतिवर्ती रेपो/स्थायी-जमा-सुविधा (एसडीएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व

चार्ट II.4.1: रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के घटक (देनदारियाँ)



बैंक में बैंकों की अधिशेष-चलनिधि के साथ, जोखिम बफर और पुर्नमूल्यन खाते [निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों (एनएनएमएल) का बड़ा हिस्सा] तुलन पत्र के अन्य प्रमुख घटक हैं।

II.4.4 रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार, मार्च 2023 के 23.5 प्रतिशत की तुलना में, मार्च 2024 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 24.1 प्रतिशत हो गया। तुलन पत्र अपने महामारी-पूर्व स्तर पर सामान्य हो गया है (चार्ट II.4.2)।

II.4.5 वर्ष 2023-24 के दौरान, आरएम³³ में वृद्धि, एक वर्ष पूर्व के 9.7 प्रतिशत से घटकर, 6.7 प्रतिशत हो गई (उक्त वृद्धि सीआरआर³⁴ में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के अनुसार समायोजित करने पर 7.4 प्रतिशत थी), जो कि इसके 12.9 प्रतिशत के दशकीय औसत³⁵ (2013-14 से 2023-24) से

³¹ आई-सीआरआर के विवरण के लिए अध्याय III देखें।

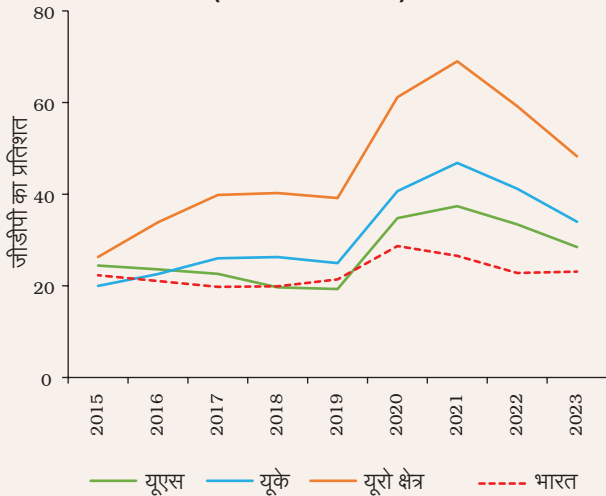
³² उप-खंड 2 में, विकास और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/महीने के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

³³ इसमें संचलनगत मुद्रा, रिज़र्व बैंक में बैंकों की जमाराशि, और और देनदारी पक्ष में रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा शामिल हैं।

³⁴ मई 2022 में सीआरआर को 4.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

³⁵ नोटबंदी के वर्ष 2016-17 को छोड़कर।

चार्ट II.4.2: केंद्रीय बैंक का तुलनपत्र (दिसंबर अंत तक)

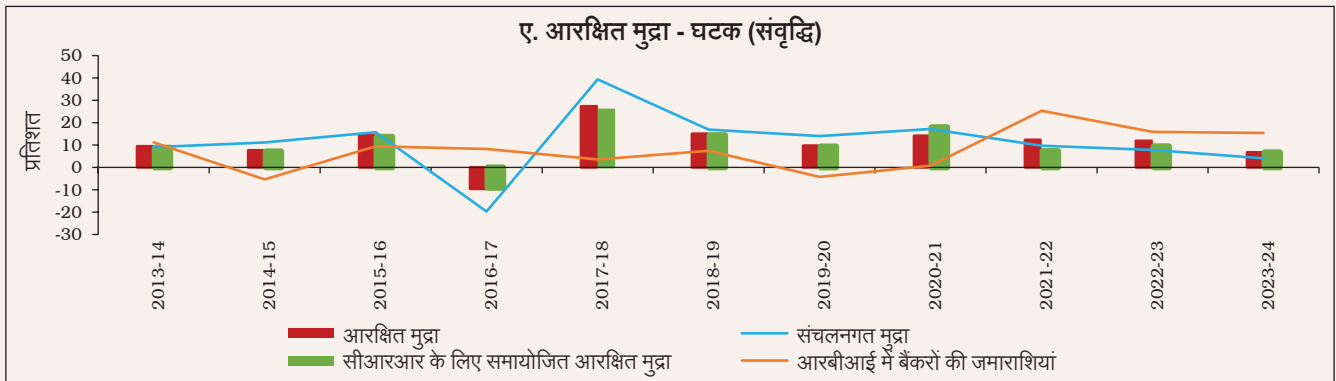


स्रोत: आरबीआई, एफआरडी (सेंट लुइस फेड), बीओई, आईएमएफ, सीआईसी, भारत सरकार तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

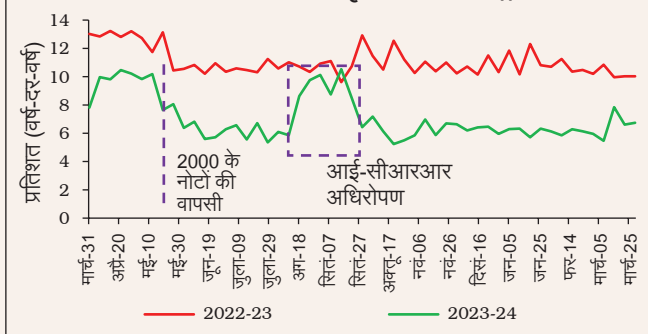
कम है। यह मुख्यतः ₹2000 बैंक-नोटों³⁶ के आहरण के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट II.4.3ए और परिशिष्ट सारणी 4)। आरएम वृद्धि ने अगस्त-अक्टूबर 2023 के दौरान आई-सीआरआर के अस्थायी अधिरोपण के कारण अगस्त 2023 में क्षणिक उछाल दर्ज की (चार्ट II.4.3बी)। ₹2000 बैंकनोट के आहरण के कारण, संचलनगत-मुद्रा(सीआईसी) में वृद्धि – जो 75.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ आरएम का प्रमुख घटक है – वर्ष 2023-24 के दौरान घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो कि एक वर्ष पूर्व 7.8 प्रतिशत थी(चार्ट II.4.3ए और II.4.3सी)।

II.4.6 महामारी की अनिश्चितता और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ मुद्रा-जीडीपी अनुपात कम हो गया है³⁷ खुदरा खंड में भारतीय केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है (चार्ट II.4.4)।

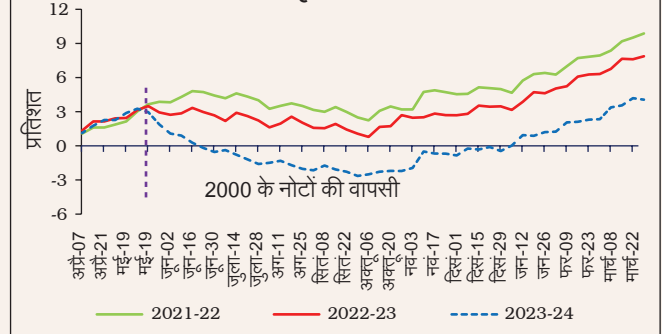
चार्ट II.4.3: आरक्षित मुद्रा- घटक (देनदारियां)



बी. आरएम वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि : सामाहिक ट्रेंड



सी. सीआईसी संवृद्धि : वित्तीय वर्ष में परिवर्तन

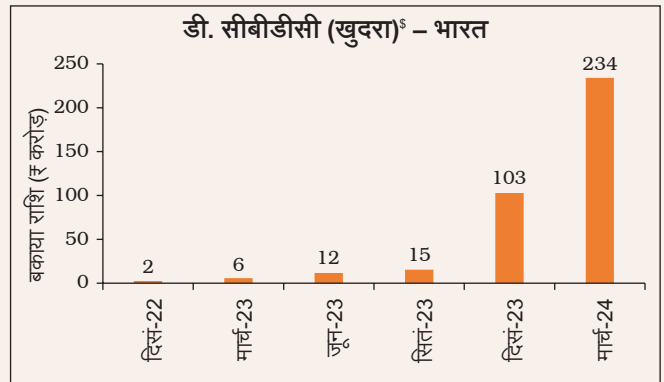
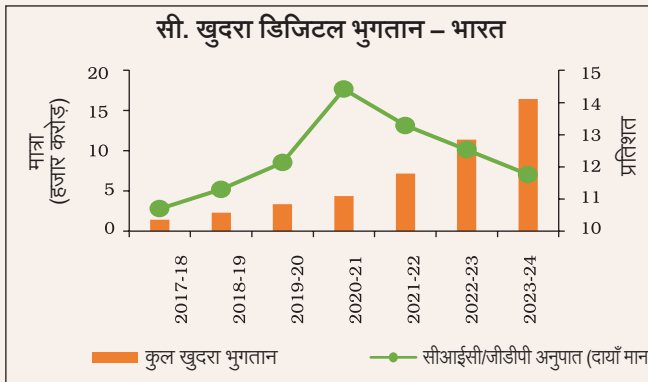
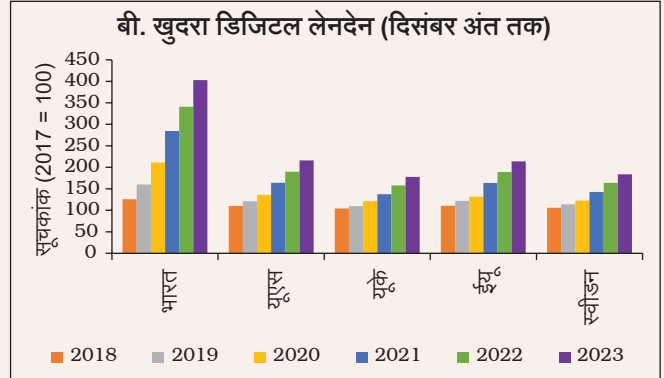
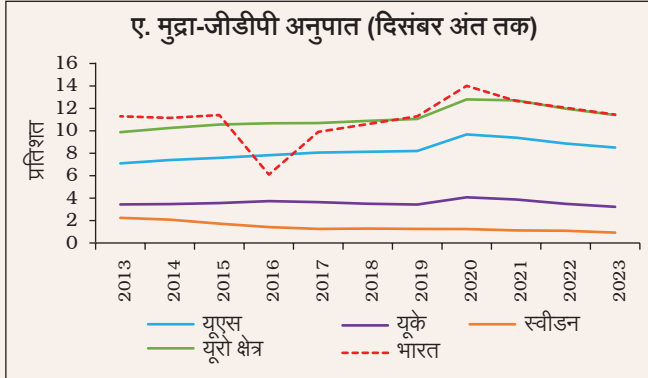


स्रोत: आरबीआई

³⁶ प्रचलन में ₹2000 बैंक-नोटों का कुल मूल्य दिनांक 19 मई, 2023 तक ₹3.56 लाख करोड़ था। दिनांक 29 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 97.69 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिनमें से अधिकांश जमा राशि के रूप में हैं।

³⁷ डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों (सीबीडीसी सहित) का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय VI, VIII और IX में शामिल हैं।

चार्ट : II.4.4: संचलनगत मुद्रा और डिजिटल भुगतान



₹: 01 दिसंबर 2022 को लागू किए गए।

स्रोत: आरबीआई, भारत सरकार, सीआईसी, स्टेटिस्टा, आईएमएफ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.4.7 भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकों की जमा राशि (आरएम में 22.9 प्रतिशत शेयर), अर्थात्, बैंकों द्वारा अपनी सीआरआर आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संधृत जमा-शेष में, वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक-जमा में विस्तार के साथ 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 15.9 प्रतिशत थी (चार्ट II.4.3ए)।

II.4.8 स्रोत पक्ष (आस्तियां) के संदर्भ में, आरएम में भारतीय रिजर्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियाँ (एनडीए)³⁸ और निवल विदेशी आस्तियाँ (एनएफए)³⁹ शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में, आरएम में विस्तार मुख्य रूप से एनएफए द्वारा चालित था,

जिसमें पिछले वर्ष की ₹2.2 लाख करोड़ की निवल बिक्री के मुकाबले अधिकृत डीलरों से ₹3.4 लाख करोड़ की निवल खरीद हुई थी। वर्ष के दौरान एनडीए में गिरावट आई क्योंकि सरकारी नकदी शेष में वृद्धि ने, बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को निवल ऋण में विस्तार की भरपाई से कहीं ज्यादा, सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के निवल दावों को कम कर दिया (चार्ट II.4.5)।

3. मुद्रा आपूर्ति⁴⁰

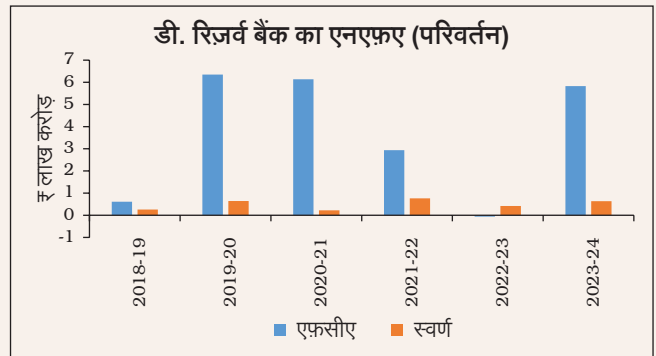
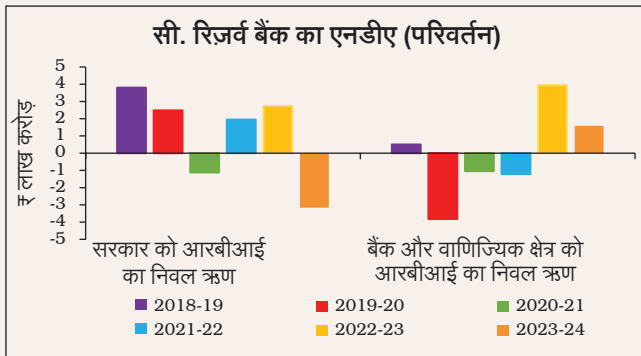
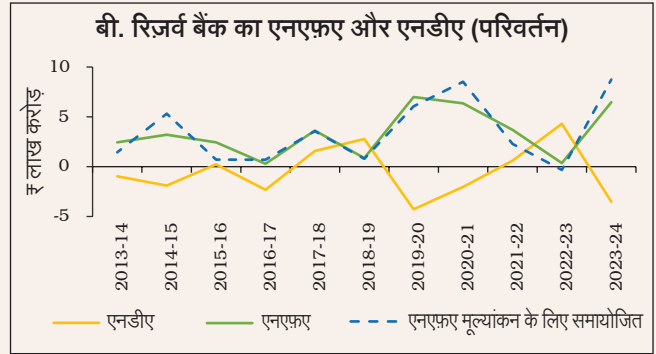
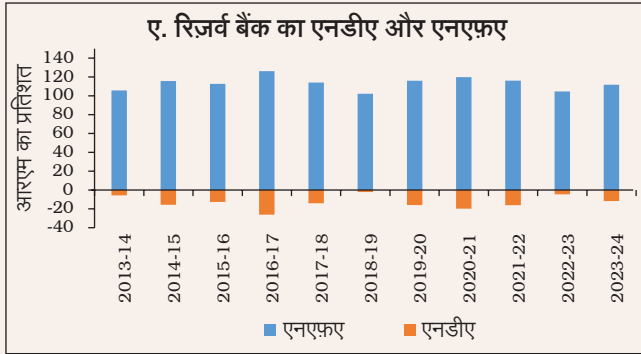
II.4.9 व्यापक मुद्रा (एम₃) के अर्थों में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) और घटकों के संदर्भ (देयताओं) में बैंकों की कुल जमा राशियाँ (एडी) शामिल होती हैं।

³⁸ इसमें बैंकों, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राथमिक डीलरों) को निवल रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण शामिल है।

³⁹ इसमें स्वर्ण विदेशी-मुद्रा-आस्ति (एफसीए) शामिल हैं। एफसीए में भारत सरकार (जीओआई) से हस्तांतरित विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। आईएमएफ में भारत सरकार और रिजर्व ट्रांश पोजीशन (आरटीपी) के साथ शेष एसडीआर होल्डिंग्स, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के अंश-योगदान का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिजर्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं।

⁴⁰ उप-खंड 3 और 4 में, विकास और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं। आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट II.4.5: आरक्षित मुद्रा - स्रोत (आस्तियां)



स्रोत: आरबीआई

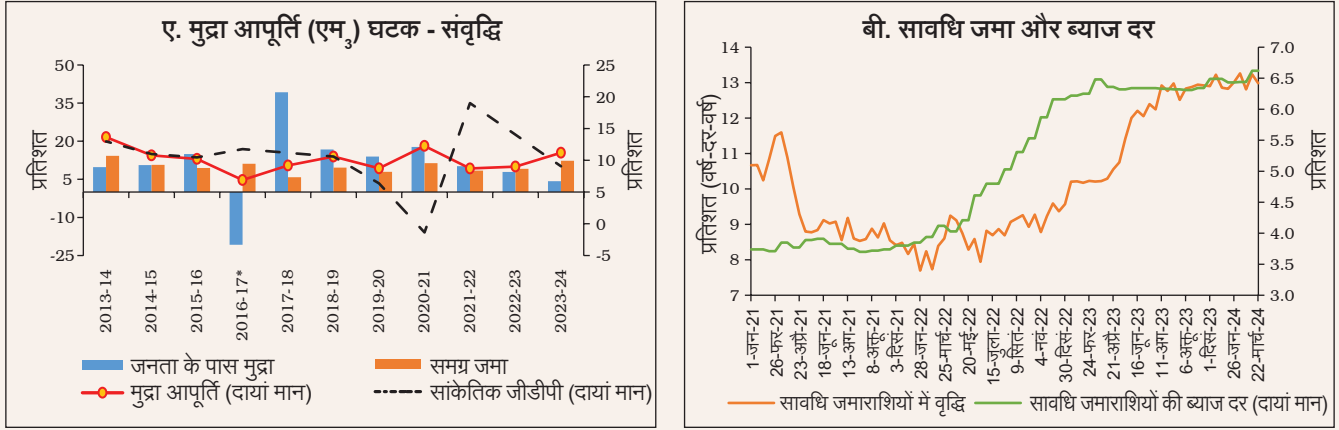
दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार एम₃ ने 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (एक साल पहले 9.0 प्रतिशत) जो मुख्य रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ नीतिगत-दर-वृद्धि के संचरण के कारण उच्च जमा दरों से लाभप्राप्त सावधि-जमा द्वारा चालित थी(चार्ट II.4.6)। बैंक-ऋण की निरंतर मांग ने बैंकों पर अधिक जमाराशि जुटाने के लिए दबाव डाला। लगातार दूसरे वर्ष, बैंक-जमा में विस्तार सीडब्ल्यूपी से अधिक हो गया।⁴¹ एम₃ और जीडीपी का अनुपात अपने महामारी-पूर्व स्तरों पर वापस आ गया है (चार्ट II.4.7)।

II.4.10 स्रोत पक्ष (आस्तियां) के संदर्भ में, एम₃ में हुआ विस्तार मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण द्वारा चालित था, जो वर्ष 2023-24 में 15.6 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व के 14.4 प्रतिशत) तक बढ़ा था। सरकार को निवल बैंक-ऋण का विस्तार 2023-24 में अपने एक वर्ष पूर्व के 11.5 प्रतिशत से घटकर 5.7 प्रतिशत हो गया। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार, एससीबी द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों⁴² की अतिरिक्त धारिताएँ निवल मांग और सावधि देयताओं(एनडीटीएल) का 10.4 प्रतिशत थीं, जबकि एक वर्ष पूर्व उक्त धारिताएँ 11.0 प्रतिशत थीं। बैंकिंग क्षेत्र की निवल

⁴¹ मांग-जमा अस्थिर बने रहे, जो काफी हद तक जनता के साथ मुद्रा में विचलन को दर्शाता है।

⁴² एसएलआर प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए संपादिक बफर प्रदान करती है और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी है। रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल, 2022 से प्रभावी परिपक्वता श्रेणी(एचटीएम) के तहत प्रतिभूतियों को रखने की सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया। एचटीएम सीमा को 31 मार्च, 2025 तक चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत पर बहाल किया जाएगा, जो 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही से शुरू होगा।

चार्ट II.4.6: मुद्रा आपूर्ति एवं एससीबी की सावधि जमाराशियां



*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।
टिप्पणी: एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा के लिए, सावधि जमा ब्याज दरें, भारत औसत घरेलू सावधि जमा दरों को संदर्भित करती हैं।
स्रोत: आरबीआई।

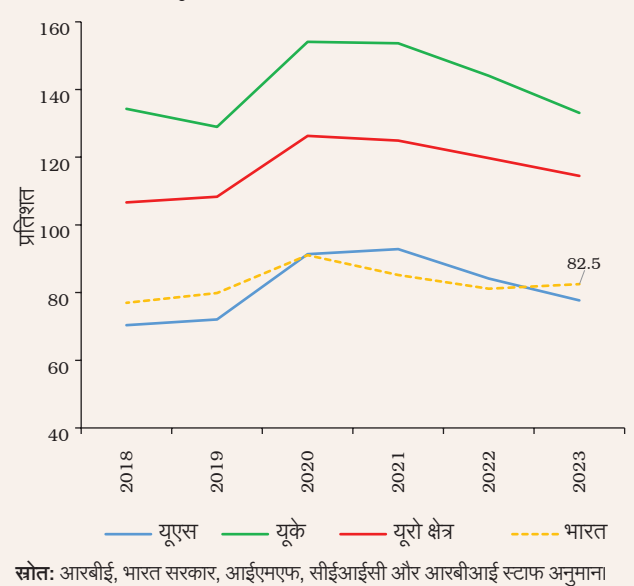
विदेशी आस्तियों में वृद्धि हुई, जो कि वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन पत्र में एनएफए के विस्तार को दर्शाता है (चार्ट II.4.5 और II.4.8; सारणी II.4.1)।

प्रमुख मौद्रिक-अनुपात

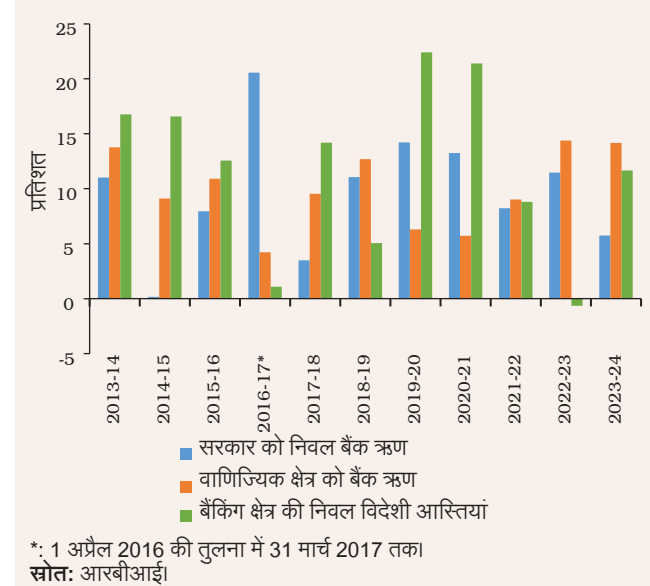
II.4.11 मौद्रिक लेन-देन कि गति, जो सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद को एम₃ से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, स्थिर बनी

हुई है। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार, मुद्रा बहुगुणक(एमएम) 5.4 था, जो अपने दशकीय औसत⁴³ (2013-14 से 2023-24) से थोड़ा अधिक है। मुद्रा-जमा अनुपात वर्ष 2022-23 में 17.3 प्रतिशत से गिरकर 15.9 प्रतिशत हो गया, जो ₹2000 रुपये के बैंक-नोटों के आहरण और जमा के रूप में बैंकिंग प्रणाली में उनकी वापसी को दर्शाता है। प्रतिवर्ती रेपो के लिए समायोजित

चार्ट II.4.7: एम₃ और जीडीपी अनुपात (दिसंबर अंत तक)



चार्ट II.4.8: मुद्रा आपूर्ति स्रोत-संवृद्धि



⁴³ इसमें नोटबंदी का वर्ष 2016-17 शामिल नहीं है।

सारणी II.4.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	22 मार्च 2024 को बकाया (₹ लाख करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24 (22 मार्च, 2024 तक)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	46.8	12.3	9.7	6.7
II. मुद्रा आपूर्ति (एम ₃)	248.3	8.7	9.0	11.2
III. एम₃ के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	34.2	10.2	7.9	4.3
III.2. समग्र जमाराशियां	213.3	8.4	9.1	12.3
IV. एम₃ के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	73.1	8.2	11.5	5.7
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	166.7	9.0	14.4	15.6
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	55.1	8.8	-0.6	11.7
V. मुद्रा बहुगुणक (अनुपात)	5.4			

नोट: 1. आंकड़े अनतिम हैं।

2. आरएम के आंकड़े 29 मार्च 2024 की अवधि के हैं।

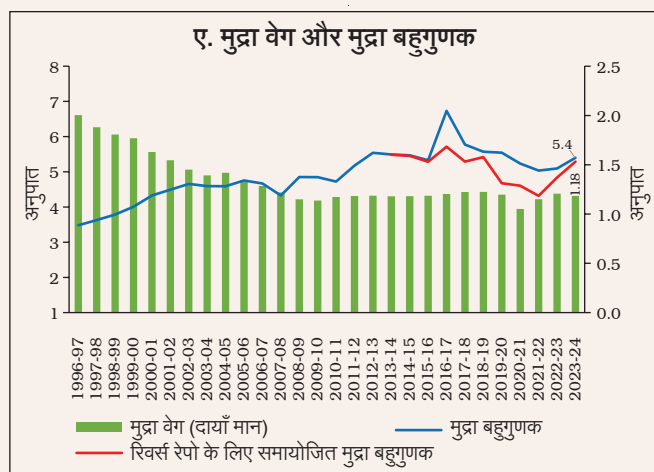
स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा बहुगुणक - विश्लेषणात्मक रूप से केंद्रीय बैंक में बैंक-जमा के समान – दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार एमएम और समायोजित एमएम के अभिसरण के साथ मामूली रूप से कम होकर 5.3 आ गया(चार्ट II.4.9ए)। सीआरआर में कोई बदलाव नहीं होने के कारण आरक्षित-जमा अनुपात स्थिर रहा (चार्ट II.4.9बी)।

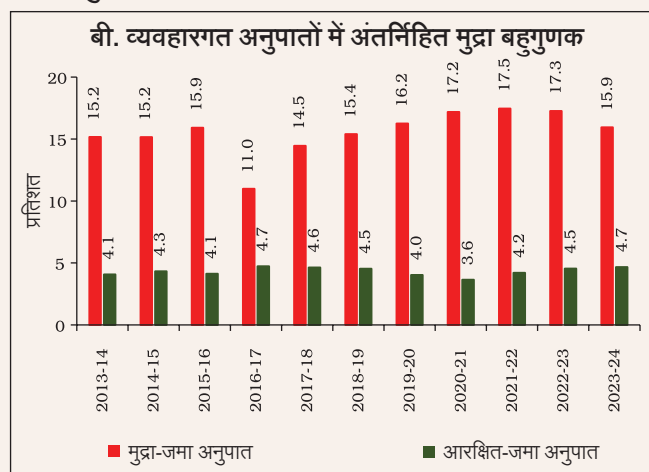
4. ऋण

II.4.12 खुदरा और सेवा क्षेत्रों की मांग के कारण वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण में द्वि-अंकीय वृद्धि बनी रही। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार एससीबी के ऋण में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व 15.0 प्रतिशत थी (चार्ट II.4.10ए)। बैंक समूह-वार, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के

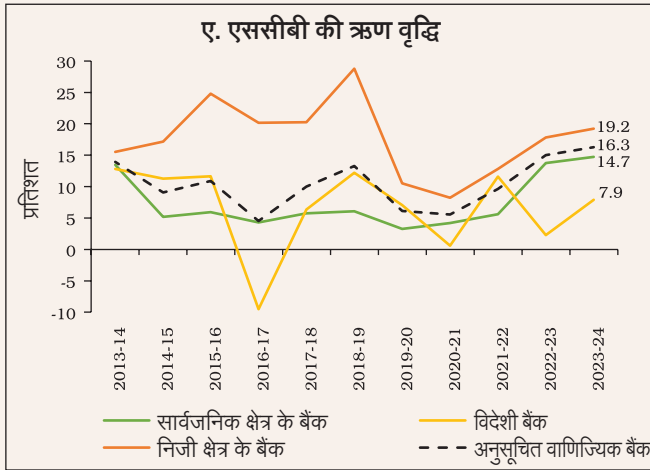
चार्ट II.4.9 : मौद्रिक अनुपात



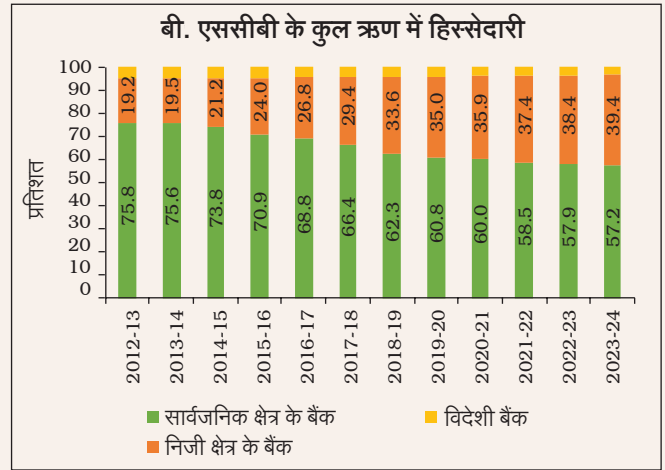
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।



चार्ट II.4.10 : बैंक समूह-वार ऋण



स्रोत: आरबीआई



बैंकों (पीएसबी) से उच्चतर वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार, पीवीबी में संवृद्धि एक वर्ष पूर्व के 17.8 प्रतिशत से बढ़कर 19.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और पीएसबी में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गई। इसके परिणामस्वरूप कुल ऋण में पीएसबी के हिस्से में गिरावट आई, हालांकि ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी पीएसबी का है। (चार्ट II.4.10बी)

II.4.13 क्षेत्रवार⁴⁴ देखें तो, मार्च 2024 में कृषि-क्षेत्र के लिए ऋण में 20.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ (जो कि एक वर्ष पूर्व 15.4 प्रतिशत था)। बड़े उद्योगों में ऋण वृद्धि अपेक्षाकृत कम (6.4 प्रतिशत) थी जिसका कारण आंशिक रूप से उनकी लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में सुधार होना था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के ऋण में 14.1 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई जो कि संपार्श्विक-मुक्त ऋण⁴⁵ की उपलब्धता से समर्थित थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और व्यापार-क्षेत्र की मांग के चलते मार्च 2024 में सेवा क्षेत्र के बैंक ऋण में 20.2 प्रतिशत

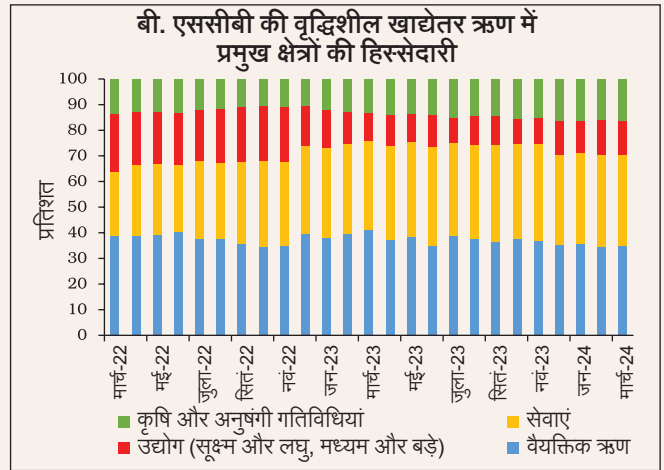
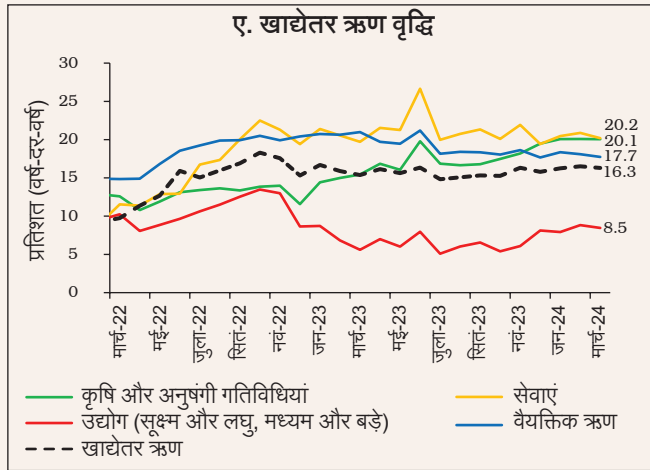
की वृद्धि हुई। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 नवंबर, 2023 को घोषित विनियामकीय उपायों के बाद एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋण की विस्तार-गति कम हुई (अध्याय VI देखें)। मार्च 2024 में निजी-ऋण में 17.7 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई, जो कि आवास ऋण - इस खंड का आधे से अधिक हिस्सा-से समर्थित थी(चार्ट II.4.11 और सारणी II.4.2)।

II.4.14 वर्ष 2023-24 में एससीबी की जमा वृद्धि बैंक-ऋण से कम रही (चार्ट II.4.12ए और II.4.12बी)। इसके परिणामस्वरूप, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात जून 2022-मई 2023 के दौरान 100 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गया (चार्ट II.4.12सी)। तदनंतर, जमा वृद्धि में तेजी के कारण यह अनुपात गिर तो गया, लेकिन ऋण और जमा वृद्धि के बीच की खाई बनी हुई है। निधीयन के उक्त अंतर को पाटने के लिए बैंकों ने सीडी-निर्गम किए जो, पिछले वर्ष के ₹6.4 लाख करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर ₹8.3 लाख करोड़ रुपये हो गए(चार्ट II.4.12डी)।

⁴⁴ गैर-खाद्य ऋण आंकड़े पाक्षिक धारा 42 रिटर्न पर आधारित हैं और सभी एससीबी को शामिल करते हैं। क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक-ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होते हैं, जिसमें, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्से को दर्शाने के लिए चुनिंदा बैंकों के हिसाब शामिल हैं। उक्त आंकड़े महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

⁴⁵ केंद्रीय बजट 2023-24 में, सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना में सुधार की घोषणा की, जिसमें कॉर्पस में ₹9,000 करोड़ का निवेश किया गया ताकि ₹2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण को सक्षम किया जा सके और ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी की जा सके। इसके अलावा, गारंटी के लिए उच्चतर सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।

चार्ट II.4.11 एससीबी की खाद्येतर ऋण वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

II.4.15 सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण फर्मों की कर्ज-चुकौती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, लेकिन न्यून-ऋण-आश्रय

और चलनिधि बफ़र्स का निर्माण कॉर्पोरेट वित्त पर उच्चतर ब्याज दरों के प्रभाव को कम कर सकता है (बॉक्स II.4.1)

सारणी II.4.2: क्षेत्रीय ऋण वृद्धि - एससीबी

(प्रतिशत, वर्ष दर वर्ष)

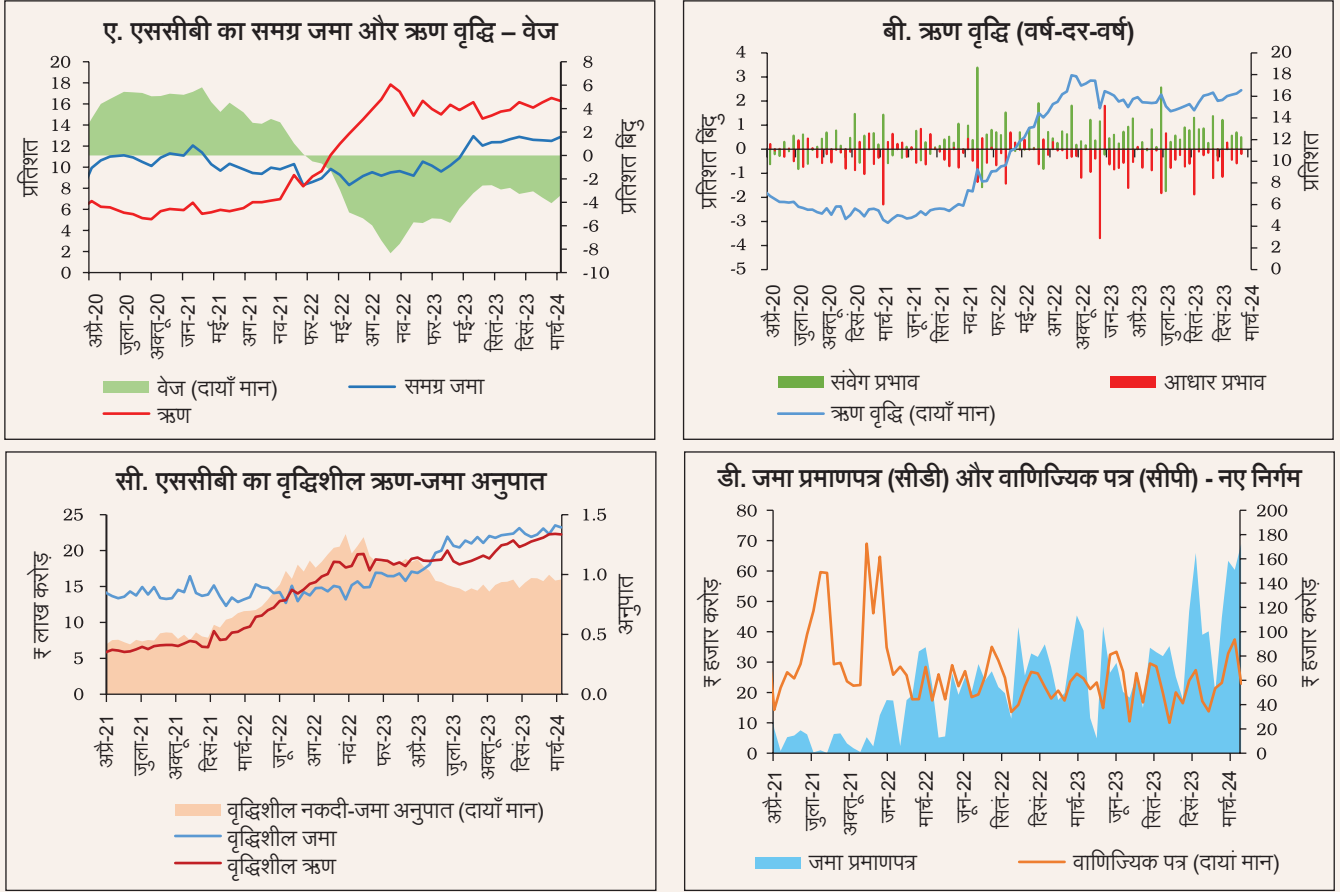
क्षेत्र	2022-23 [#]			2023-24										
	अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्तू	नव	दिसं	जन	फर	मार्च		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
खाद्येतर ऋण	15.4	16.1	15.6	16.3	14.8	15.0	15.3	15.3	16.3	15.8	16.2	16.5	16.3	
I. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	15.4	16.8	16.1	19.8	16.9	16.6	16.8	17.5	18.2	19.5	20.1	20.1	20.1	
II. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	5.6	7.0	6.0	8.0	5.1	6.0	6.6	5.4	6.1	8.1	7.9	8.8	8.5	
II.1. सूक्ष्म और लघु	13.2	9.9	9.8	13.2	10.2	10.8	10.1	16.5	16.8	14.7	16.0	15.1	14.6	
II.2. मध्यम	12.0	11.2	10.4	13.4	9.1	9.3	9.1	12.0	11.9	8.6	9.9	12.7	13.1	
II.3. बड़े	3.1	5.8	4.6	6.1	3.4	4.5	5.4	2.2	3.0	6.4	5.7	6.8	6.4	
II.3.1 इंफ्रास्ट्रक्चर	0.4	3.2	1.9	1.7	0.3	1.0	1.9	-0.1	1.1	4.8	5.0	5.8	5.4	
II.3.2 मूल धातु और धातु उत्पाद	19.6	19.9	17.1	22.0	18.1	18.5	18.6	17.0	17.9	15.0	11.5	11.9	11.4	
II.3.3 रसायन और रसायनिक उत्पाद	10.0	4.9	4.5	6.5	0.2	1.7	2.9	0.4	5.8	9.5	8.9	11.8	11.5	
II.3.4 वस्त्र	1.9	4.3	5.2	8.7	8.4	11.8	12.6	12.7	14.9	13.5	13.6	13.6	10.9	
II.3.5 सभी इंजीनियरिंग	4.3	6.3	5.6	10.5	10.2	9.0	7.4	9.4	9.6	8.5	12.0	11.1	11.2	
II.3.6 खाद्य प्रसंस्करण	5.1	2.4	3.7	5.9	4.1	8.0	8.0	10.6	11.4	10.3	13.5	13.7	14.9	
III. सेवाएं	19.6	21.4	21.1	26.5	19.4	20.6	21.2	19.9	21.7	19.4	20.5	20.9	20.2	
III.1. व्यापार	17.8	18.2	17.4	17.4	16.6	16.0	17.2	19.6	19.6	17.8	18.2	18.1	17.0	
III.2. एनबीएफसी	29.9	28.7	27.3	34.7	19.4	20.9	21.4	17.9	18.5	14.7	15.2	14.4	15.0	
IV. वैयक्तिक ऋण	21.0	19.7	19.5	21.2	17.9	18.4	18.3	18.0	18.6	17.7	18.4	18.1	17.7	
IV.1. आवास	15.2	14.5	14.6	15.0	12.8	13.6	13.7	14.5	15.0	14.4	16.7	16.7	17.4	
IV.2. वाहन ऋण	24.8	23.1	22.3	23.0	21.2	20.7	21.3	20.0	20.8	20.5	16.3	17.5	17.3	

#: मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023।

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है और बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को हटाने के बाद।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.4.12 : एससीबी के जमा एवं ऋण



स्रोत: आरबीआई

बॉक्स II.4.1

भारत में मौद्रिक नीति और गैर-वित्तीय संस्थाएं

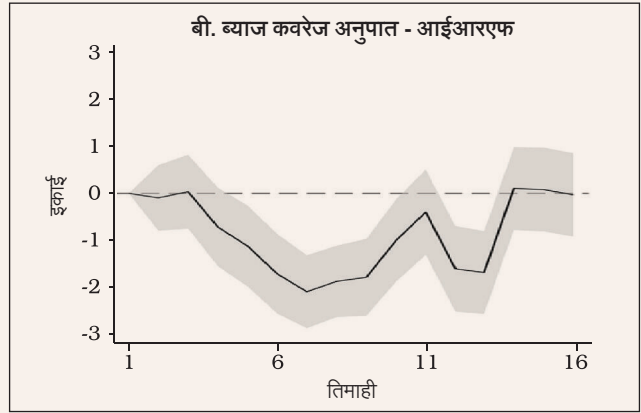
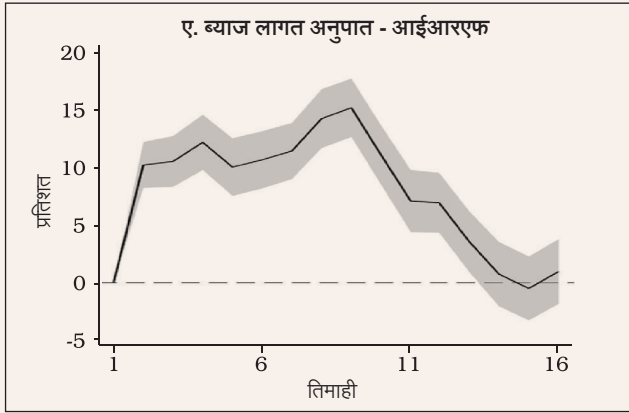
मौद्रिक नीति चक्रों से बनीं वित्तीय स्थितियों वित्त पोषण लागत, कर्ज-चुकौती और गैर-वित्तीय कॉरपोरेट क्षेत्र के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं (शूलरिक और अन्य, 2021; बोइसे और अन्य, 2023)। वर्ष 2010 की पहली तिमाही से वर्ष 2023 की चौथी तिमाही की अवधि के 1,700 सूचीबद्ध भारतीय गैर-वित्तीय फर्मों के लिए सीएमआईई कौशल त्रैमासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, औसत निधीयन लागत पर मौद्रिक नीति में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण स्थानीय रैखिक प्रक्षेपण (एलएलपी) मॉडल फ्रेमवर्क में किया जाता है। यह विश्लेषण, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, और तिमाही और फर्म-निश्चित प्रभावों को स्थिर रखते हुए, ब्याज-व्यय-अनुपात (आईईआर) [कुल ऋण पर सकल ब्याज व्यय] और ब्याज-कवरेज-अनुपात (आईसीआर) [सकल ब्याज

व्यय पर परिचालन लाभ] का नीतिगत रेपो दर में से प्रतिगमन करके किया जाता है। नीतिगत दर में बदलाव का कर्ज-चुकौती संकेतकों पर एक धीमा प्रभाव पड़ता है और फर्मों पर चरम प्रभाव नीतिगत दर संबंधी कार्रवाई के 7-9 तिमाहियों के बाद होता है (चार्ट 1)।

कॉरपोरेट क्षेत्र का स्वास्थ्य – जो ऋण परिपक्वता संरचना और नकदी शेष जैसे संकेतकों में लक्षित है- कर्ज-चुकौती लागत पर नीतिगत दर कार्रवाइयों के प्रभाव को संभावित रूप से बढ़ा या घटा सकता है। भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र ने चलनिधि बफर्स के निर्माण के साथ अपने ऋण की परिपक्वता संरचना में बढ़त देखी है। यह फर्मों को कठिन वित्तीय परिस्थितियों में समुत्थानशील बनाता है (चार्ट 2)।

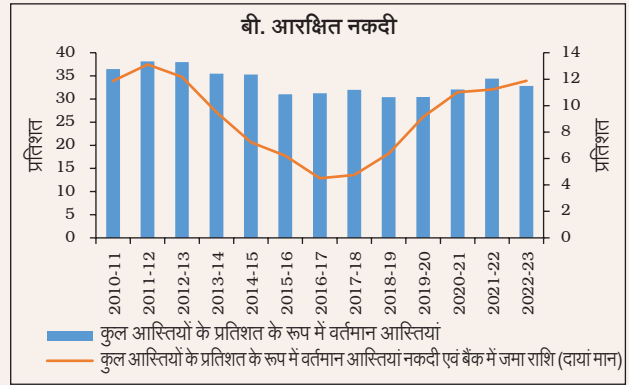
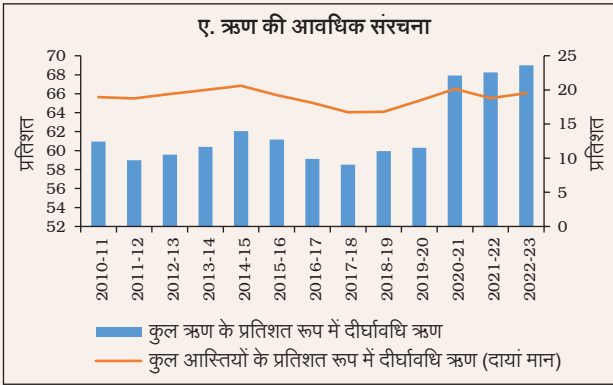
(जारी)

चार्ट 1 : मौद्रिक नीति और ऋण उपयोगिता
(रेपो रेट में 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी का प्रभाव)



आईआरएफ: आवेग प्रतिक्रिया कार्य
टिप्पणी: छायाित भाग 95 प्रतिशत कॉन्फिडेंस बैंड को दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 2 : मौद्रिक दरों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने वाले संस्था-विशिष्ट कारक



टिप्पणी: उक्त आंकड़े 900 फर्मों की कुल संख्या के वार्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

संदर्भ:

1. शूलरिक, एम, स्टीगे, एल. टी., और वार्ड, एफ. (2021), 'लीनिंग अगेस्ट द विंड एंड क्राइसिस रिस्क', *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू: इनसाइट्स*, 3(2), 199-214
2. बोइसे, एफ., कोलार्ड, एफ., मानेया, सी., और शापिरो, ए. (2023), 'मोनेटरी टाइटनिंग, इन्फ्लेशन ड्राइवर्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस', बीआईएस वर्किंग पेपर्स, नं.1155, दिसंबर

5. निष्कर्ष

II.4.16 वर्ष के दौरान ₹2000 के बैंक-नोटों का आहरण और बैंक-जमा के रूप में उनकी वापसी से संचलनगत-मुद्रा के और आरक्षित मुद्रा में मंदी आई, जबकि उसी अवधि में जमा-वृद्धि में तेजी आई। आकर्षक रिटर्न से बैंक-जमा को भी बढ़ावा मिला।

सेवा, कृषि, खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों के नेतृत्व में बैंक-ऋण में सुदृढ़ विस्तार बना रहा। उपभोक्ता और व्यावसाय दोनों की आशावादिता और बैंकों के सशक्त तुलन-पत्रों से ऋण-वृद्धि के बने रहने की उम्मीद है, और ऐसे में ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए जमाराशि-जुटाव हेतु प्रयासरत होना आवश्यक है।

II.5 वित्तीय बाजार

II.5.1 वैश्विक वित्तीय बाजार वर्ष 2023-24 के दौरान अस्थिर रहे, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति-गति की अनिश्चितता, प्रमुख केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक-नीति प्रक्षेप-वक्र और तीव्र भू-राजनैतिक तनावों को दर्शाता है। ब्याज दरों के चरम पर पहुंचने की प्रत्याशा के कारण, केंद्रीय बैंकों के मार्गदर्शन और नवीनतम आंकड़ों के प्रति बाजार का उत्साह अत्यधिक संवेदनशील बना रहा, जिसके कारण बड़े उतार-चढ़ाव हुए।

II.5.2 समुत्थानशील आर्थिक गतिविधियों और मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियाद से सुदृढ़ता प्राप्त कर, घरेलू वित्तीय बाजार 2023-24 के दौरान एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए। सरकारी नकदी शेष में निरंतर वृद्धि से चलनिधि अधिशेष कम होने के कारण वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में मुद्रा बाजार दरें मजबूत हुईं। नकदी की तंगी और ऋण मांग में कमी के बीच जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के निर्गम में तेजी आई। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के दौरान संप्रभु बॉण्ड प्रतिफल अपने कार्यक्षेत्र में ही सीमित रहा, लेकिन कच्चे तेल की कम कीमतें, वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट, प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय संप्रभु बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा, घरेलू मुद्रास्फीति में ढील और वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद से कम ऋण लेने के बाद उक्त कार्यक्षेत्र बढ़ गया। कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल ने सामान्यतः वर्ष के अंत में स्प्रेड में बृहतीकरण के साथ जी-सेक प्रतिफल को ट्रैक किया। आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के प्रदर्शन में हुई तेजी के कारण शेयर बाजारों ने मजबूत लाभ दर्ज किया। घरेलू विकास की संभावनाओं में सुधार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के उच्चतर प्रवाह के चलते भारतीय रुपये (आईएनआर) में स्थिरता देखी गई।

II.5.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, मुद्रा बाजार की गतिविधियां उप-खंड 2 में विस्तार से दी गई हैं। सरकारी

प्रतिभूतियों (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉण्ड के बाजार खंड का उल्लेख क्रमशः उप-खंड 3 और 4 में है। इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां, उप-खंड 7 में निष्कर्षी टिप्पणियों के साथ, उप-खंड 5 और 6 में शामिल हैं।

2. मुद्रा बाजार

II.5.4 वर्ष 2023-24 के दौरान मुद्रा बाजार दरें नीतिगत-गलियारे के आसपास बनी रहीं, जो कि चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप थीं⁴⁶। भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) वर्ष की पहली छमाही में अपने कार्यक्षेत्र में ही सीमित रही। उक्त दर अक्टूबर-जनवरी के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की उच्चतम सीमा के करीब बनी रही क्योंकि सरकारी नकदी शेष में लगातार वृद्धि और संचलनगत-मुद्रा (सीआईसी) में त्योहारी परिवेश के कारण हुए विस्तार के परिणामस्वरूप चलनिधि स्थितियाँ सख्त हो गईं थी [अध्याय III देखें]। फरवरी-मार्च के दौरान डब्ल्यूएसीआर में बढ़त हुई और यह नीतिगत रेपो दर के आसपास बनी रही। नीतिगत दर के सापेक्ष डब्ल्यूएसीआर का औसत प्रसार वर्ष 2022-23 के (-) 12 बीपीएस की तुलना में वर्ष 2023-24 में (+) 13 आधार अंक (बीपीएस) था (चार्ट II.5.1)।

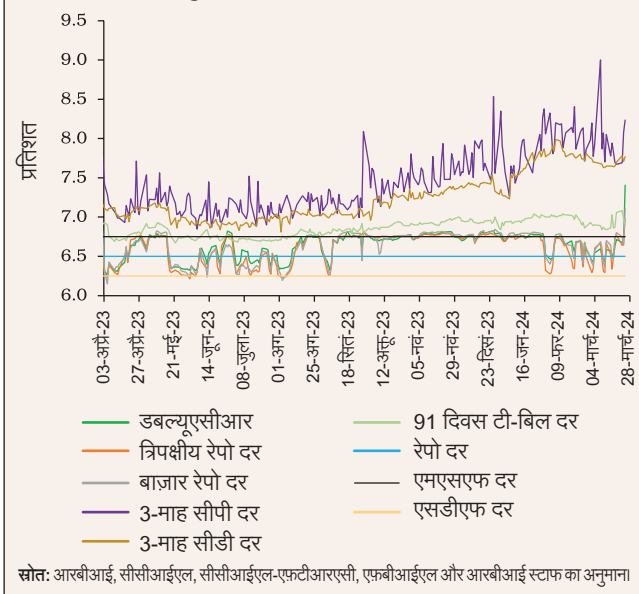
II.5.5 डब्ल्यूएसीआर के परिवर्तन-गुणांक⁴⁷ द्वारा मापे गए कॉल मनी खंड में अस्थिरता पिछले वर्ष के 18.1 प्रतिशत से वर्ष 2023-24 में तेजी से घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई। मुद्रा बाजार⁴⁸ में औसत-दैनिक-मात्रा 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के ₹5.36 लाख करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत घटकर ₹5.04 लाख करोड़ रुपये रह गई। वर्ष के दौरान, सख्त-चलनिधि-स्थितियों के साथ, तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः ₹5.1 लाख करोड़ और ₹5.2 लाख करोड़ तक पुनरुत्थान करने से पहले, औसत-दैनिक-मात्रा आरंभ में पहली तिमाही के ₹5.0 लाख करोड़ से वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में ₹4.9 लाख

⁴⁶ रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को इस रिपोर्ट के अध्याय-III में शामिल किया गया है।

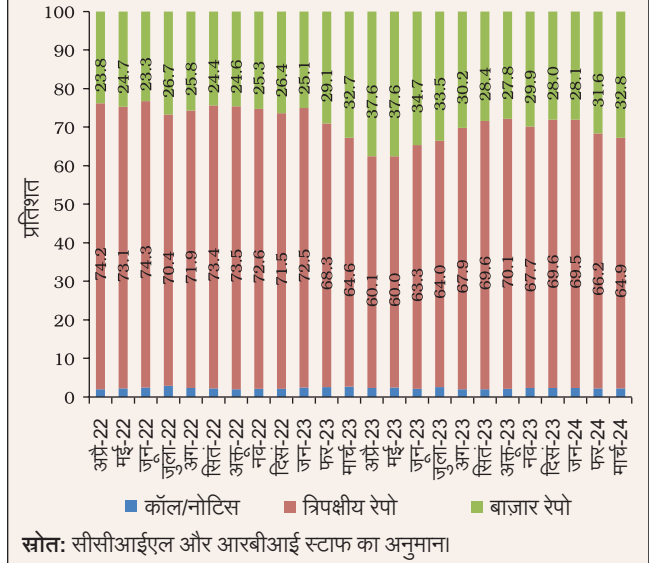
⁴⁷ भिन्नता-गुणांक माध्य से मानक विचलन का अनुपात है।

⁴⁸ शनिवार को छोड़कर ओवरनाइट और आवधिक खंड दोनों के कॉल मनी, त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो

चार्ट II.5.1 मुद्रा बाजार दरें और नीतिगत कॉरिडोर



चार्ट II.5.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा



करोड़ तक गिर गई⁴⁹ बाजार रेपो की हिस्सेदारी में 37 प्रतिशत से 31 प्रतिशत की सहगामी गिरावट के साथ, कुल मुद्रा-बाजार-मात्रा में से त्रिपक्षीय रेपो की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 61 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 67 प्रतिशत हो गई। गैर-संपार्श्विक कॉल मनी खंड का हिस्सा सभी तिमाहियों में लगभग 2 प्रतिशत पर बना रहा (चार्ट II.5.2)।

II.5.6 वर्ष के दौरान टी-बिल दरों की तुलना में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पेपर (सीपी) दरों का औसत दैनिक प्रसार बढ़ा (चार्ट II.5.3)। दिनांक 16 नवंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण पर विनियामकीय उपायों ने भी वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान एनबीएफसी के लिए सीपी दरों को सख्त करने में योगदान दिया।

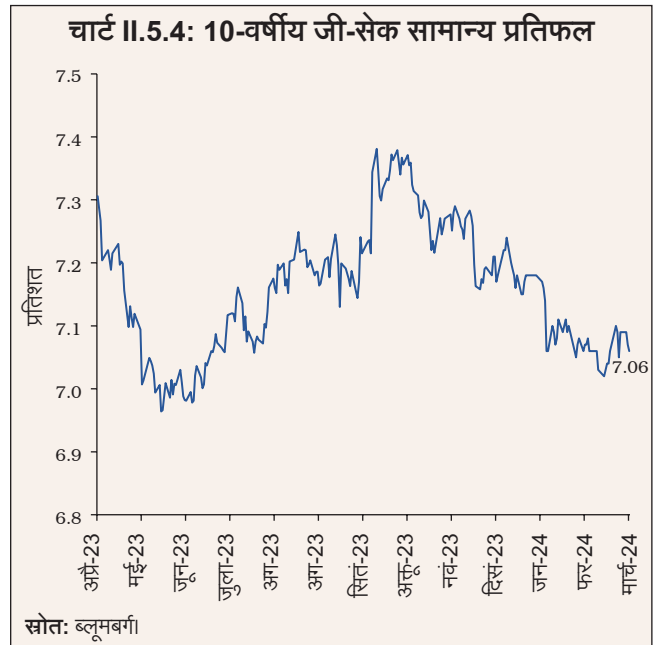
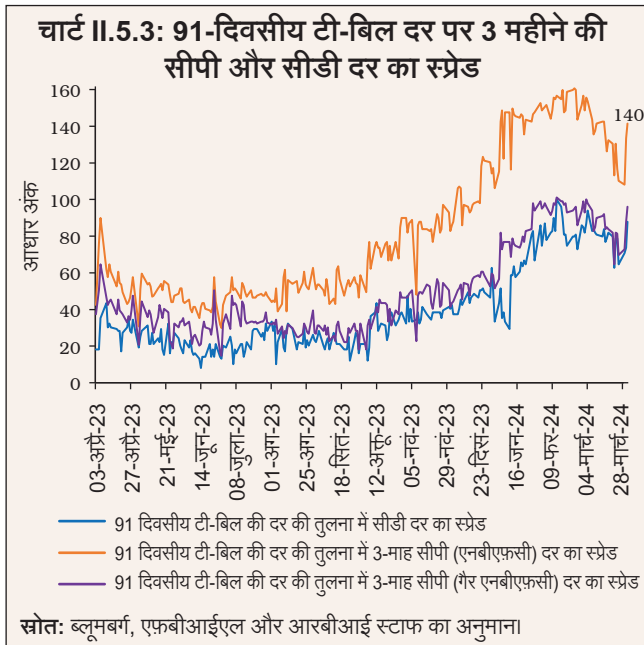
II.5.7 बैंकों द्वारा सुदृढ़ क्रेडिट ऑफ़टेक के निधीयन की मांग के कारण, प्राथमिक बाजार में, नए सीडी का निर्गम वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के ₹1.5 लाख करोड़ और दूसरी तिमाही के ₹1.6 लाख करोड़ से बढ़कर तीसरी तिमाही में ₹2.6 लाख

करोड़ हो गया। चौथी तिमाही में ₹3.0 लाख करोड़ रुपये का सीडी निर्गम हुआ। हालांकि, प्राथमिक बाजार में सीपी का नया निर्गम पहली तिमाही के ₹3.8 लाख करोड़ रुपये से घटकर दूसरी तिमाही में ₹3.3 लाख करोड़ रुपये और तीसरी तिमाही में ₹2.9 लाख करोड़ रुपये रह गया। तथापि, चौथी तिमाही में सीपी निर्गम फिर से बढ़कर ₹3.8 लाख करोड़ रुपये हो गया।

3. जी-सेक बाजार

II.5.8 वर्ष 2023-24 के दौरान जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव बना रहा। पहली तिमाही के दौरान मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखने, मुद्रास्फीति के अनुकूल माहौल और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से प्रतिफल में गिरावट आई। 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल तिमाही के अंत में 7.12 प्रतिशत रहा, जो 31 मार्च, 2023 (चार्ट II.5.4) के अपने स्तर से 19 बीपीएस कम है। मार्च 2023 के अंत तक 5-वर्षीय और 10-वर्षीय दरों के बीच प्रसार 14 बीपीएस से 4 बीपीएस तक सीमित होने के कारण प्रतिफल-वक्र सपाट हो गया। वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान,

⁴⁹ कॉल मनी खंड में, औसत-दैनिक-मात्रा (शनिवार को छोड़कर) पहली तिमाही में ₹11,274 करोड़ से घटकर दूसरी तिमाही में ₹10,381 करोड़ हो गई थी जो कि तीसरी तिमाही में बढ़कर ₹11,441 करोड़ और चौथी तिमाही में बढ़कर ₹11,785 करोड़ हो गई थी।



घरेलू जी-सेक प्रतिफल सख्त वैश्विक प्रतिफल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ बढ़ गया, जो प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने के आशावाद को अनुचित्रित करता है।⁵⁰ पिछली तिमाही में अपने स्तरों की तुलना में, घरेलू 10 वर्षीय और 5 वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल तिमाही के अंत में क्रमशः 10 बीपीएस और 15 बीपीएस की अधिकता पर पहुंचे। घरेलू जी-सेक प्रतिफल-वक्र आगे और सपाट हो गया एवं 5 वर्षीय और 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल के बीच प्रसार 1 बीपीएस तक मामूली रूप से व्युत्क्रमित हो गया।

II.5.9 तीसरी तिमाही के दौरान 10 वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल 5 आधार अंक घटकर 7.17 प्रतिशत रह गया, जो बहुवर्षीय उच्च स्तरों से प्राप्त वैश्विक प्रतिफल में वृद्धि और घरेलू मुद्रास्फीति में तेजी के बावजूद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। दीर्घान्त क्रम की तुलना में अल्पांत क्रम के प्रतिफल में हुई तेज गिरावट के साथ, प्रतिफल-वक्र अधोगामी

हो गया। 5 वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल 10 आधार अंक की गिरावट के साथ 7.13 फीसदी पर बंद हुआ। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में उम्मीद से कम सकल और निवल बाजार उधारी और घरेलू मुद्रास्फीति के कम होने के बीच वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान प्रतिफल और बढ़ गया। तिमाही के दौरान 10-वर्ष और 5-वर्ष का जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल क्रमशः 11 बीपीएस और 7 बीपीएस तक कम हो गया और दोनों मार्च 2024 के अंत में उक्त अवधि के दोनों प्रतिफल 7.06 प्रतिशत पर थे।

II.5.10 दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से पूर्ण प्राप्य मार्ग (एफएआर)⁵¹ की शुरुआत के साथ, एफपीआई के पास निवेश के तीन चैनल हैं - मध्यम अवधि के प्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत निर्धारित निवेश सीमाओं का सामान्य मार्ग; स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर); और एफएआर (सारणी II.5.1)। कुल मिलाकर, एफपीआई ने वर्ष 2023-24 में ऋण लिखतों में ₹1.3 लाख करोड़ का निवेश किया।

⁵⁰ 10 वर्षीय जेनेरिक अमेरिकी राजकोष-प्रतिफल 73 आधार अंक बढ़ा, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत उक्त अवधि में 27 प्रतिशत से अधिक बढ़ी और जुलाई और अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति ने ऊपरी सीमा के परे चली गई।

⁵¹ एफएआर के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियों को घरेलू निवेशकों को उपलब्ध होने के अलावा, बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था।

सारणी II.5.1 : ऋण लिखतों में एफपीआई निवेश

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

निवेश का मार्ग/चैनल	मार्च 31, 2022			मार्च 31, 2023			मार्च 31, 2024		
	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i) एमटीएफ [^]	10.8	2.2	20.5	11.7	1.8	15.4	11.7	1.9	16.0
(ii) वीआरआर ^{^S}	1.5	1.5	100.0	2.5	2.1	82.0	2.5	1.8	70.1
(iii) एफएआर [#]	17.6	0.5	2.6	28.0	0.8	2.8	39.0	1.7	4.5

[^]: इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (जी-सेक), राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) और कॉरपोरेट बॉण्ड शामिल हैं।

^S: 2023-24 में उपयोग में कमी जुलाई 2023 से वीआरआर के तहत समाप्त सीमा को वापस लेने के कारण है।

[#]: केवल मार्ग के अंतर्गत शामिल निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है।

स्रोत: सीसीआईएल और एनएसडीएल।

4. कॉरपोरेट ऋण बाजार

II.5.11 वर्ष 2023-24 के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल बढ़ा, जो कि जी-सेक प्रतिफल को प्रतिबिंबित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों के एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड पर मासिक औसत प्रतिफल; एनबीएफसी; और कॉरपोरेट्स मार्च 2023 के स्तर की तुलना में मार्च 2024 में क्रमशः 12 बीपीएस, 14 बीपीएस और 12 बीपीएस तक बढ़े (सारणी II.5.2)। पहली छमाही के दौरान प्रतिफल बढ़ा और चलनिधि-स्थितियों के सख्त होने और एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए विनियामकीय उपायों की घोषणा के बीच स्प्रेड-विस्तार के साथ सामान्यतः दूसरी छमाही में कम हुआ।

II.5.12 तदनुसूची परिपक्वता के जी-सेक प्रतिफल पर एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड-प्रतिफल का प्रसार सामान्यतः मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच बढ़ गया। कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक द्वितीयक बाजार का कारोबार वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के ₹5,549 करोड़ रुपये से मामूली रूप से बढ़कर ₹5,718 करोड़ रुपये हो गया (चार्ट II.5.5)।

II.5.13 विदेशी निर्गमों के माध्यम से लामबंदी में वृद्धि के साथ, वर्ष 2023-24 में सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉण्ड के प्राथमिक निर्गम बढ़े (सारणी II.5.3)। बॉण्ड बाजार के जरिए जुटाए गए कुल संसाधनों में निजी नियोजनों का हिस्सा 97.8 प्रतिशत रहा। कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश वर्ष के दौरान मामूली रूप से बढ़ा, जिससे अनुमोदित सीमाओं का उपयोग एक वर्ष पूर्व के 15.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 16.2 प्रतिशत तक हो गया।

सारणी II.5.2: कॉरपोरेट बॉण्ड* - प्रतिफल और स्प्रेड

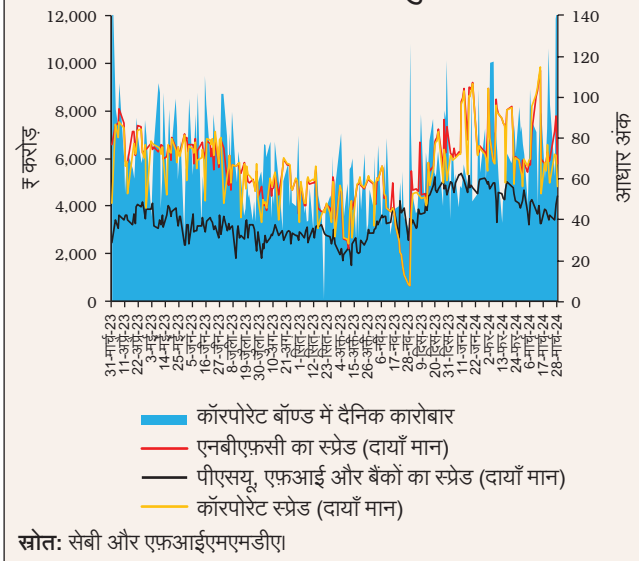
इकाई	प्रतिफल (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) [संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक]		
	मार्च 2023	मार्च 2024	परिवर्तन (बीपीएस)	मार्च 2023	मार्च 2024	परिवर्तन (बीपीएस)
1	2	3	4 (=3-2)	5	6	7 (=6-5)
(i) पीएसयू, एफआई और बैंक	7.75	7.63	-12	36	44	8
(ii) एनबीएफसी	8.12	7.98	-14	73	80	7
(iii) कॉरपोरेट्स	8.07	7.95	-12	68	77	9

*: एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड।

नोट: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: एफआईएमएमडीए।

चार्ट II.5.5: कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार में एए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार



5. इक्विटी बाजार

II.5.14 वर्ष 2023-24 में, भारतीय इक्विटी मार्केट मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियाद और कॉरपोरेट लाभप्रदता पर उद्गामी बना रहा। मार्च 2024 के अंत में 24.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,651 पर बंद होकर बीएसई सेंसेक्स एक नए पायदान पर पहुंचा, जो अधिकांश वैश्विक समकक्षों (चार्ट II.5.6) के प्रदर्शन से बेहतर था। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) निर्गमों के स्थिर प्रवाह और तरजीही आवंटन एवं योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ते हुए संसाधन जुटाव के साथ द्वितीयक बाजार के उत्साह के कारण प्राथमिक बाजार में भी अधिक संसाधन जुटे।

II.5.15 वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए ठोस कॉरपोरेट आय, उत्साहित घरेलू विनिर्माण प्रदर्शन, सुदृढ़ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और मई 2023 के लिए बढ़े हुए मुद्रास्फीति-प्रिट से उत्साहित होकर वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बाजार एक शुभ संकेत नोट पर शुरू हुआ। चीन के इक्विटी में हुई गिरावट के तनाव और उच्च वैश्विक ब्याज दरों की लंबी अवधि की बढ़ती चिंताओं के बावजूद, दूसरी तिमाही में बाजारों ने 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सकारात्मक घरेलू कॉरपोरेट परिणामों और अनुकूल समष्टि-आर्थिक आंकड़ों पर उद्गामी प्रक्षेपवक्र बनाए रखा।

II.5.16 तीसरी तिमाही में, शुरू में बाजारों ने अक्टूबर 2023 में एफपीआई बहिर्वाह और मध्य-पूर्व युद्धस्थितियों के कारण नुकसान दर्ज किया। इसके बाद, घरेलू इक्विटी सूचकांकों में तीव्र प्रतिक्षेप हुआ, जो कि अमेरिका में प्रत्याशा से अधिक बढ़ी मुद्रास्फीति से मिले वैश्विक संकेतों और वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही की अनुकूल घरेलू कॉरपोरेट आय से प्रेरित था। वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में, बाजारों ने मामूली वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के मजबूत जीडीपी विकास आंकड़ों के बाद, बीएसई सेंसेक्स ने मार्च 2024 में 74,000 अंक – जो एक नया शिखर था- पार कर लिया।

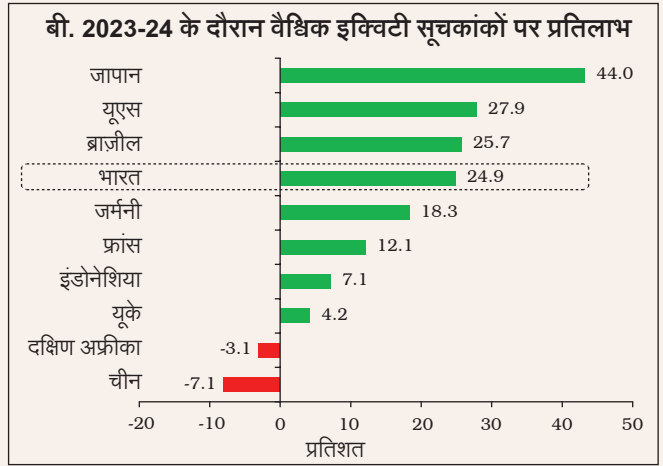
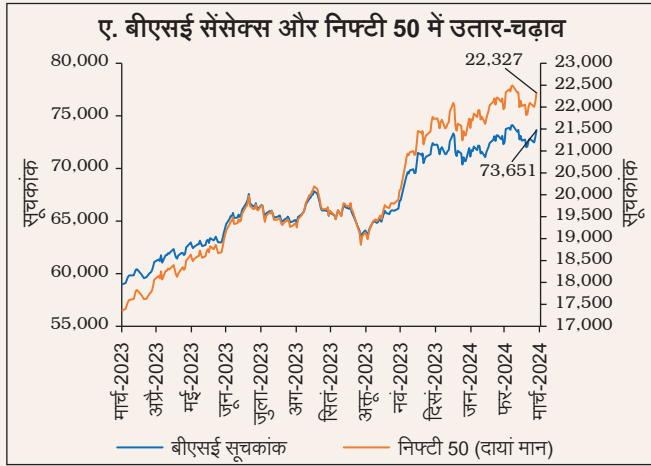
II.5.17 बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में जोखिम-प्रवृत्ति बढ़ने पर वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 63.4 प्रतिशत और 60.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, व्यापक बाजार सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट II.5.7ए)। एफपीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹0.4 लाख करोड़ की निवल बिक्री के मुकाबले वर्ष 2023-24 के दौरान घरेलू इक्विटी बाजार में ₹2.1 लाख करोड़ का निवल क्रय किया (चार्ट II.5.7बी)।

सारणी II.5.3: कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करना

मद	राशि (₹ लाख करोड़)		परिवर्तन (कॉलम 3 की तुलना में कॉलम 2) [प्रतिशत]
	2022-23	2023-24	
1	2	3	4
(i) प्राथमिक कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गमन	7.6	8.6	12.2
(ii) बकाया कॉरपोरेट बॉण्ड (मार्च-अंत)	43.1	47.3	9.6
(iii) कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश (मार्च अंत)	1.04	1.08	4.4

स्रोत: सेबी और एनएसडीएल।

चार्ट II.5.6: इक्विटी बाजार



स्रोत : बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग

म्यूचुअल फंड्स ने वर्ष 2023-24 में ₹2.0 लाख करोड़ का निवल क्रय किया।

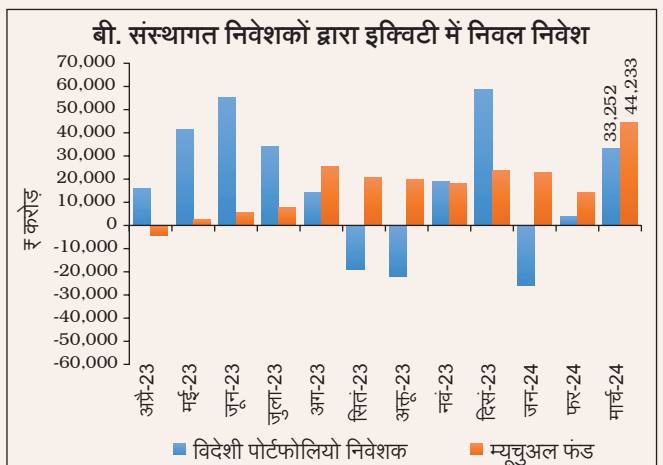
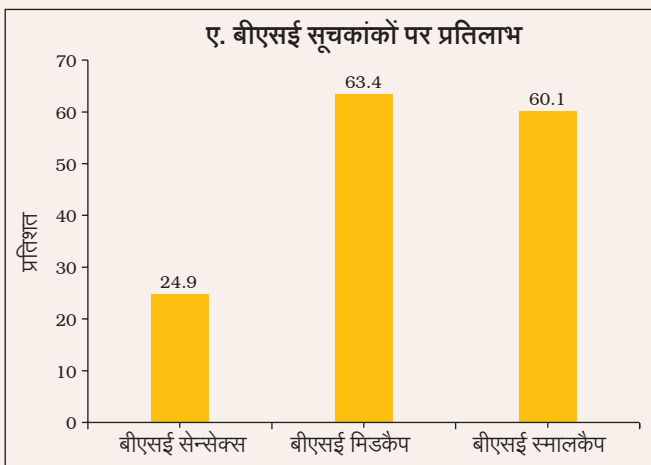
प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाव

II.5.18 इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में, तरजीही आवंटन और क्यूआईपी के माध्यम से संसाधनों का जुटाव वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर ₹1.1 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹0.9 लाख करोड़ रुपये था। आईपीओ, अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधनों का जुटाव 0.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 0.8 लाख करोड़ रुपये हो गया (चार्ट II.5.8ए और परिशिष्ट सारणी 5)। लघु

एवं मध्यम उद्योग (एसएमई) खंड ने, एक वर्ष पूर्व 125 एसएमई आईपीओ/एफपीओ निर्गमों से जुटाए गए ₹2,333 करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2023-24 में 197 एसएमई आईपीओ/एफपीओ निर्गमों से ₹6,122 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

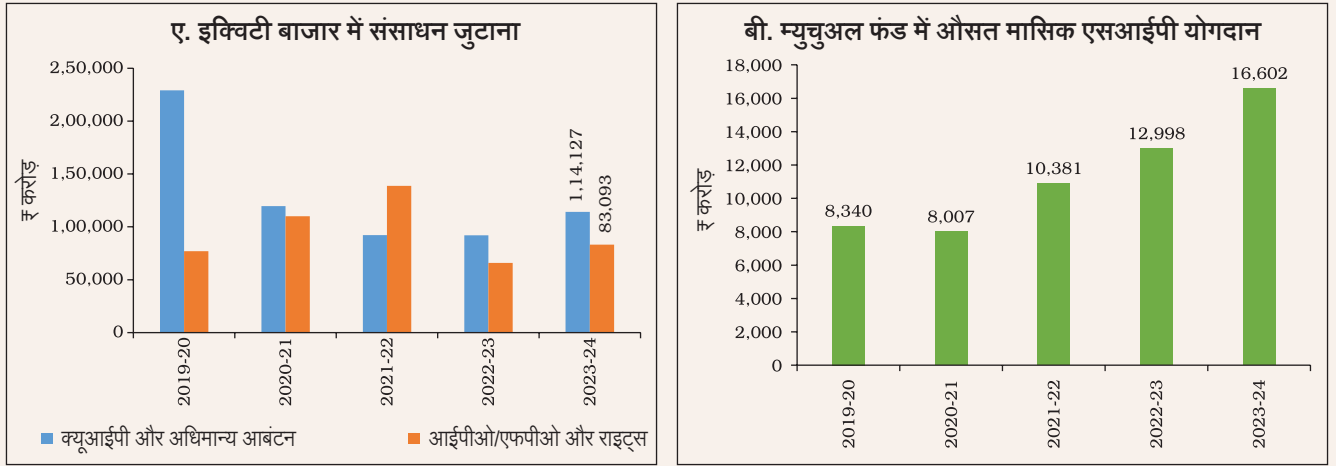
II.5.19 म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संसाधन, वर्ष 2022-23 के ₹0.8 लाख करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2023-24 के दौरान चार गुना से अधिक बढ़कर ₹3.5 लाख करोड़ रुपये हो गए। इक्विटी-आधारित-अबाध- म्यूचुअल फंड-योजनाओं से निवल संसाधन जुटाव ₹1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर ₹1.8 लाख करोड़ रुपये हो गया। सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) मार्ग के माध्यम से म्यूचुअल फंड में औसत

चार्ट II.5.7: व्यापक बाजार और संस्थागत निवेश



स्रोत : सेबी, एनएसडीएल और ब्लूमबर्ग

चार्ट II.5.8: संसाधन जुटाना



स्रोत: सेबी और एमएफआई

मासिक योगदान पिछले वर्ष के ₹12,998 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹16,602 करोड़ हो गया (चार्ट II.5.8बी)। इक्विटी-आधारित-अबाध-म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के तहत आस्तियां (एयूएम) मार्च 2024 के अंत में करीब 55 प्रतिशत बढ़कर ₹23.5 लाख करोड़ रुपये हो गईं। ऋण-आधारित-अबाध योजनाओं में निवल प्रतिदान वर्ष 2023-24 के दौरान गिरकर ₹0.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष में ₹1.8 लाख करोड़ रुपये था।

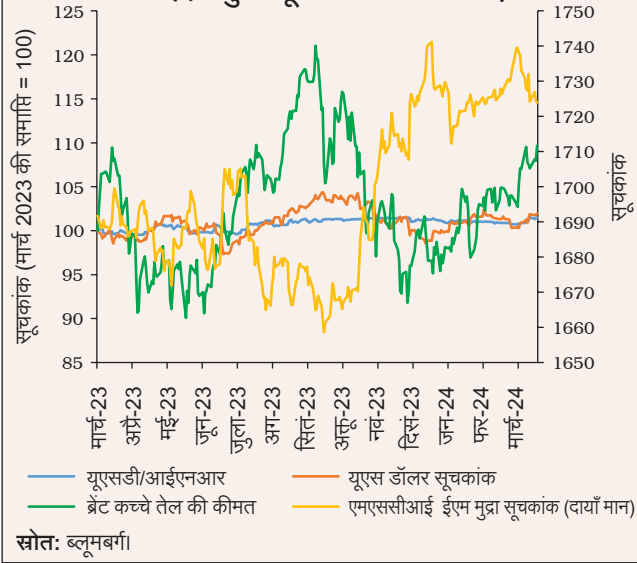
6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.20 भारतीय रुपए (आईएनआर) ने 2023-24 के दौरान घरेलू समष्टि-आर्थिक बुनियाद में सुधार, कमतर चालू खाता घाटे (सीएडी) और उच्च पूंजी अंतर्वाह के प्रति समुत्थानशीलता दिखाई। पहली तिमाही में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बड़े एफपीआई अंतर्वाह से भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि की उम्मीद मिली, जबकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ऋण-उच्चतम-सीमा समस्या के कारण भारतीय रुपए को मूल्यहास के दबाव और गतिरोध का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर, पहली तिमाही में 0.2 प्रतिशत बढ़कर भारतीय रुपए का मूल्य जून 2023 के अंत तक ₹82.04 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में, यूएस डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र लाभ के चलते भारतीय रुपया मूल्यहास के दबाव में आ गया। यूएस एफईडी द्वारा और अधिक मौद्रिक कसाव की उम्मीदों और लंबी अवधि के लिए उच्चतर ब्याज दर

के अपने रुख के कारण, यूएस डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) ने तिमाही के दौरान 3.2 प्रतिशत की बढ़त प्राप्त की जो कि सितंबर 2022 के बाद से इसका सबसे अच्छा प्रतिशत था। सितंबर 2023 में एफपीआई के बहिर्वाह ने भारतीय रुपए पर मूल्यहास दबाव डाला, जबकि जेपी मॉर्गन के *इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल बॉण्ड इंडेक्स* में भारतीय बॉण्ड के शामिल होने की रिपोर्ट ने उसे सहायता प्रदान की। कुल मिलाकर, तिमाही के अंत में 1.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ भारतीय रुपए का मूल्य ₹83.04 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.5.9)।

II.5.21 वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में, अमेरिकी राजकोष-प्रतिफल में वर्ष 2007 के बाद से हुई, उच्चतम स्तर की वृद्धि, मध्य-पूर्व एशिया के भू-राजनैतिक-तनाव-विस्फोट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और निरंतर एफपीआई बहिर्वाह का भारतीय रुपए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद, नवंबर और दिसंबर (यूएस \$ 13 बिलियन) के दौरान अमेरिकी राजकोष-प्रतिफल की बढ़त और एफपीआई अंतर्वाह की बहाली से भारतीय रुपए को बल मिला। कुल मिलाकर, तिमाही के अंत में 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ भारतीय रुपए का मूल्य ₹83.21 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में, मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की उच्च कीमतों ने भारतीय रुपए पर मूल्यहास का दबाव डाला, जबकि करीब \$10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफपीआई अंतर्वाह ने भारतीय रुपए को बल दिया। तिमाही के अंत में 0.2

चार्ट II.5.9: रुपये, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव



प्रतिशत की गिरावट के साथ भारतीय रुपए का मूल्य ₹83.40 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और अमेरिका के बीच व्याज-दर-विभेदक के संकुचन के चलते कम वर्ष 2023-24 के दौरान, वायदा-लाभ में गिरावट आई।

II.5.22 40- सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में वर्ष 2023-24 के दौरान 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7. निष्कर्ष

II.5.23 सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों से उत्पन्न प्रतिकूल वैश्विक स्पिलओवर, प्रमुख प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति के अनिश्चित प्रक्षेपवक्र, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और दीर्घस्थायी भू-राजनैतिक तनावों के बावजूद, भारतीय वित्तीय बाजारों में वर्ष 2023-24 के दौरान व्यवस्थित उतार-चढ़ाव देखे गए। मुद्रा बाजार दरों में कम अस्थिरता देखी गई। घरेलू जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव देखा गया। भारतीय रुपए का मूल्य स्थिर रहा। भारतीय इक्विटी मार्केट को नए शिखर मिले और प्राथमिक बाजारों में संसाधन जुटाव को गति मिली।

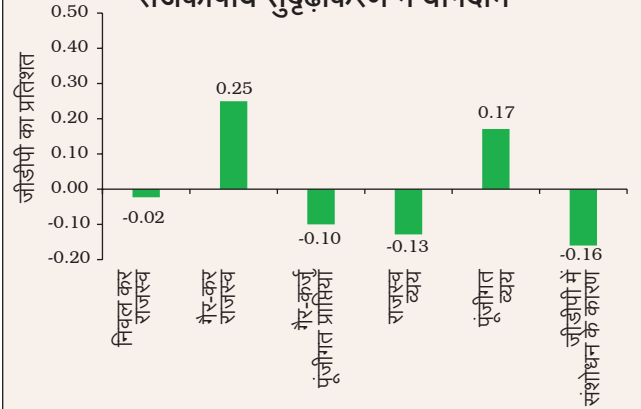
II.6 सरकारी वित्त

II.6.1 सरकारी वित्त - केंद्र और राज्य दोनों - 2023-24 के दौरान मजबूत हुए। कर प्राप्तियों में बढ़ोतरी और कम राजस्व व्यय के कारण सामान्य सरकारी घाटे (जीडीपी का प्रतिशत) में गिरावट आई। पूंजीगत परिव्यय में विस्तार के साथ व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इस पृष्ठभूमि में, उपखंड 2 और 3 क्रमशः 2023-24 और 2024-25 में केंद्र सरकार के वित्त का विश्लेषण करते हैं। उपखंड 4 और 5 इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर केंद्रित हैं। उपखंड 6 में सामान्य सरकारी वित्त पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड समापन टिप्पणियाँ निर्धारित करता है।

2. 2023-24 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.2 केंद्र सरकार ने बजट अनुमान (चार्ट II.6.1) के अनुरूप, संशोधित अनुमान (आरई)⁵² में 2023-24 के लिए अपने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर सीमित रखा।

चार्ट II.6.1: बीई की तुलना में आरई का 2023-24 में राजकोषीय सुदृढीकरण में योगदान



बीई: बजट अनुमान। आरई: संशोधित अनुमान।

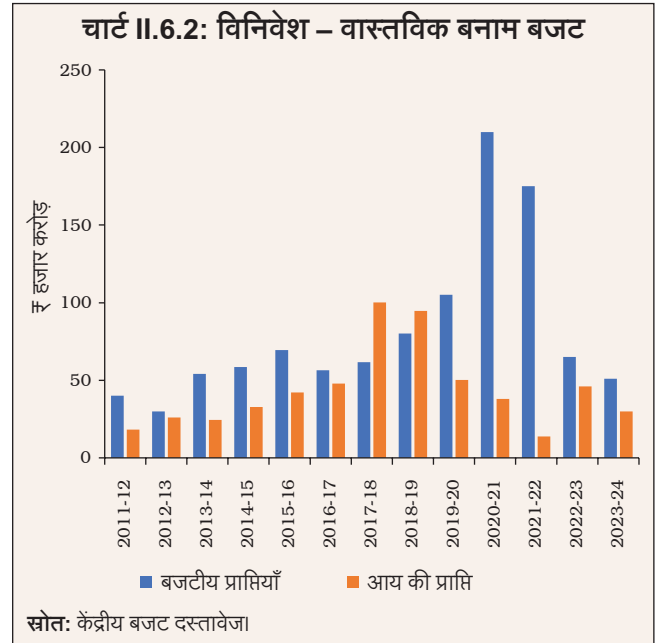
टिप्पणी: नकारात्मक योगदान, प्राप्तियों में वृद्धि या व्यय में कटौती या जीडीपी में बीई से आरई तक ऊर्ध्वगामी संशोधन को दर्शाता है क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक योगदान, कम प्राप्तियों या बीई से आरई तक उच्च व्यय को दर्शाता है, क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से फिसलन में योगदान करते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

⁵² 2023-24 के लिए सांकेतिक जीडीपी का दूसरा अग्रिम अनुमान (29 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी) 293.9 लाख करोड़ रुपये रखा गया, जबकि पहले का अनुमान 296.6 लाख करोड़ रुपये (अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किया गया) था। तदनुसार, 2023-24 (आरई) के लिए सकल राजकोषीय घाटा अंतरिम यूनियन बजट 2024-25 में दिए गए 5.85 प्रतिशत के संशोधित अनुमान के मुकाबले जीडीपी का 5.90 प्रतिशत है।

II.6.3 2023-24 (आरई) में राजस्व व्यय, बजट अनुमान से सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत (₹38,103 करोड़) अधिक हो गया, यह अतिरिक्त व्यय उपायों को प्रतिबिंबित करता है जैसे कि ₹200 प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी (अगस्त 2023 में घोषित); प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) योजना (अक्टूबर 2023 में घोषित) के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर ₹100 की अतिरिक्त सब्सिडी; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) का पांच साल तक विस्तार; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत अधिक धन का आवंटन और पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी (एनबीएस) के तहत उच्च व्यय। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय, बजटीय ऋण और अग्रिम (₹20,640 करोड़) तथा पूंजी परिव्यय⁵³ (₹30,075 करोड़) कम होने के कारण बजट अनुमान (बीई) से ₹50,715 करोड़ कम हो गया। फिर भी, पूंजीगत व्यय 2023-24 (आरई) में 28.4 प्रतिशत की मजबूत गति से बढ़ा और 2022-23 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत हो गया।

II.6.4 प्राप्ति के मामले में, सकल कर राजस्व बजट अनुमान बीई से बढ़कर ₹76,353 करोड़ हो गया, जो उच्च आयकर राजस्व से प्रेरित है, जो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह में कमी की भरपाई करता है। आयकर ने बजट अनुमान (बीई) के 1.0 की तुलना में 2023-24 (आरई) में 2.5 की उछाल दर्ज की। हालाँकि, राज्यों को अधिक हस्तांतरण के कारण निवल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद (₹6,713 करोड़) के बीई से 0.02 प्रतिशत कम हो गया। रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उच्च लाभांश हस्तांतरण के कारण गैर-कर राजस्व संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (₹74,145 करोड़) के बीई से 0.3 प्रतिशत अधिक हो गया। हालाँकि, 2023-24 (आरई) में विनिवेश प्राप्ति ₹30,000 करोड़ थीं, जो बीई (चार्ट II.6.2) से कम थीं।



3. 2024-25 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.5 अंतरिम यूनियन बजट 2024-25 ने उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से विकास गति का समर्थन करते हुए राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। 2024-25 के लिए जीएफडी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत रखा गया है, जो 2023-24 के लिए आरई पर 76 आधार अंक (बीपीएस) का समेकन है, जिसका मकसद सकल घरेलू उत्पाद के 11.2 प्रतिशत पर राजस्व व्यय को नियंत्रित करना है, साथ ही पूंजीगत व्यय को 2023-24 (आरई) के 3.2 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत करने का बजट रखा गया है [सारणी II.6.1 और परिशिष्ट सारणी 6]।

II.6.6 व्यय के मोर्चे पर, प्रमुख सब्सिडी पर भुगतान 2024-25 (बीई) में 7.8 प्रतिशत तक संकुचन होने की उम्मीद है, जिससे राजस्व व्यय वृद्धि 3.2 प्रतिशत तक सीमित हो जाएगी। 2024-25 में पूंजीगत व्यय मजबूत रहने की उम्मीद है (16.9 प्रतिशत की वृद्धि), जो सड़कों और रेलवे पर खर्च से प्रेरित है (चार्ट II.6.3)। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को 2024-25 तक बढ़ा दिया गया

⁵³ पूंजीगत व्यय से ऋण और अग्रिम को कम करके।

सारणी II.6.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय प्रदर्शन

(जीडीपी का प्रतिशत)

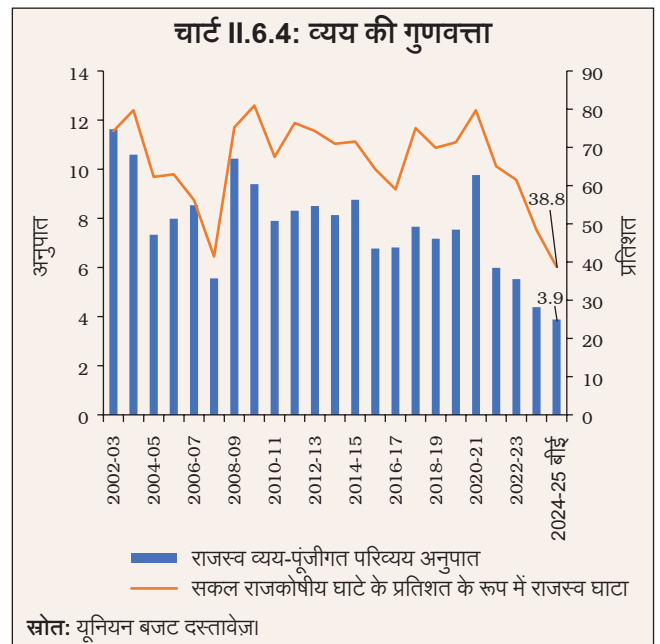
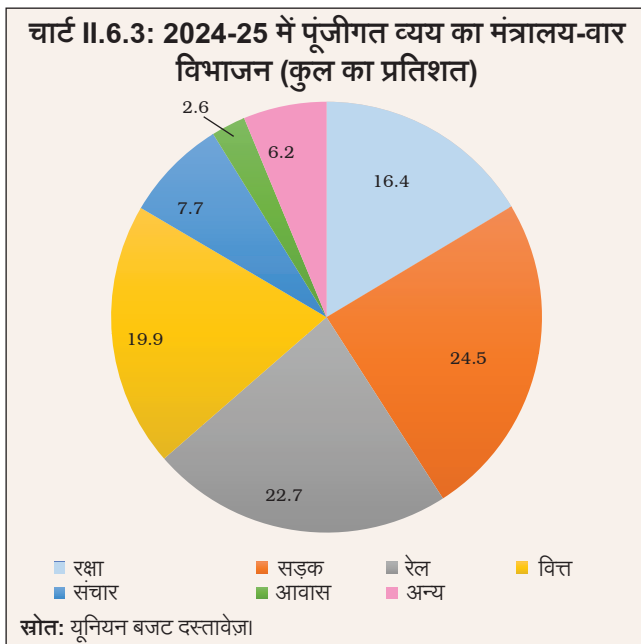
मद	2015-16 से 2018-19 तक का औसत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (बीई)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर-कर्ज प्राप्तियाँ	9.1	8.7	8.5	9.4	9.1	9.0	9.4	9.4
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	11.0	10.0	10.2	11.5	11.3	11.1	11.7	11.7
ए) प्रत्यक्ष कर	5.7	5.2	4.8	6.0	6.2	6.0	6.6	6.7
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.3	4.8	5.5	5.5	5.2	5.1	5.1	5.0
III. निवल कर राजस्व	7.1	6.7	7.2	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9
IV. गैर-कर राजस्व	1.5	1.6	1.0	1.5	1.1	1.0	1.3	1.2
V. गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
VI. कुल व्यय	12.6	13.4	17.7	16.1	15.6	14.9	15.3	14.5
VII. राजस्व व्यय	10.9	11.7	15.5	13.6	12.8	11.6	12.0	11.2
VIII. पूंजीगत व्यय	1.7	1.7	2.1	2.5	2.7	3.3	3.2	3.4
IX. राजस्व घाटा	2.4	3.3	7.3	4.4	4.0	2.9	2.9	2.0
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	4.6	9.2	6.7	6.4	5.9	5.9	5.1

बीई: बजट अनुमाना आरई: संशोधित अनुमाना
 स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

है। 2024-25 (बजट अनुमान) में पूंजीगत परिव्यय के बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है और राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय अनुपात में और गिरावट आएगी, जिससे खर्च की गुणवत्ता में सुधार होगा (चार्ट II.6.4)।

II.6.7 प्राप्तियों के मामले में, सकल कर राजस्व में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, इसमें हाल के रुझानों के

अनुरूप 1.09 की उछाल है [सारणी II.6.2]। 2024-25 में प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात जीडीपी का 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो तीन दशकों में सबसे अधिक है (चार्ट II.6.5)। गैर-कर प्राप्तियों में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जबकि विनिवेश लक्ष्य ₹0.5 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।

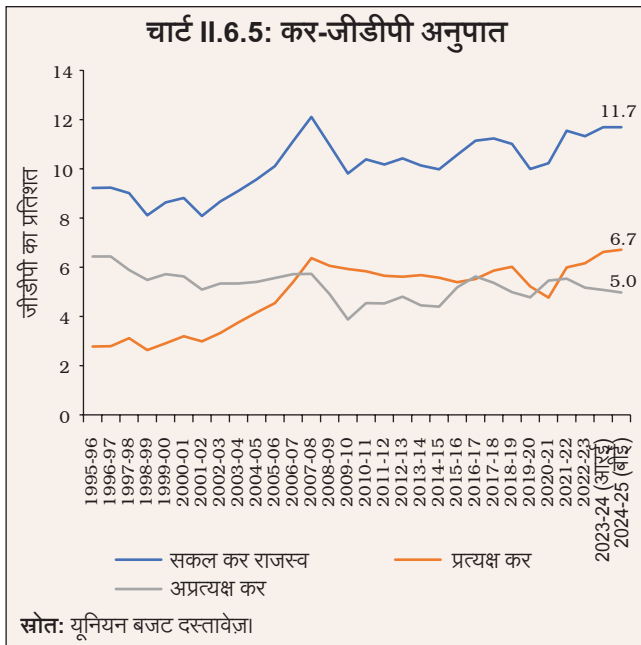


सारणी II.6.2 : कर उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 to 2018-19)	2023-24 (बीई)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	0.99	1.39	1.09
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.00	1.90	1.24
i) कॉर्पोरेशन कर	0.92	1.00	1.30	1.24
ii) आय कर	1.27	1.00	2.49	1.25
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.99	0.77	0.89
i) जीएसटी	-	1.14	1.40	1.11
ii) सीमा शुल्क	0.31	1.05	0.27	0.55
iii) उत्पाद शुल्क	0.91	0.57	-0.50	0.48

:- अनुपलब्ध जीएसटी : वस्तु एवं सेवा कर
टिप्पणी: कर उछाल को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन तथा कर नीतियों में विवेकाधीन परिवर्तनों के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के यूनियन बजट दस्तावेजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ अनुमान।

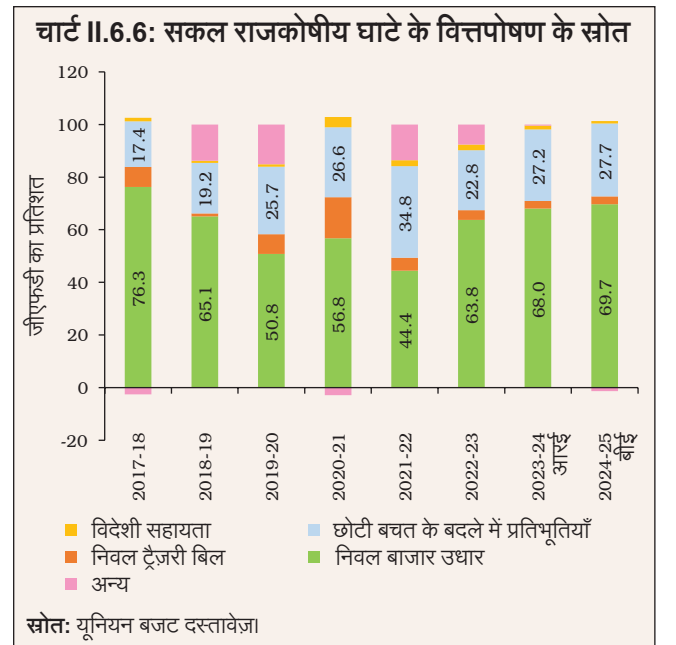
II.6.8 2024-25 के लिए सकल बाजार उधार ₹14.1 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) आंका गया है, जो 2023-24



आरई (जीडीपी का 5.3 प्रतिशत) के ₹15.4 लाख करोड़ से कम है। 2024-25 (बीई)⁵⁴ में निवल बाजार उधार जीएफडी के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बना हुआ है, इसके बाद छोटी बचतें (चार्ट II.6.6) हैं।

4. 2023-24 में राज्य वित्त

II.6.9 राज्यों ने 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत का संयुक्त जीएफडी बजट रखा है, जो इस वर्ष के लिए केंद्र की 3.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है (सारणी II.6.3)। 2023-24 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पास उपलब्ध 22 राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का जीएफडी बजट अनुमान का 92.0 प्रतिशत था जो एक साल पहले (88.1 प्रतिशत) से अधिक था। प्राप्तियों के मोर्चे पर, उच्च हस्तांतरण के कारण राज्यों के कुल कर राजस्व में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उनके स्वयं की कर राजस्व वृद्धि कम हो गई। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर और राज्य उत्पाद



⁵⁴ 2024-25 (बीई) के लिए निवल बाजार उधार 11.75 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.6 प्रतिशत) रखा गया है, जबकि 2023-24 (आरई) में 11.80 लाख करोड़ रुपये [जीडीपी का 4.0 प्रतिशत] था।

सारणी II.6.3: राज्यों/यूटी की राजकोषीय स्थिति

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	26.7 (13.3)	25.9 (13.0)	32.3 (13.7)	39.1 (14.4)	43.1 (14.3)
II. गैर कर पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.6 (0.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.4 (0.1)
III. राजस्व व्यय	27.9 (13.9)	29.6 (14.9)	33.3 (14.2)	40.4 (14.8)	43.4 (14.4)
IV. पूंजीगत व्यय	4.6 (2.3)	4.6 (2.3)	5.8 (2.4)	8.1 (3.0)	9.6 (3.2)
ए. पूंजीगत परिव्यय	4.2 (2.1)	4.1 (2.1)	5.3 (2.3)	7.3 (2.7)	8.7 (2.9)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.8 (0.3)	0.9 (0.3)
V. राजकोषीय घाटा	5.3 (2.6)	8.1 (4.1)	6.6 (2.8)	9.2 (3.4)	9.5 (3.1)
VI. राजस्व घाटा	1.2 (0.6)	3.7 (1.9)	1.0 (0.4)	1.3 (0.5)	0.4 (0.1)
VII. प्राथमिक घाटा	1.7 (0.9)	4.2 (2.1)	2.3 (1.0)	4.5 (1.7)	4.3 (1.4)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

शुल्क में कमी हुई। गैर-कर राजस्व में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राज्यों को जीएसटी मुआवजे की समाप्ति और वित्त आयोग अनुदान में कमी के बाद केंद्र से अनुदान में 21.7 प्रतिशत की कमी आई।

II.6.10 खर्च के मोर्चे पर, 2023-24 में राजस्व व्यय वृद्धि (8.1 प्रतिशत) रही, जो एक साल पहले (11.2 प्रतिशत) की तुलना में कम थी। पूंजीगत खर्च पर जोर (19.4 फीसदी वृद्धि) जारी रहा, जिसे पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की केंद्र की योजना से सहायता मिली।

5. 2024-25 में राज्य वित्त

II.6.11 2024-25 के लिए 27 राज्यों की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत के समेकित जीएफडी के लिए बजट रखा है (सारणी II.6.4)। 2024-25 (बीई) के दौरान केंद्र से सकल हस्तांतरण के बजट में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कर हस्तांतरण में वृद्धि और पूंजीगत व्यय के लिए ऋण में वृद्धि है। राज्यों को

पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना 2024-25 में जारी रहेगी, जिसमें कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा - 2023-24 में संशोधित अनुमान (आरई) के स्तरों पर 23.2 प्रतिशत की वृद्धि। हालांकि, वित्त आयोग के अनुदान में 2024-25 में गिरावट की उम्मीद है, मुख्य रूप से हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत कम अंतरण के कारण।

सारणी II.6.4: राज्य सरकार वित्त 2024-25*: प्रमुख घाटा संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2022-23	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
1	2	3	4
राजस्व घाटा	0.3	0.5	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	3.3	3.0
प्राथमिक घाटा	1.0	1.6	1.3

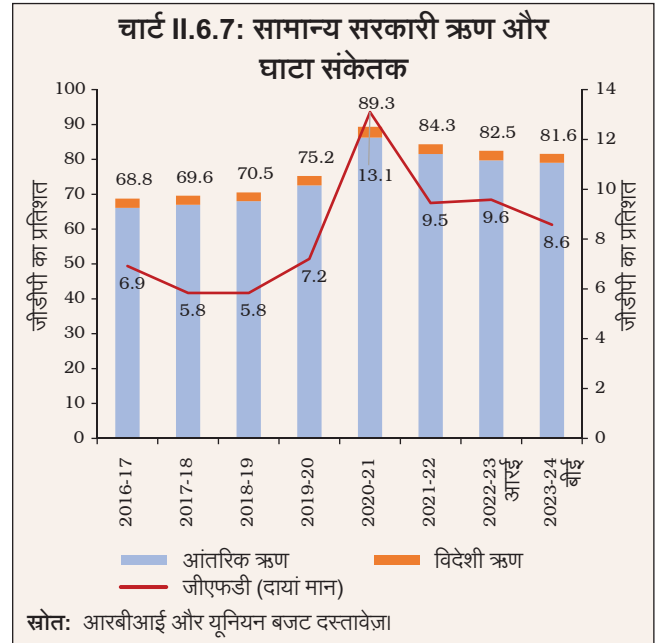
*: डेटा 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है, जिनमें से 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है और शेष राज्यों ने 2024-25 के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

6. सामान्य सरकारी वित्त

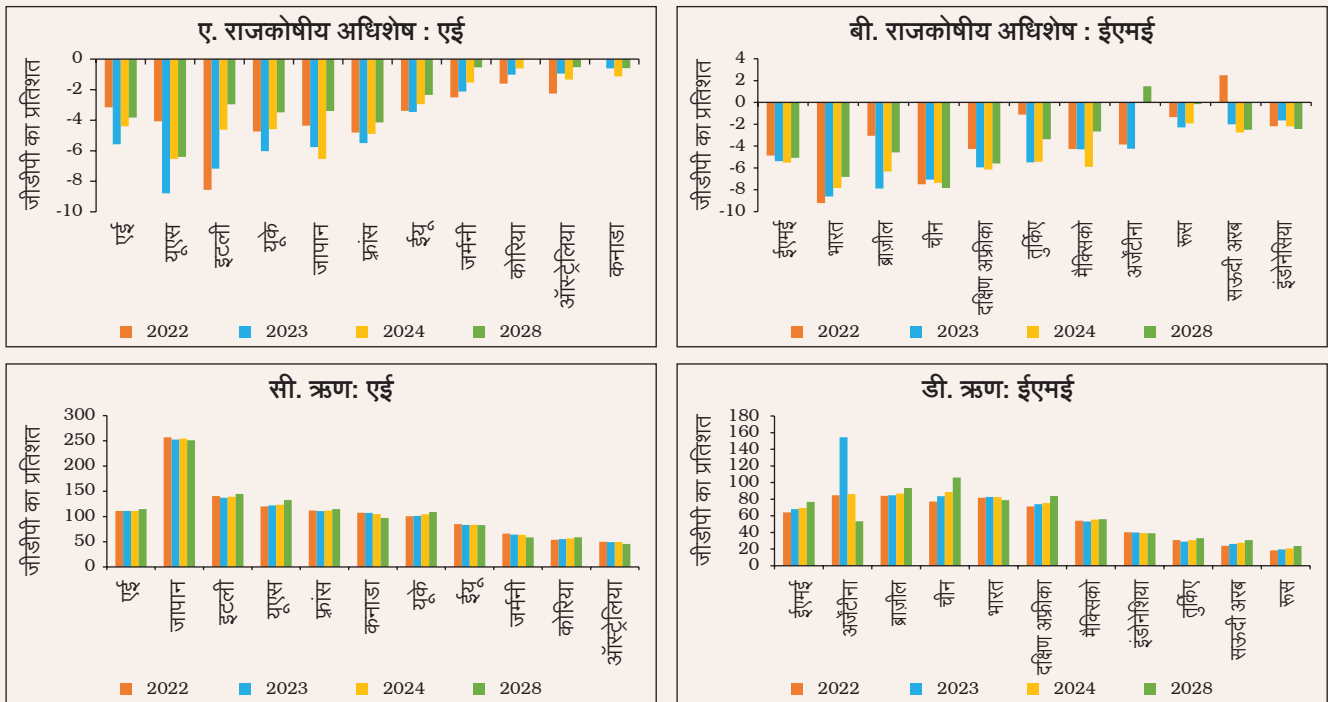
11.6.12 सामान्य सरकारी घाटा और ऋण 2023-24 (बीई) में कम होकर क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 8.6 प्रतिशत और 81.6 प्रतिशत हो गया, जो 2022-23 (आरई) में क्रमशः 9.6 प्रतिशत और 82.5 प्रतिशत था (चार्ट 11.6.7 और परिशिष्ट सारणी 7)। 2023-24 में सामान्य सरकारी घाटे में कमी को कर राजस्व में वृद्धि [2022-23 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद के 17.9 प्रतिशत से 2023-24 (बीई) में 18.2 प्रतिशत तक] के साथ-साथ राजस्व व्यय में कमी (जीडीपी का 25.8 प्रतिशत से 24.0 प्रतिशत तक) से समर्थन मिला।

11.6.13 वैश्विक स्तर पर, धीमी वृद्धि, बढ़ती वास्तविक ब्याज दरों और विस्तारवादी राजकोषीय नीति (आईएमएफ, 2023)⁵⁵ के कारण 2023 में सरकारी वित्त दबाव में रहा। सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AE) में 2022 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023



में 5.6 प्रतिशत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EME) में 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया [चार्ट 11.6.8]। भले

चार्ट 11.6.8: राजकोषीय अधिशेष और सकल ऋण



यूएस : संयुक्त राज्य अमेरिका यूके: यूनाइटेड किंगडम ईयू: यूरोपीय संघ
टिप्पणी: अन्य देशों के साथ तुलना सुनिश्चित करने के लिए भारत का डेटा वर्ल्ड ईकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ से लिया गया है। हालाँकि, यह यूनिनियन बजट दस्तावेज़ों या रिजर्व बैंक प्रकाशनों में बताए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकता है क्योंकि आईएमएफ भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रथाओं और परंपराओं की तुलना में विभिन्न लेखांकन प्रथाओं और परंपराओं का पालन करता है।
स्रोत: वर्ल्ड ईकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ।

⁵⁵ आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर, अक्टूबर 2023।

ही 2024 में समग्र घाटे के कम रहने का अनुमान है, वैश्विक ऋण/जीडीपी अनुपात ऊंचा रहेगा और आई और ईएमई दोनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

7. निष्कर्ष

11.6.14 वर्ष 2024-25 का अंतरिम यूनियन बजट उच्च पूंजी परिव्यय के माध्यम से खर्च की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सुदृढ़ीकरण को जारी रखता है। 2024-25 में सकल बाजार उधार को कम रखा गया है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होगी। 2024-25 के लिए राज्य सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण की भी परिकल्पना की गई है। तदनुसार, 2024-25 में सामान्य सरकारी घाटे में और गिरावट आने की उम्मीद है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है।

11.7 बाह्य क्षेत्र

11.7.1 वर्ष 2023-24 के दौरान वैश्विक व्यापार की मात्रा में तेज गिरावट से उत्पन्न होने वाली कई वैश्विक प्रतिकूलताओं, प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की आक्रामक कठोर मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वित्तीय बाजार में उत्पन्न अस्थिरता के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत हुआ। कमोडिटी की कीमतों में सुधार और कमजोर बाहरी मांग

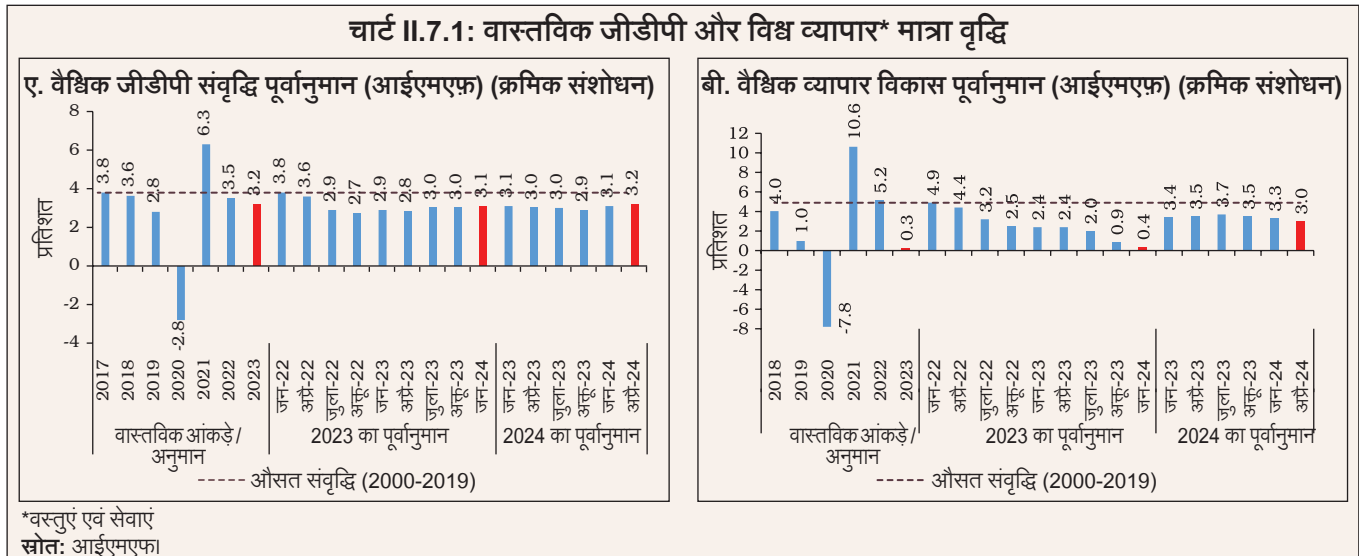
के कारण व्यापारिक निर्यात और आयात (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) में संकुचन हुआ और पण्य व्यापार घाटा कम हुआ। सेवा निर्यात और निजी अंतरण प्राप्तियों में उछाल ने चालू खाता घाटे (सीएडी) को कम कर दिया। पोर्टफोलियो प्रवाह और बैंकिंग पूंजी के कारण निवल पूंजी प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।

11.7.2 इस पृष्ठभूमि में, उपखंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है, इसके बाद खंड 3 में भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अदृश्य मदों का रुख उपखंड 4 में प्रस्तुत किया गया है। निवल पूंजी प्रवाह पर विवरण उपखंड 5 में दिए गए हैं, जबकि बाह्य भेद्यता संकेतकों का मूल्यांकन उपखंड 6 में किया गया है, जिसके पश्चात निष्कर्ष अवलोकन किया गया है।

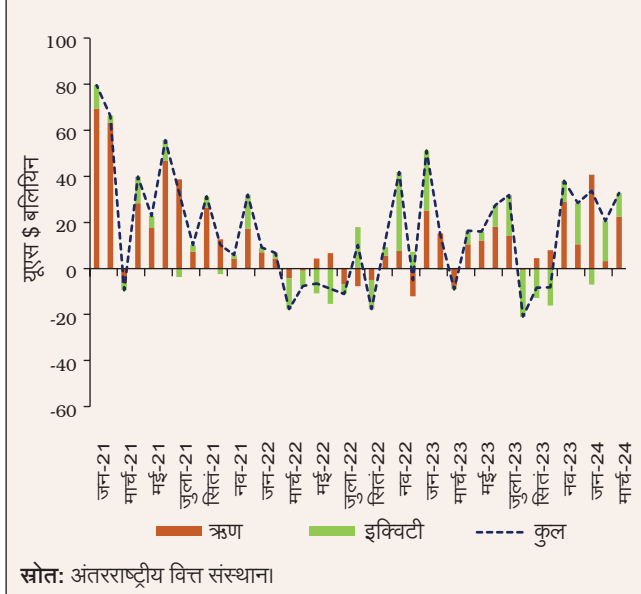
2. वैश्विक आर्थिक स्थितियां

11.7.3 तंग वित्तीय स्थितियों, उच्च मुद्रास्फीति, भू-आर्थिक विखंडन और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 के दौरान असमान विस्तार बनाए रखा। अमेरिका और कई बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में समुत्थानशीलता के कारण जीडीपी वृद्धि कुछ हद तक अनुमानों से अधिक रही [चार्ट 11.7.1ए]। वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि बढ़ती व्यापार

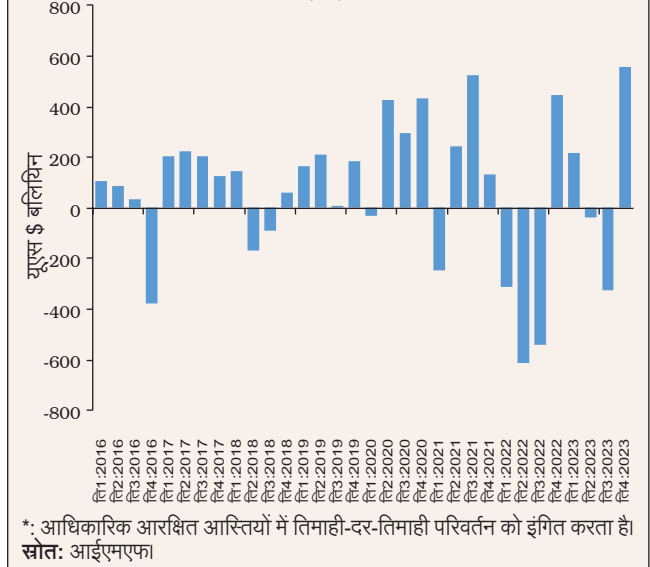
चार्ट 11.7.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार* मात्रा वृद्धि



चार्ट II.7.2: ईएमई के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह



चार्ट II.7.3: वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन*



बाधाओं, महामारी के कम होने के साथ वैश्विक मांग का वस्तुओं से कम-व्यापार गहन सेवाओं की ओर घूमना, कमजोर निवेश मांग और अमेरिकी डॉलर की मजबूती (चार्ट II.7.1बी) के कारण बाधित हुई। अवस्फीति में लगातार बढ़ोतरी के साथ, बाजार 2024 में वैश्विक मौद्रिक चक्र में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, जो वित्तीय बाजारों के रुख को बढ़ा रहा है।

II.7.4 बढ़ती अस्थिरता के बीच 2023 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पोर्टफोलियो प्रवाह में सुधार हुआ (चार्ट II.7.2)। 2023 के दौरान वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, जो वर्ष के दौरान सोने की ऊंची कीमतें और 2023 की चौथी तिमाही में निम्न बॉण्ड प्रतिफल को दर्शाता है (चार्ट II.7.3)।

3. पण्य व्यापार

II.7.5 भारत में, 2023-24 के दौरान पण्य निर्यात के साथ-साथ आयात (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) में भी गिरावट आई (सारणी II.7.1)। निर्यात से अधिक आयात में गिरावट के साथ, 2023-24 में व्यापारिक व्यापार घाटा कम हो गया, जो वैश्विक मांग की कमजोरी को दर्शाता है (बॉक्स II.7.1)।

सारणी II.7.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	यूएस \$ बिलियन में मूल्य				विकास दर (वर्ष-दर-वर्ष)			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात								
ति1	51.5	95.5	121.0	103.9	-36.4	85.7	26.6	-14.1
ति2	74.2	102.7	110.7	107.2	-5.2	38.5	7.8	-3.2
ति3	75.8	106.8	104.6	105.6	-4.2	41.0	-2.1	1.0
ति4	90.4	117.0	114.8	120.4	20.4	29.3	-1.9	4.9
वार्षिक	291.8	422.0	451.1	437.1	-6.9	44.6	6.9	-3.1
आयात								
ति1	61.3	127.0	183.5	160.1	-52.9	107.2	44.5	-12.8
ति2	90.7	147.5	189.0	170.3	-23.1	62.7	28.1	-9.9
ति3	110.8	167.0	176.1	174.4	-4.6	50.7	5.4	-1.0
ति4	131.7	171.6	167.3	170.7	19.1	30.3	-2.5	2.0
वार्षिक	394.4	613.1	716.0	675.4	-16.9	55.4	16.8	-5.7
व्यापार शेष								
ति1	-9.8	-31.4	-62.6	-56.2				
ति2	-16.5	-44.8	-78.3	-63.1				
ति3	-35.1	-60.2	-71.5	-68.8				
ति4	-41.2	-54.6	-52.6	-50.3				
वार्षिक	-102.6	-191.0	-264.9	-238.3				

टिप्पणी : तिमाही आंकड़े वार्षिक आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

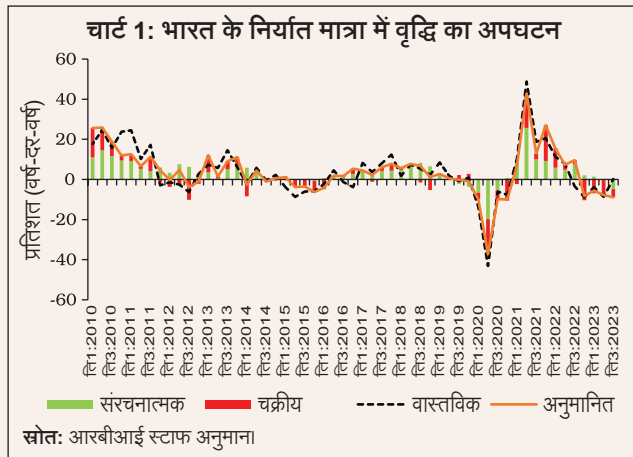
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

बॉक्स II.7.1

निर्यात में गिरावट: संरचनात्मक या चक्रीय?

भारत का पण्य निर्यात 2000-01 के 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दस गुना बढ़कर 2023-24 में 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें बीच-बीच में संकुचन और तेजी दर्ज की गई। वर्ष 2009 की पहली तिमाही से वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही तक की अवधि के लिए एक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल इंगित करता है कि विश्व पण्य व्यापार मात्रा के संबंध में भारत की पण्य निर्यात मात्रा की दीर्घकालिक मूल्य-सापेक्षता लगभग 1.4 है। लगभग (-) 0.5 की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) लोचनीयता के साथ निर्यात भी सापेक्ष कीमतों के प्रति संवेदनशील है (सारणी 1)।

अल्पावधि व्यापार लोच इसकी दीर्घकालिक मात्रा से ऊपर है, जो बताता है कि वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव का अल्पावधि में भारत के निर्यात पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समायोजन की गति (ईसीएम शब्द) अधिक है, यानी, प्रवृत्ति से विचलन के बाद निर्यात वृद्धि तेजी से अपने संतुलन पथ पर लौट आती है। उपरोक्त परिणामों का उपयोग करते हुए, भारत की पण्य निर्यात वृद्धि संरचनात्मक और चक्रीय घटकों (कॉन्स्टेंटिनेस्कु एट अल, 2020) में विघटित हो गई है। विश्लेषण से पता चलता है कि चक्रीय घटक हाल की तिमाहियों में पण्य निर्यात मात्रा में संकुचन का प्रमुख चालक रहा है (चार्ट 1)।



II.7.6 2023-24 में निर्यात में गिरावट व्यापक थी, निर्यात टोकरी के लगभग आधे हिस्से में गिरावट दर्ज की गई। यह संकुचन पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों (पीओएल) तथा रत्न एवं आभूषणों द्वारा प्रेरित था। दूसरी ओर, गैर-तेल, गैर-रत्न और आभूषण निर्यात में विस्तार देखा गया (चार्ट II.7.4)।

सारणी 1 : भारत के व्यापारिक निर्यात की अनुमानित मूल्य सापेक्षता आश्रित चर: लॉग (निर्यात मात्रा सूचकांक)

व्याख्यात्मक चर	गुणक
1	2
अल्पकालिक (त्रुटि सुधार परिणाम)	
D [लॉग (भारत का निर्यात मात्रा सूचकांक) _{t-1}]	-0.173** (0.076)
D [लॉग (भारत का निर्यात मात्रा सूचकांक) _{t-2}]	0.123* (0.064)
D [लॉग (भारत का निर्यात मात्रा सूचकांक) _{t-3}]	0.272*** (0.061)
D [लॉग (विश्व व्यापार मात्रा सूचकांक) _t]	2.132*** (0.155)
त्रुटि सुधार _{t-1}	-0.567*** (0.099)
दीर्घकालिक (संयुक्त संबंध)	
स्थिर	1.263 (0.933)
लॉग (विश्व व्यापार मात्रा सूचकांक)	1.369*** (0.106)
लॉग (निर्यात भारत आरईआईआर)	-0.544** (0.265)
बाउंड टेस्ट, एफ-सांख्यिकी	7.779
ब्रूश-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट, पी-वैल्यू	0.339
ब्रूश-पेगन-गॉडफ्रे टेस्ट, पी-वैल्यू	0.455
समायोजित आर-वर्ग	0.818

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियां हैं।

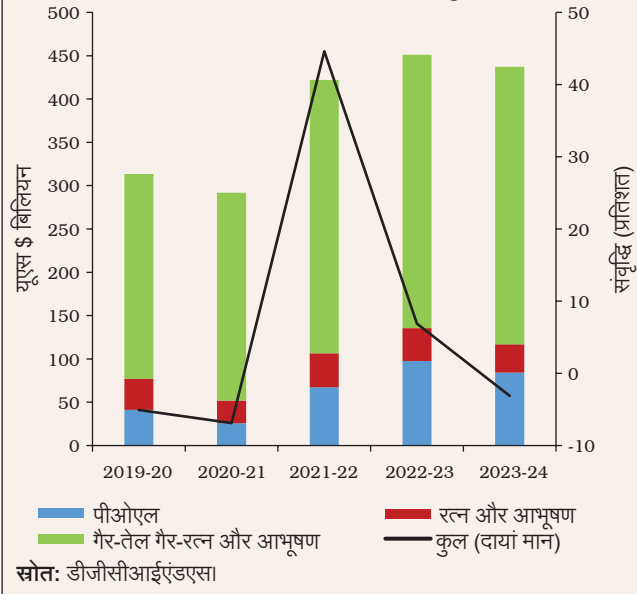
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

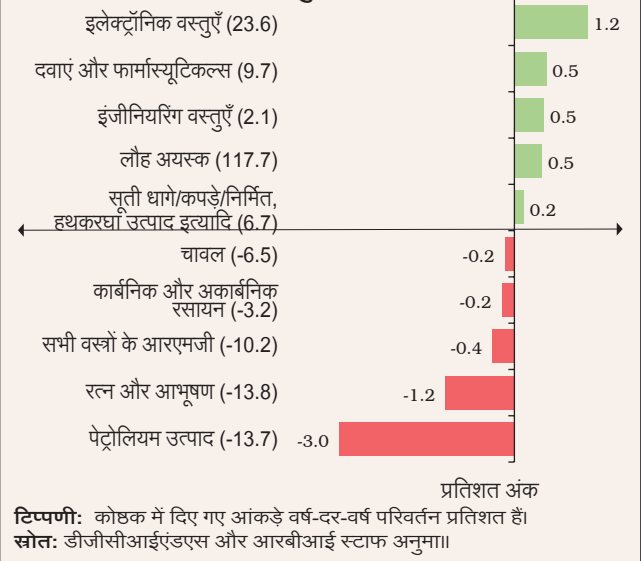
कॉन्स्टेंटिनेस्कु, सी., मट्टू, ए., और रूटा, एम. (2020), 'द ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन: साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल?', द वर्ल्ड बैंक ईकोनॉमिक रिव्यू, 34(1), 121-142।

II.7.7 पेट्रोलियम उत्पादों तथा रत्न और आभूषणों के अलावा, सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधान (आरएमजी), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और चावल ने पण्य निर्यात में गिरावट में योगदान दिया। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क और सूती धागे/फैब्स/मेड-अप्स में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.7.5)।

चार्ट II.7.4: भारत का पण्य वस्तु निर्यात



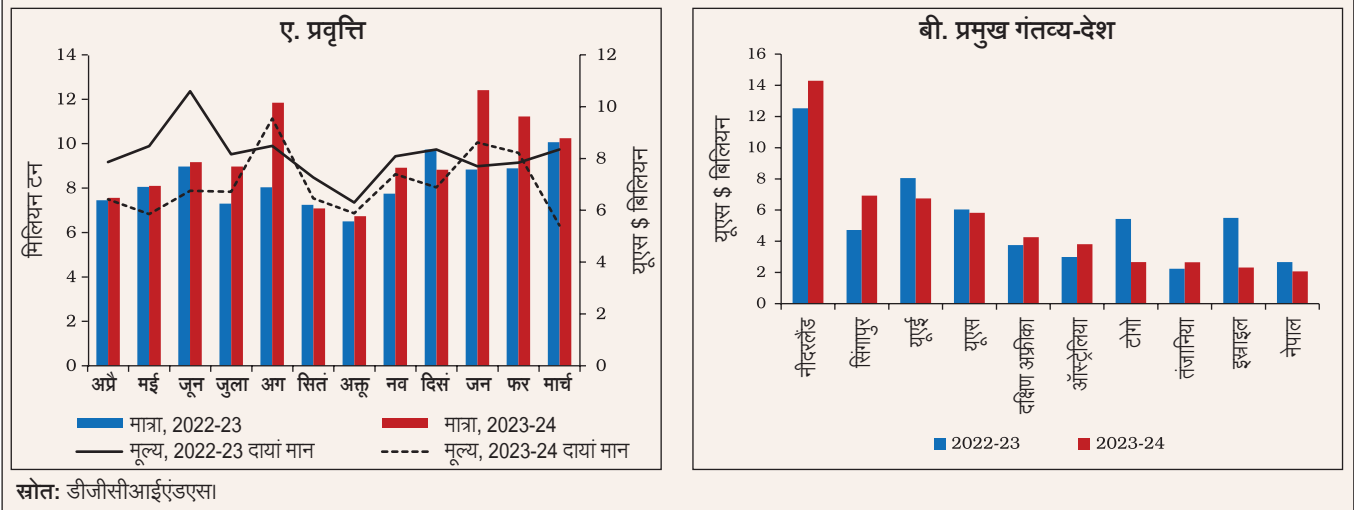
चार्ट II.7.5: निर्यात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2022-23 की तुलना में 2023-24)



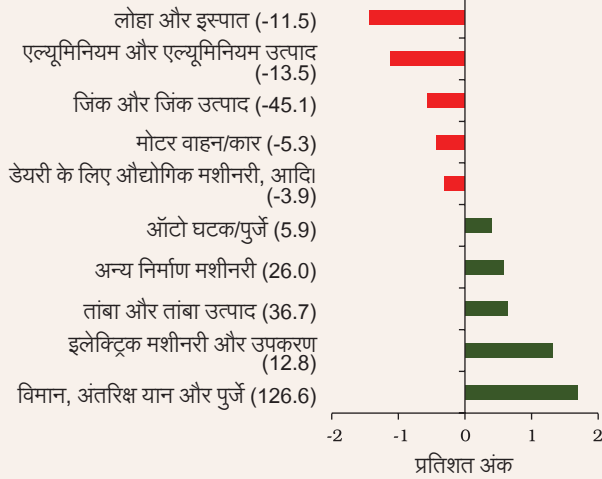
II.7.8 तेल की कीमतों में नरमी के कारण 2023-24 में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 13.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जिससे मात्रा के संदर्भ में वृद्धि की भरपाई हो गई (चार्ट II.7.6ए)। शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों में से, पांच में आपूर्ति में वृद्धि देखी गई (चार्ट II.7.6बी)।

II.7.9 इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात - कुल निर्यात टोकरी का एक-चौथाई - 2023-24 के दौरान 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा, जो विमान, अंतरिक्ष यान और कल-पुर्जों, और इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरणों द्वारा समर्थित है। दूसरी ओर, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम और उसके उत्पाद, और जस्ता

चार्ट II.7.6 : भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

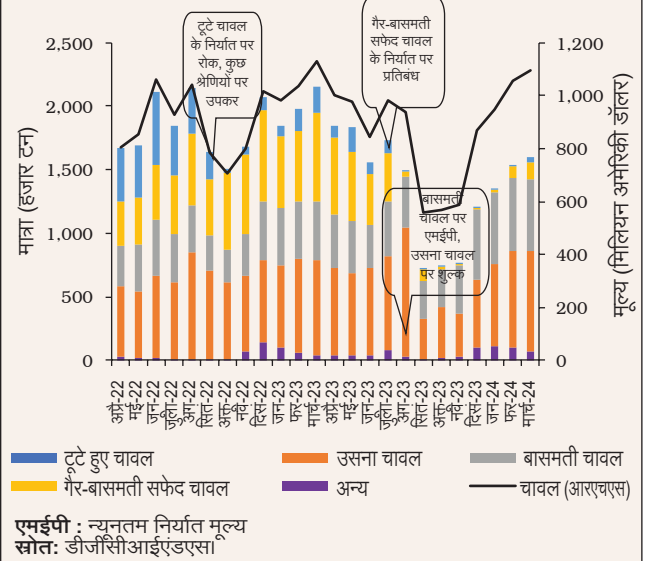


चार्ट II.7.7: भारत के इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात – सापेक्ष योगदान (2022-23 की तुलना में 2023-24)



टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.7.8: भारत का चावल निर्यात



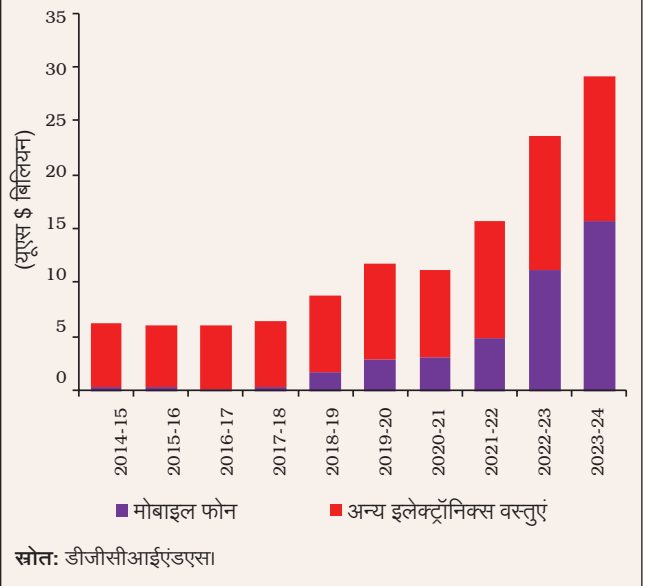
और उसके उत्पादों ने समग्र निर्यात वृद्धि को नीचे खींच लिया (चार्ट II.7.7)।

II.7.10 2023-24 के दौरान कृषि निर्यात में 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई और यह 46.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। घरेलू आपूर्ति में सुधार के लिए निर्यात पर प्रतिबंध के कारण 2023-24 के दौरान चावल निर्यात 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.7.8)।

II.7.11 2023-24 के दौरान 29.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 23.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो मोबाइल फोन (कुल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात का आधे से ज्यादा) द्वारा संचालित है, जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसएमई)⁵⁶ के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लाभान्वित है [चार्ट

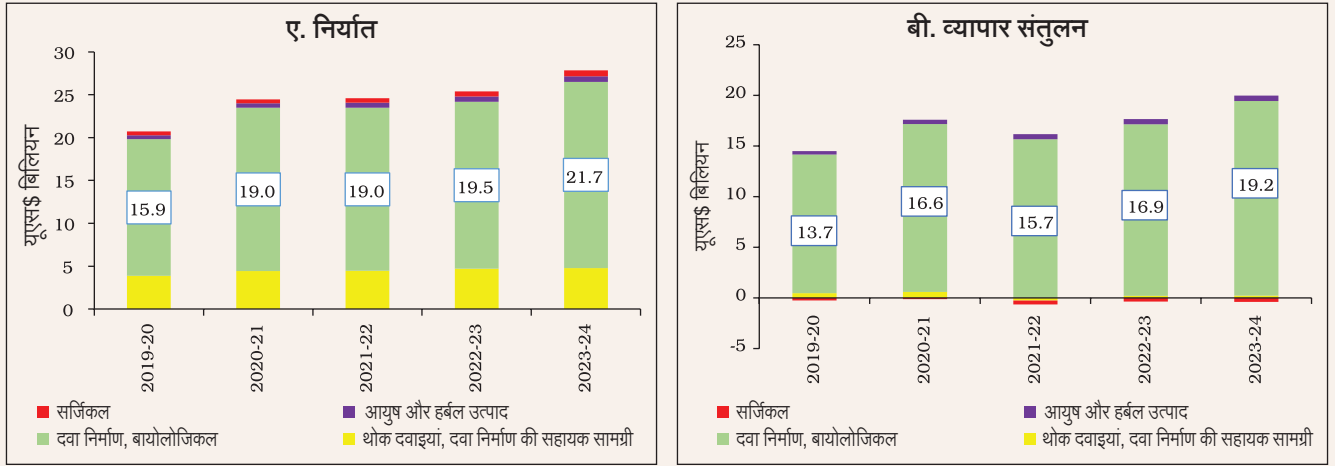
II.7.9]। स्मार्टफोन के लिए प्रमुख निर्यात बाजार अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, नीदरलैंड और इटली रहे।

चार्ट II.7.9: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात



⁵⁶ सरकार ने अप्रैल 2020 में एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना शुरू की यह पात्र कंपनियों को पांच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष पर निवल वृद्धिशील बिक्री पर 4-6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान करती है। एलएसईएम के लिए पीएलआई का दूसरा दौर मार्च 2021 में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें चार साल की अवधि के लिए 3-5 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

चार्ट II.7.10: दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

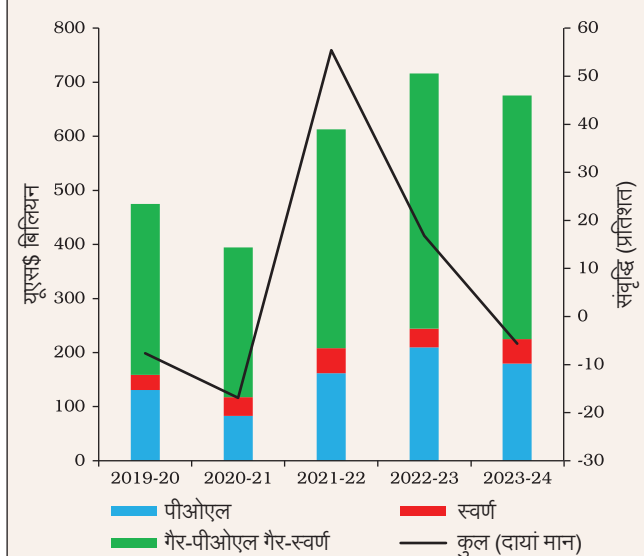
II.7.12 दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात, भारत के व्यापारिक निर्यात का 6.4 प्रतिशत है, 2023-24 में सभी उप-घटकों के उच्च शिपमेंट पर 9.7 प्रतिशत बढ़ गया, जिसमें दवा फॉर्मूलेशन, जैविक और शल्य चिकित्सा में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट II.7.10)।

II.7.13 2023-24 के दौरान 675.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य आयात में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण कम कीमतें रही (चार्ट II.7.11)। आयात में गिरावट

पीओएल, कोयला, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों, उर्वरकों और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों से प्रेरित रही। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, स्वर्ण, मशीनरी, दालों और अलौह धातुओं ने समग्र आयात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट II.7.12)।

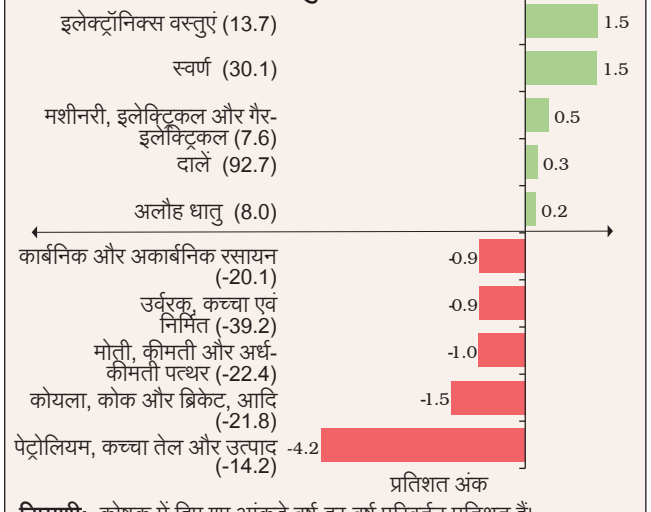
II.7.14 पीओएल आयात (कुल पण्य आयात का 26.6 प्रतिशत) 2023-24 के दौरान 14.2 प्रतिशत घटकर 179.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण कम

चार्ट II.7.11: भारत का पण्य आयात



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

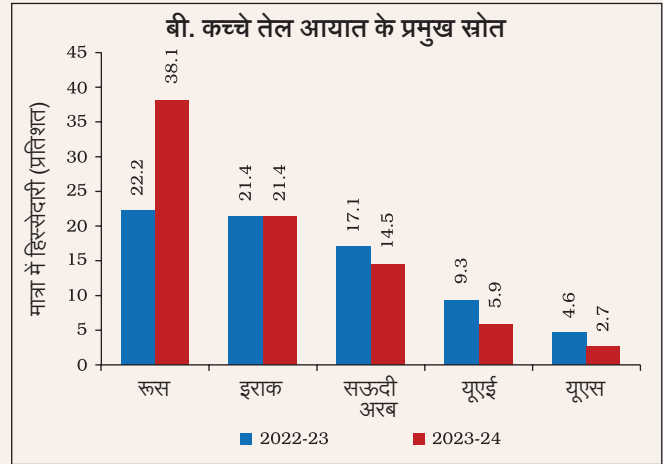
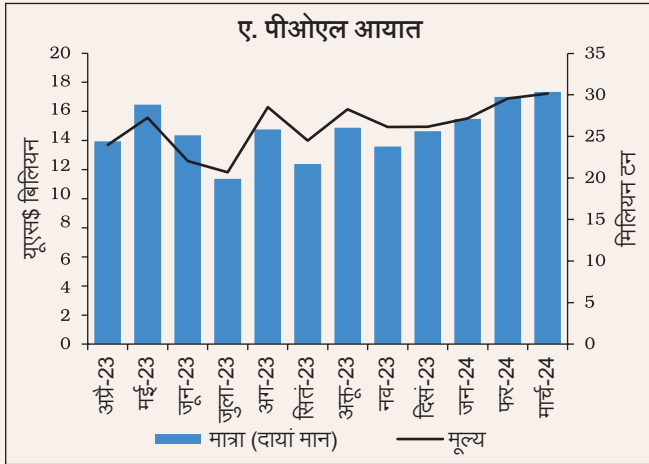
चार्ट II.7.12: आयात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2022-23 की तुलना में 2023-24)



टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत हैं।

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.7.13: पीओएल



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

कीमतें रही क्योंकि मात्रा में 0.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ (चार्ट II.7.13ए)। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रूस की हिस्सेदारी 2022-23 में 22.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान 38.1 प्रतिशत हो गई, जबकि मध्य पूर्व क्षेत्र से आपूर्ति में कमी आई (चार्ट II.7.13बी)।

II.7.15 घरेलू खपत का लगभग एक तिहाई उर्वरक आयात, कम कीमतों पर 2023-24 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 39.2 प्रतिशत घटकर 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.7.14)।

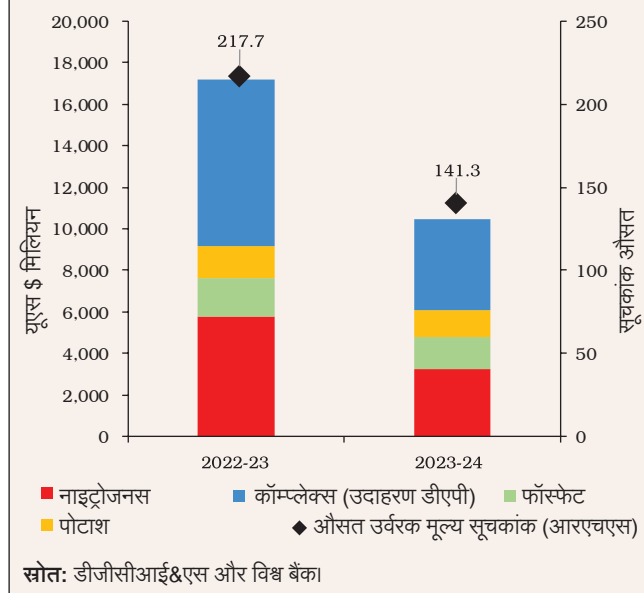
II.7.16 2023-24 के दौरान कोयला आयात 21.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) गिर कर 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, इसमें कम कीमतों से लाभ हुआ, यहां तक कि अंतर्निहित मात्रा में 11.3 प्रतिशत⁵⁷ की वृद्धि हुई (चार्ट II.7.15)।

II.7.17 2023-24 के दौरान सोने का आयात 30.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मात्रा (17.2 प्रतिशत) के साथ-साथ कीमतों (10.2 प्रतिशत) में वृद्धि पर आधारित है [चार्ट II.7.16]।

II.7.18 2023-24 के दौरान 87.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में 13.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई जो इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों, दूरसंचार उपकरणों और कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा चालित रही (चार्ट II.7.17)।

II.7.19 2023-24 के दौरान पण्य व्यापार घाटा 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) गिरकर 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तेल घाटा लगभग 40.1 प्रतिशत रहा (चार्ट II.7.18ए)।

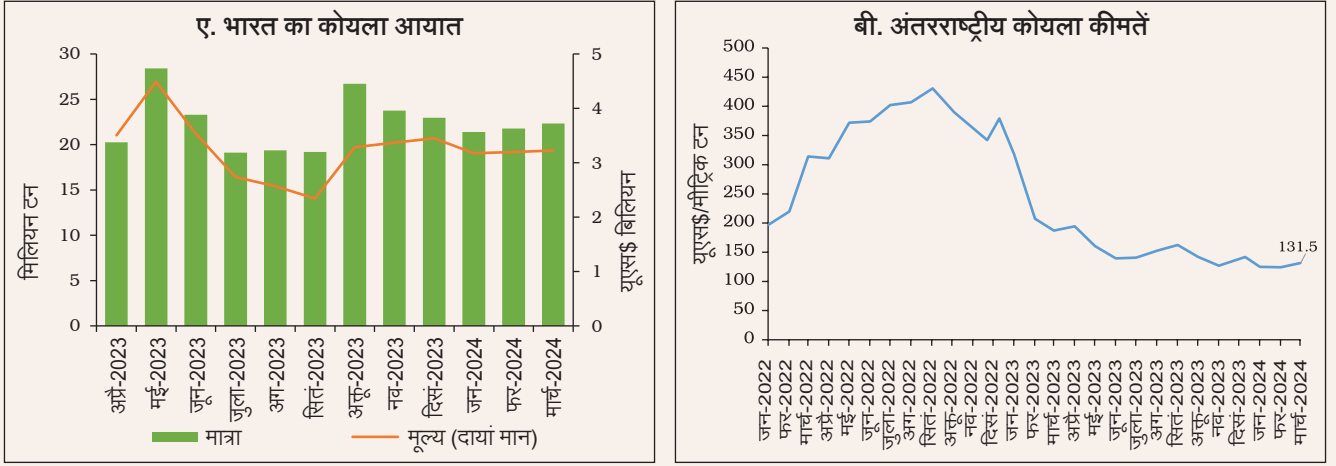
चार्ट II.7.14: भारत का उर्वरक आयात



स्रोत: डीजीसीआई&एस और विश्व बैंक।

⁵⁷ वैश्विक मांग में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत कोयले का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है [कोल 2023, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)।]

चार्ट II.7.15: कोयला आयात और कीमत



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और विश्व बैंक।

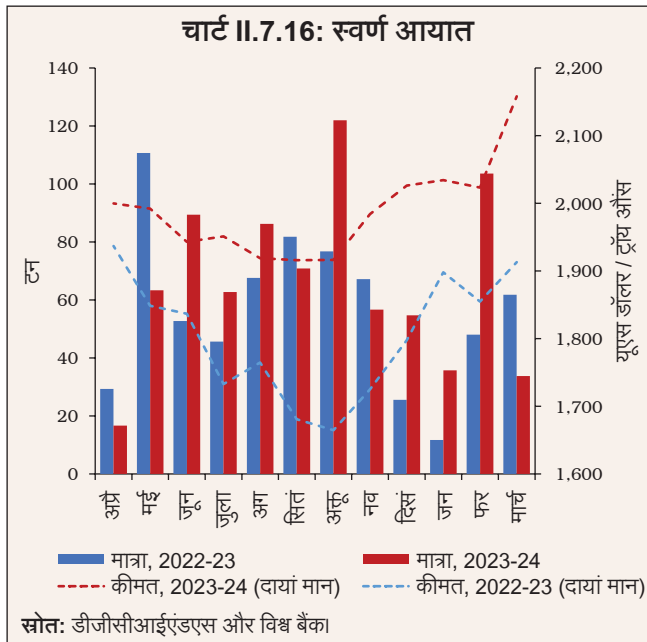
प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में, रूस, स्विट्जरलैंड और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया, जबकि अमेरिका, नीदरलैंड और यूके के संबंध में व्यापार अधिशेष में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7.18बी)।

4. अदृश्य मदें

II.7.20 अदृश्य मदों से शुद्ध प्राप्तियां - सेवाओं, आय और अंतरण में सीमा पार लेनदेन - पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24

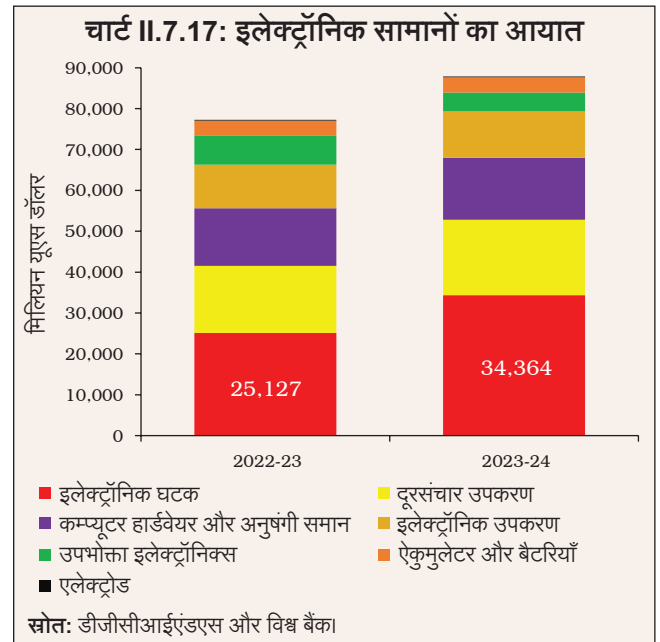
(अप्रैल-दिसंबर) के दौरान बढ़ीं। सॉफ्टवेयर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात कुल मिलाकर भारत के सेवा निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत रहा, और समान अवधि के दौरान उनमें 11.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है [चार्ट II.7.19]। अन्य सेवाओं में, यात्रा सेवाओं के निर्यात में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसे महामारी से संबंधित आवाजाही प्रतिबंधों के हटने का लाभ मिला है। परिवहन प्राप्तियों में 23.9 प्रतिशत की

चार्ट II.7.16: स्वर्ण आयात



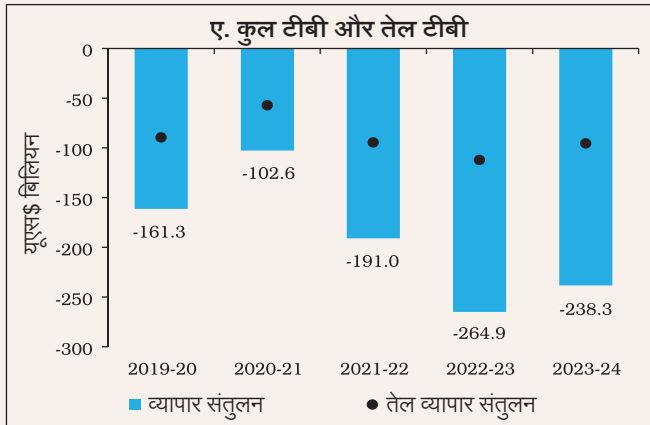
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और विश्व बैंक।

चार्ट II.7.17: इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात

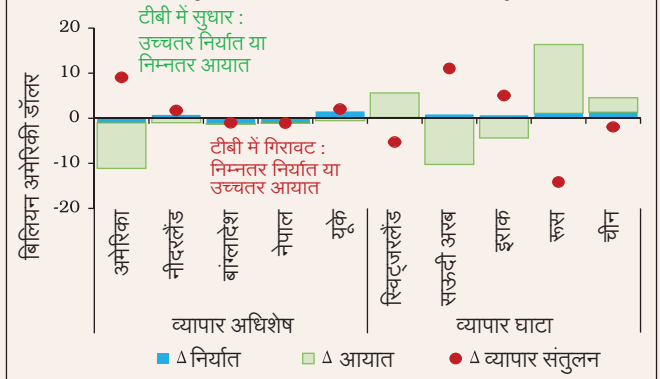


स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और विश्व बैंक।

चार्ट II.7.18 : भारत का पण्य व्यापार घाटा



बी. भारत के व्यापार संतुलन में परिवर्तन के स्रोत (2022-23 की तुलना में 2023-24)



टीबी : व्यापार संतुलन

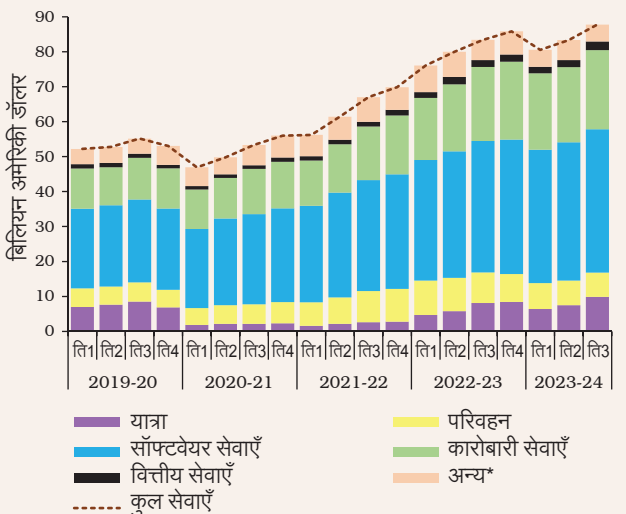
नोट : एक सकारात्मक Δ निर्यात/Δ आयात का अर्थ अधिक निर्यात / आयात है और यह विलोमतः भी सही है।

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

गिरावट आई, जो मुख्य रूप से वैश्विक माल ढुलाई दरों में नरमी के कारण हुई: अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान औसत बाल्टिक ड्राई इंडेक्स⁵⁸ पिछले वर्ष की तुलना में 19.3 प्रतिशत गिर गया। निजी हस्तांतरण प्राप्ति, मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत

भारतीयों द्वारा विप्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान इसमें 3.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई। प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उच्च ब्याज और लाभांश भुगतान को दर्शाता है।

चार्ट II.7.19 : भारत के सेवा निर्यात की संरचना



* इसमें बीमा सेवाएँ और संचार शामिल हैं, जिन्हें अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : आरबीआई।

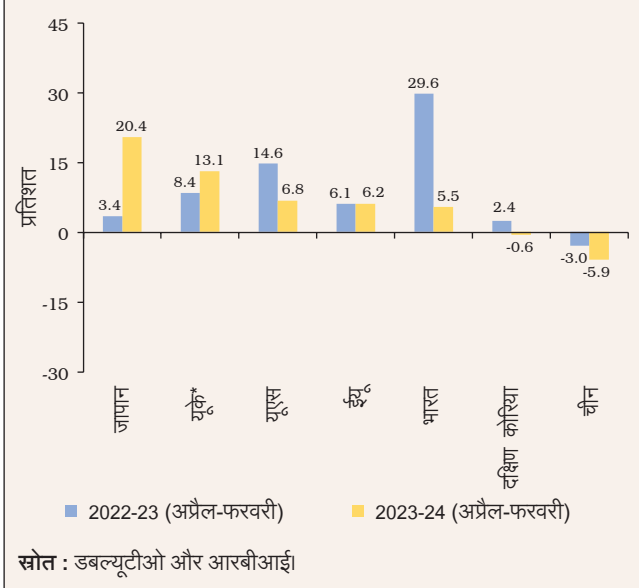
II.7.21 कमजोर वैश्विक मांग के कारण 2023-24 में सेवा निर्यात वृद्धि में गिरावट आई। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के मूल्य में वृद्धि 2023 में 9.0 प्रतिशत से कम रही जो 2022 में 15.1 प्रतिशत थी। भारत ने 2023 के दौरान शीर्ष पांच निर्यातक देशों में अपना स्थान बरकरार रखा (चार्ट II.7.20)। गार्टनर⁵⁹ के अनुसार, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) खर्च 2023 के 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 5.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात को समर्थन मिलना चाहिए।

II.7.22 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में भारत में आवक विप्रेषण 86.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है

⁵⁸ बाल्टिक एक्सचेंज (लंदन) द्वारा बनाया गया एक शिपिंग और व्यापार सूचकांक, जो कोयला, लोहा और स्टील जैसे सूखे थोक कच्चे माल के परिवहन की लागत को मापता है।

⁵⁹ गार्टनर इंक एक अमेरिकी तकनीकी अनुसंधान और परामर्श फर्म है, जो आईटी उद्योग पर अपने शोध और रिपोर्ट और दुनिया भर में आईटी खर्च पर पूर्वानुमान के लिए जानी जाती है।

चार्ट II.7.20 : सेवाओं के देश-वार निर्यात में वृद्धि



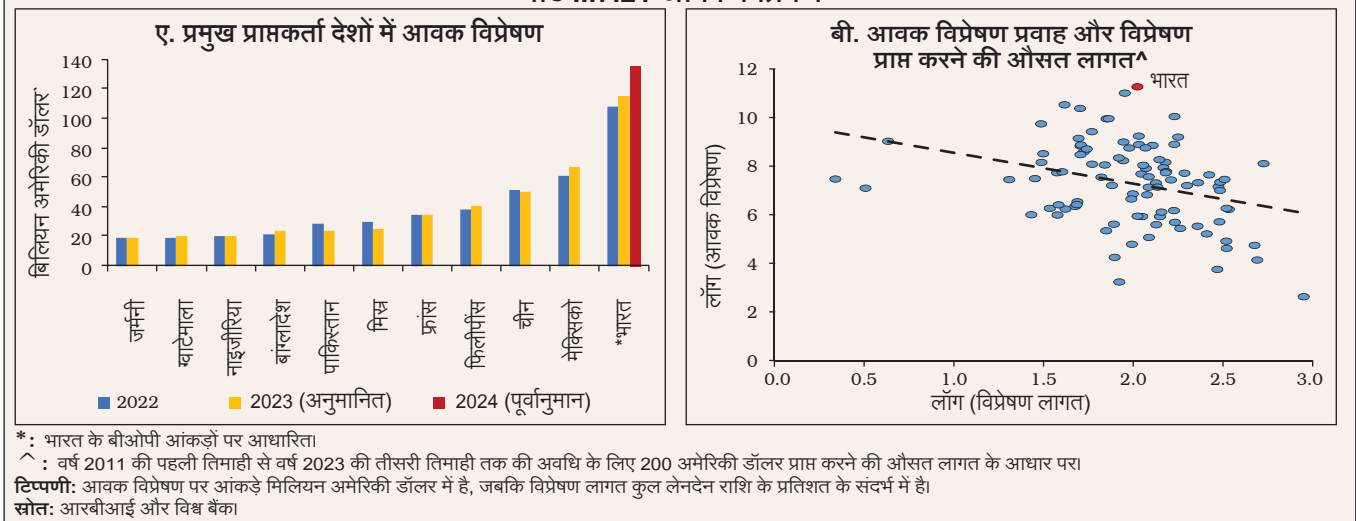
(चार्ट II.7.21ए)। विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में वैश्विक विप्रेषण में 15.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत का आवक विप्रेषण 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोप जैसी प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत श्रम बाजारों ने भारत में विप्रेषण प्रवाह का समर्थन किया है। विश्व बैंक

के अनुमान के अनुसार, भारत में 200 अमेरिकी डॉलर विप्रेषण की औसत लागत 2020 की चौथी तिमाही में 5.51 प्रतिशत (2019 की पहली तिमाही के बाद से उच्चतम) से घटकर 2023 की तीसरी तिमाही में 4.95 प्रतिशत हो गई। आम तौर पर, विप्रेषण प्राप्तियों की राशि और विप्रेषण की लागत में नकारात्मक संबंध होता है (चार्ट II.7.21बी)।

II.7.23 आय खाते⁶⁰ के तहत, 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भुगतान में बढ़ोतरी प्राप्तियों से अधिक होने के कारण घाटा बढ़ गया। विदेशों में अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के निवेश पर रिजर्व बैंक की उच्च ब्याज/छूट की कमाई बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बाहरी सहायता, अल्पकालिक क्रेडिट और अनिवासी जमाओं, तथा अनिवासी शेयरधारक (प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेशक दोनों) को लाभांश के भुगतान जैसी देनदारियों पर ब्याज के व्यय से ऑफसेट हो गई।

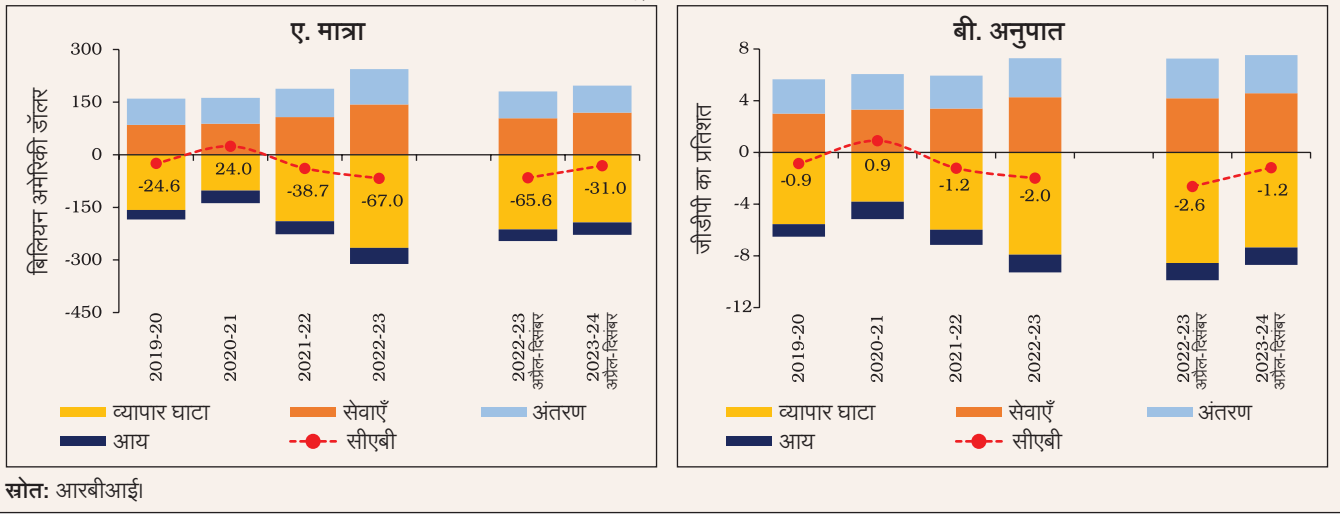
II.7.24 भारत का सीएडी 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में कम होकर 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) हो गया, जो एक साल पहले 65.6 बिलियन अमेरिकी

चार्ट II.7.21 आवक विप्रेषण



⁶⁰ सीमा पार निवेश पर आय और कर्मचारियों का मुआवजा जो घरेलू निवासी संस्थाएं शेष दुनिया से कमाती हैं/भुगतान करती हैं।

चार्ट II.7.22: भारत के चालू खाता शेष (सीएबी) की संरचना



स्रोत: आरबीआई

डॉलर (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) था (चार्ट II.7.22)। यह पण्य व्यापार घाटे में गिरावट के साथ-साथ सेवा व्यापार में उच्च अधिशेष का परिणाम था।

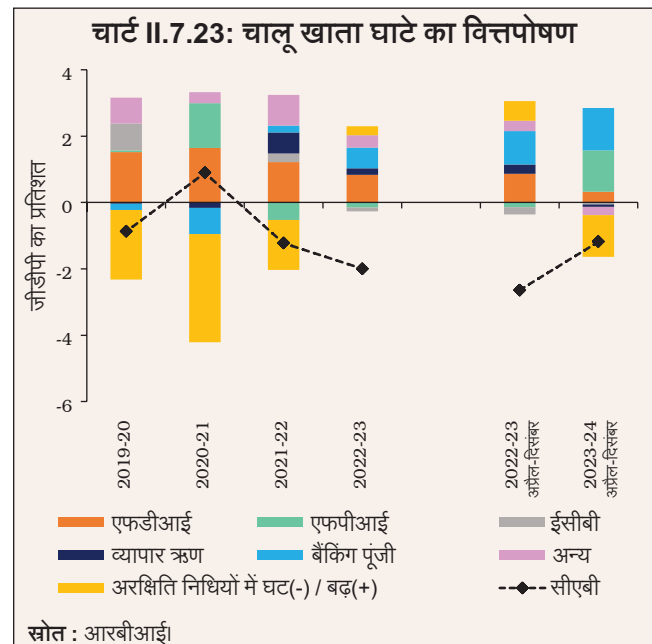
5. बाह्य वित्तपोषण

II.7.25 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, पूंजी प्रवाह मजबूत रहा, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में बदलाव से प्रेरित था। अनिवासी जमा और बाहरी वाणिज्यिक उधार के तहत निवल प्रवाह एक साल पहले की तुलना में अधिक था। हालाँकि, भारत से एफडीआई के प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह कम था। कुल मिलाकर, निवल पूंजी प्रवाह अधिक रहा, जबकि सीएडी में कमी आई, जिससे अप्रैल-दिसंबर के दौरान बीओपी आधार (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) पर विदेशी मुद्रा भंडार में 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई (चार्ट II.7.23 और परिशिष्ट सारणी 8)।

II.7.26 निवल एफडीआई (यानी, निवल आवक एफडीआई तथा निवल जावक एफडीआई का अंतर) प्रवाह 2023-24 के दौरान एक साल पहले के 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जबकि अनिवासियों द्वारा सकल प्रवाह समुत्थानशील बना रहा, भारत में एफडीआई का प्रत्यावर्तन/विनिवेश बढ़ा (सारणी II.7.2)। 2023-24 के दौरान, शीर्ष एफडीआई स्रोत देश सिंगापुर,

मॉरीशस, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान रहें, जिन्होंने 73.9 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट II.7.24)। क्षेत्र-वार, सेवा क्षेत्र (वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, व्यापार सेवाओं और संचार सेवाओं सहित) का भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में बड़ा हिस्सा रहा, इसके बाद विनिर्माण, बिजली और अन्य ऊर्जा, खुदरा और थोक व्यापार और परिवहन क्षेत्र आते हैं (परिशिष्ट सारणी 9)।

II.7.27 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2023-24 के दौरान भारत से बाहरी एफडीआई में 13.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सिंगापुर,



स्रोत: आरबीआई

सारणी II.7.2 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मर्दे	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	44.0	38.6	28.0	10.6
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	54.9	56.2	42.0	26.5
1.1.1 सकल अंतर्वाह	82.0	84.8	71.4	71.0
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	27.0	28.6	29.3	44.4
1.2 निवल जावक एफडीआई	11.0	17.6	14.0	16.0

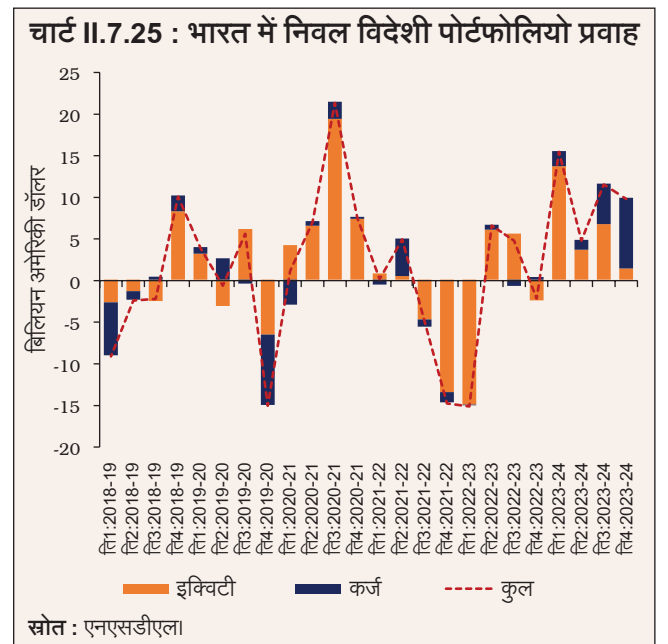
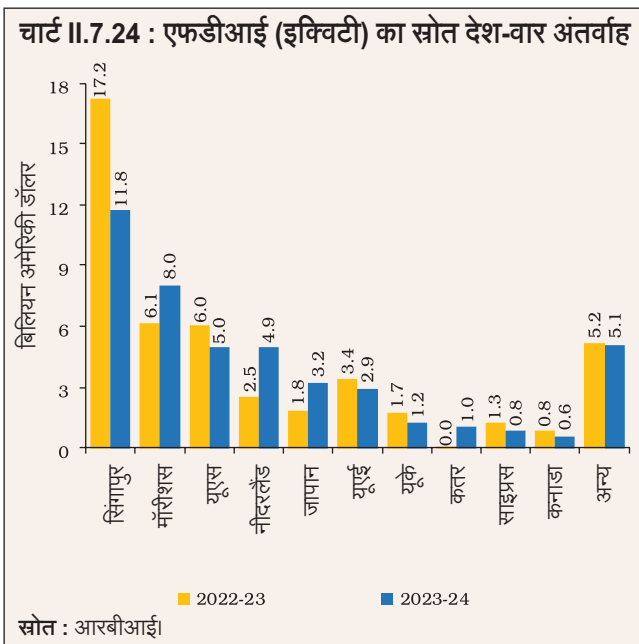
स्रोत : आरबीआई

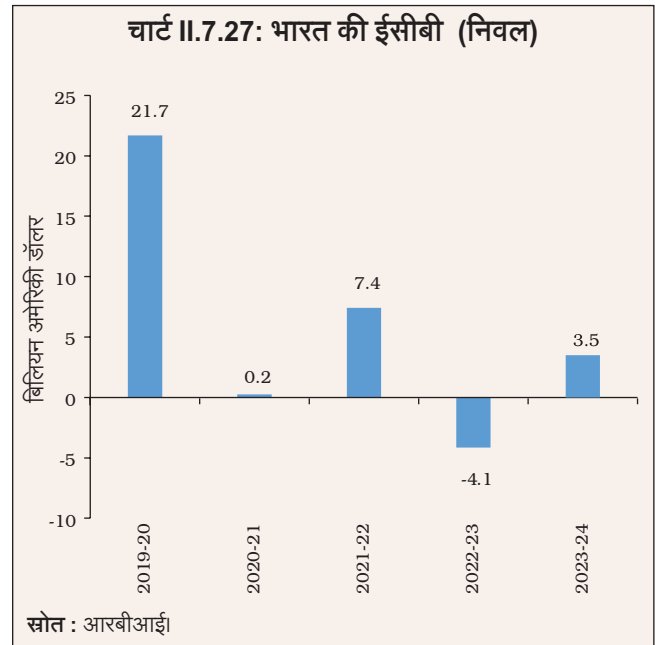
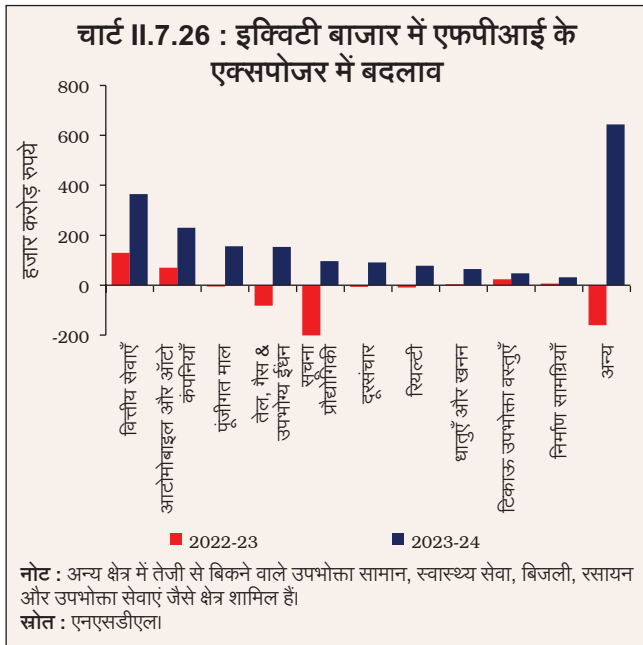
अमेरिका, यूके, यूई और नीदरलैंड प्रमुख गंतव्य देश रहे। 2023-24 के दौरान वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएँ, विनिर्माण, थोक और खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे।

II.7.28 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 2022-23 में निवल विक्रेता बने रहने के बाद 2023-24 में घरेलू बाजार में बड़े निवल खरीदार बन गए। 2023-24 के दौरान, निवल एफपीआई अंतर्वाह 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2022-23 के दौरान 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह था (चार्ट II.7.25)। मजबूत घरेलू जीडीपी वृद्धि, उज्ज्वल मध्यम अवधि

संभावनाओं और मजबूत कॉर्पोरेट आय के दम पर भारत ने 2023-24 में समकक्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक एफपीआई अंतर्वाह को आकर्षित किया।

II.7.29 इक्विटी बाजार में एफपीआई अंतर्वाह मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल, पूंजीगत सामान, तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दर्ज किया गया (चार्ट II.7.26)। वर्ष के दौरान ऋण बाजार में एफपीआई द्वारा निवेश बढ़ने के बावजूद, उपयोग उपलब्ध निवेश सीमा से कम बना हुआ है।

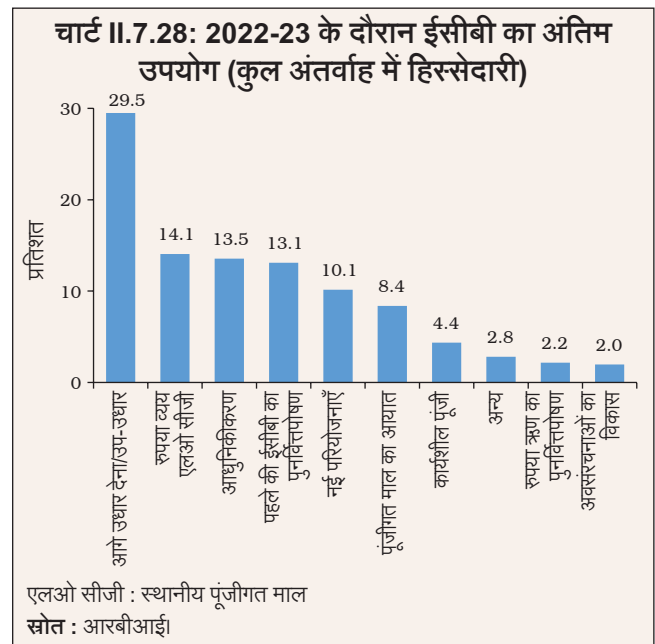




II.7.30 ईसीबी प्रवाह ने 2023-24 के दौरान 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह के साथ एक बदलाव प्रदर्शित किया, जबकि एक साल पहले 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह हुआ था (चार्ट II.7.27)।

II.7.31 ईसीबी समझौते की राशि के चार-पाँचवें भाग से अधिक का उपयोग ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग, स्थानीय पूंजीगत वस्तुओं के लिए रुपया व्यय, आधुनिकीकरण, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त और नई परियोजनाओं के लिए किया गया था (चार्ट II.7.28)। ईसीबी के भीतर, रुपये मूल्यवर्ग वाले ऋण और रुपये मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड का हिस्सा 2023-24 के दौरान कुल समझौता राशि का 5.3 प्रतिशत रहा, जबकि एक साल पहले यह 8.0 प्रतिशत था। 2023-24 के दौरान कुल समझौता राशि में से 50.8 प्रतिशत ऋण स्पष्ट रूप से हेज किए गए, 15.3 प्रतिशत ऋण एफडीआई मूल कंपनियों (आईएनआर ऋण को छोड़कर) से थे और 5.3 प्रतिशत आईएनआर में मूल्यवर्गित थे। शेष 28.6 प्रतिशत में अन्य ईसीबी शामिल हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से हेज्ड ऋण (यानी, विदेशी मुद्रा में उधारकर्ताओं की व्यावसायिक आय) शामिल हैं।

II.7.32 पण्य आयात में संकुचन के अनुरूप 2023-24 के दौरान अल्पकालिक व्यापार ऋण में गिरावट आई, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ, जबकि एक साल पहले 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह हुआ था। व्यापार ऋण का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल, सोना, कोयला और तांबे के आयात के लिए उठाया गया था।



सारणी II.7.3 : अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	8.8	3.3	2.5	4.2
2. अनिवासी साधारण खाता	2.3	3.5	4.0	4.2
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	-3.8	-3.6	2.4	6.4
अनिवासी जमा राशियाँ (1+2+3)	7.4	3.2	9.0	14.7

स्रोत : आरबीआई

II.7.33 अनिवासी जमा के तहत निवल अंतर्वाह 2023-24 के दौरान बढ़कर 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, सभी तीन योजनाओं के तहत अभिवृद्धि के साथ - अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा; अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाते; और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमा (सारणी II.7.3)।

6. भेद्यता संकेतक

II.7.34 दिसंबर 2023 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2023 के अंत के स्तर से 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, इसमें गिरावट आई और यह उभरते बाज़ार प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे कम रहा (सारणी II.7.4)।

II.7.35 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 के दौरान बढ़ा, जिससे बाहरी जोखिमों और स्पिलओवर को कम करने के लिए

सारणी II.7.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित न किया गया हो)

संकेतक	2013	2022	2023	दिसंबर अंत में 2023
1	2	3	4	5
1. जीडीपी में बाहरी कर्ज का अनुपात	22.4	20.0	19.0	18.7
2. कुल कर्ज में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	19.7	20.6	19.5
3. कुल कर्ज में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	43.2	44.0	43.9
4. कुल कर्ज में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	8.3	8.2	7.7
5. कुल कर्ज में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	98.1	92.7	96.0
6. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	20.0	22.2	20.3
7. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	44.0	47.4	45.7
8. आयात का रिज़र्व कवर (महीनों में)*	7.0	11.8	9.6	11.0 (11.4)
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्राप्ति की तुलना में)	5.9	5.2	5.3	6.5
10. बाह्य कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	619.0	624.3	648.2
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-326.7	-358.2	-367.5	-370.3
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-11.6	-11.3	-10.8
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	-1.2	-2.0	-1.2

*: बीओपी आंकड़ों में प्रकाशित नवीनतम चार तिमाहियों के पण्य आयातों पर आधारित।

#: कॉलम 5 में सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2023 से संबंधित है।

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े मार्च 2024 के अंत से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई और भारत सरकार।

बफर मजबूत हुए। मार्च 2024 के अंत में उन्हें 646.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रखा गया, जिसमें मार्च 2023 के अंत में 68.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2023 के अंत में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मूल परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक विदेशी ऋण से पांच गुना अधिक और अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक विदेशी ऋण का दो गुना से अधिक रहा। मार्च 2024 के अंत में, विदेशी मुद्रा भंडार ने 2023-24 के लिए 11.4 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

7. निष्कर्ष

II.7.36 भारत का बाह्य क्षेत्र 2023-24 के दौरान मजबूत हुआ। चालू खाते का घाटा कम हुआ, धारणीय बना रहा और अच्छी तरह से वित्तपोषित रहा। पूंजी प्रवाह में सुधार हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिली। तदनुसार, प्रतिकूल वैश्विक समष्टि-वित्तीय आघातों के प्रसार को झेलने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि हुई, जिसने समग्र व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान दिया।